राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 8 अंक 45

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, बुधवार, 24 जुलाई, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 16

❝ यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान करेगा एवं उसे सशक्त बनाएगा और सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस बजट का बड़ा फोकस देश के किसान हैं। यह बजट किसानों को समृद्धि के मार्ग पर लेकर जाएगा। –नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जागरण सरोकार और आम बजट 2024-25

सुशिक्षित समाज

- शिक्षा, रोजगार व कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रविधान
- 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा
- उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा
- पांच वर्ष में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है

स्वस्थ समाज

- स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान 80,517.62 करोड़ से 12.96% अधिक है
- कैंसर के इलाज से जुड़ीं तीन जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क हटाया गया। पहले इन पर 10 प्रतिशत का शुल्क था। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी

जनसंख्या नियोजन

- 4.1 करोड़ युवाओं को पांच साल में दो लाख करोड़ के आवंटन से मिलेगा रोजगार
- मुद्रा योजना के तहत लोन लेने की सीमा को 20 लाख किया, इससे रोजगार का सृजन होगा
- शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा

नारी सशक्तीकरण

- महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक का आवंटन
- कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास स्थापित करने की भी घोषणा
- बजट में महिला विशेष कौशल कार्यक्रमों की शुरुआत की रूपरेखा तैयार की गई

गरीबी उन्मूलन

- पीएम गरीब कल्याण योजना पांच साल के लिए बढ़ी
- शहरों में प्रभावशाली और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट तैयार की जाएगी। इससे किराये के लिए घरों की उपलब्धता बढ़ेगी
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी माडल से छात्रावास जैसी सुविधा की व्यवस्था की जाएगी

पर्यावरण संरक्षण

- कापर, लिथियम जैसे दुर्लभ खनिजों का उत्पादन बढ़ाने, उनकी रिसाइक्लिंग करने और विदेश में ऐसे खनिजों के अधिग्रहण के लिए मिशन की शुरुआत होगी
- परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों की साझेदारी से भारत स्माल रिएक्टर स्थापित किए जा जाएंगे

जल संरक्षण

- जल स्रोत, नदियों के विकास, गंगा की सफाई के लिए 30,233.83 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है
- पिछले वर्ष 19,516.92 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था
- बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन किया गया है

समृद्धि का पथ

नीतिगत निरंतरता, सुधार का संकल्प और नए अवसरों का सृजन..इन सूत्रों के साथ मोदी सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की स्वाभाविक अपेक्षाओं के साथ ही हुई। आम बजट 2024-25 अगले पांच साल के भावी पथ की झलक देने के साथ वर्तमान चुनौतियों से निपटने की राह भी दिखाता है। किसी बड़ी, आकर्षक और चर्चा का विषय बनने वाली घोषणा के बिना बजट ने आर्थिक प्रगति और खुशहाली के नौ आधार भी बताए और उन पर चलने की राह भी। नई पीढ़ी के लिए नए अवसर तैयार करने के साथ ही कृषि और किसानों के कल्याण की प्रतिबद्धता और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के निर्माण के कदम एक सशक्त, समर्थ, समृद्ध और संभावनाओं वाले भारत का आधार तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह बजट राष्ट्र सर्वोपरि की धारणा को मजबूत करने के साथ ही देश के उन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने का भरोसा दिलाता है, जो प्रगति में पीछे रहे हैं और लंबे समय से सहारे-समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

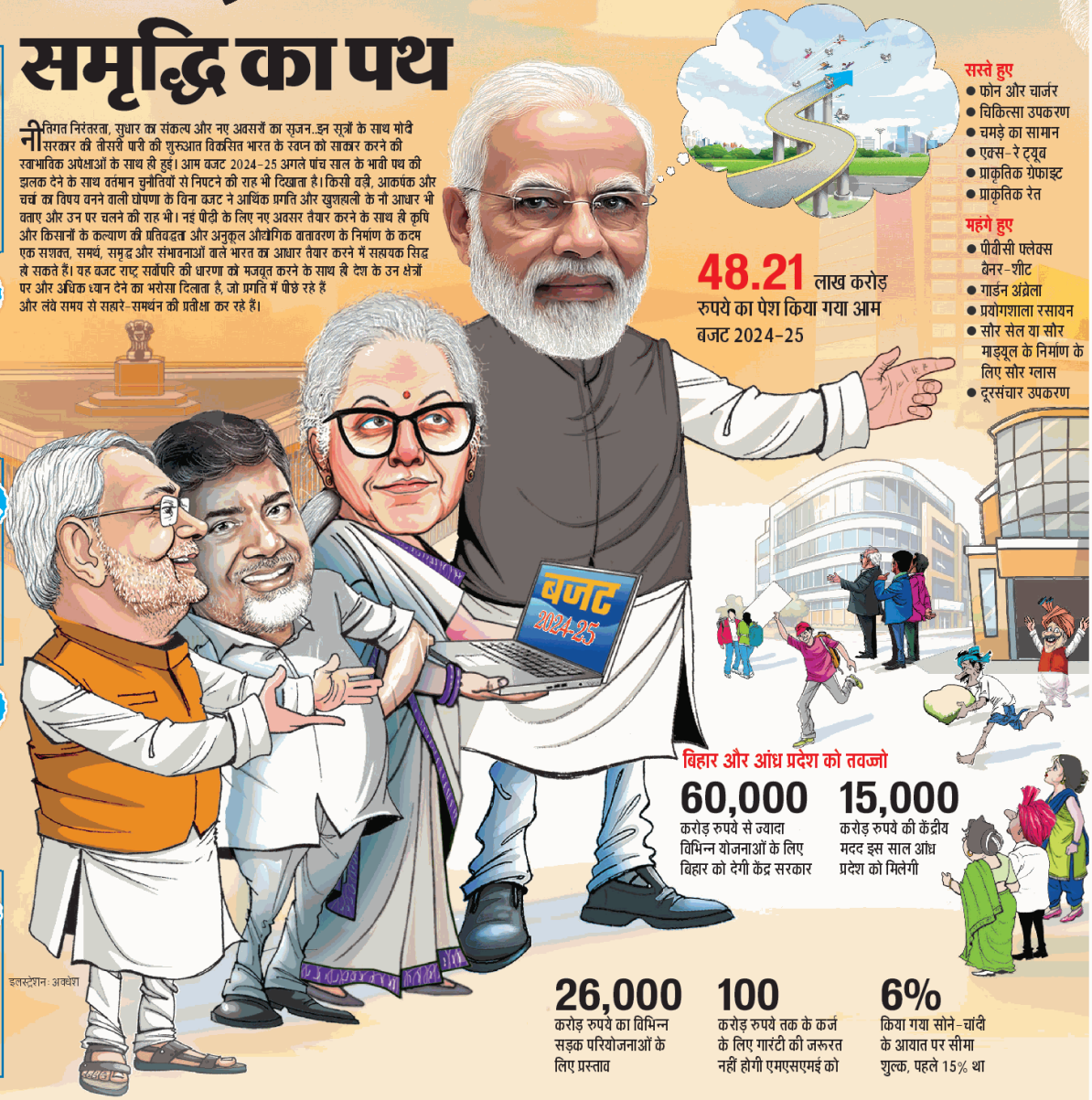

इलस्ट्रेशन: अवधेश

सस्ते हुए

- फोन और चार्जर
- चिकित्सा उपकरण
- चमड़े का सामान
- एक्स-रे ट्यूब
- प्राकृतिक ग्रेफाइट
- प्राकृतिक रेत

महंगे हुए

- पीवीसी फ्लेक्स बैनर-शीट
- गार्डन अंब्रेला
- प्रयोगशाला रसायन
- सौर सेल या सौर माड्यूल के निर्माण के लिए सौर ग्लास
- दूरसंचार उपकरण

48.21 लाख करोड़ रुपये का पेश किया गया आम बजट 2024-25

बिहार और आंध्र प्रदेश को तवज्जो

60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार को देगी केंद्र सरकार

15,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद इस साल आंध्र प्रदेश को मिलेगी

26,000 करोड़ रुपये का विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव

100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी एमएसएमई को

6% किया गया सोने-चांदी के आयात पर सीमा शुल्क, पहले 15% था

विकास को नई ऊंचाई, समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा बजट : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए 2024-25 के बजट को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला महत्वपूर्ण बजट करार दिया और कहा कि यह समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है।

प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद कहा कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा और विकसित भारत की नींव भी रखेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ युवाओं, पिछड़े वर्गों, महिलाओं एवं मध्यम वर्ग पर फोकस की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना से करोड़ों नए रोजगार सृजित होंगे। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान करेगा एवं उसे सशक्त बनाएगा और सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।' उन्होंने कहा कि युवाओं की पहली नौकरी की पहली सैलरी अब सरकार देगी। साथ ही कहा, 'कौशल विकास और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड़ नौजवानों को प्रोत्साहन की योजनाएं, इससे गांव के गरीब युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव में घर-घर उद्यमी बनाना है। हम सब मिलकर भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाएंगे।' बिना गारंटी मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने पर मोदी ने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और वंचितों को काफी लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट छोटे व्यापारियों व एमएसएमई के लिए प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट में

- **मध्यम वर्ग को सशक्त बनाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है यह बजट**
- **देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्प्रेरक का करेगा काम**

मैन्युफैक्चरिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इससे नया मध्यम वर्ग बना है, यह उनके सशक्तीकरण की निरंतरता का भी बजट है। युवा पीढ़ी के लिए अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा यह बजट पहले की तुलना में मध्यम वर्ग को अधिक सशक्त बनाएगा। यह शिक्षा एवं कौशल विकास को एक नया आयाम प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में आदिवासी समाज, दलितों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत योजनाएं पेश की गई हैं। यह बजट महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'बजट का एक बड़ा फोकस किसान हैं। खाद्यान्न भंडारण की दुनिया की सबसे बड़ी योजना शुरू करने के बाद सरकार ने अब सब्जी उत्पादन क्लस्टर्स शुरू किए हैं जिनसे किसानों और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना भारत के लिए समय की जरूरत है। इसलिए दालों एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करने के लिए उपायों की घोषणा की गई है। यह बजट किसानों को समृद्धि के मार्ग पर लेकर जाएगा।' उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राजग सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को कर से राहत मिले। टैक्स स्लैब में संशोधन और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

मोदी ने कहा कि बजट के 'पूर्वोदय' विजन से देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। राजमार्गों, जल परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति दी जाएगी। उन्होंने गरीबों के लिए तीन करोड़ घरों और जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पर प्रकाश डाला। कहा कि बजट भारत के स्टार्ट-अप और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए कई अवसर लेकर आया है। उन्होंने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने और एंजल टैक्स खत्म करने के फैसले का भी जिक्र किया। कहा कि बजट में भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रविधान हैं। वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को इस बजट के लिए बधाई देते हुए मोदी ने कहा, 'यह बजट देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है।'

नई कर प्रणाली में राहत

आय	कर
मौजूदा स्वरूप	
0-3 लाख रुपये तक	0%
3-6 लाख रुपये तक	5%
6-9 लाख रुपये तक	10%
9-12 लाख रुपये तक	15%
12-15 लाख रुपये तक	20%
15 लाख रुपये से ज्यादा	30%
नया स्वरूप	
0-3 लाख रुपये तक	0%
3-7 लाख रुपये तक	5%
7-10 लाख रुपये तक	10%
10-12 लाख रुपये तक	15%
12-15 लाख रुपये तक	20%
15 लाख रुपये से ज्यादा	30%

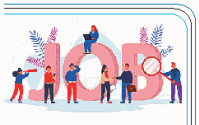

अंदर के पन्नों पर

समृद्ध युवा

लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने इस बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की हैं। दो लाख करोड़ रुपये के रोजगार व कौशल प्रशिक्षण पैकेज से युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रविधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। 2

समृद्ध किसान

बजट में किसान और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,77,566.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 32 फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी। अगले दो वर्षों के दौरान एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 3

समृद्ध शहर

शहरों को विकास का इंजन होना चाहिए, इस सोच के साथ 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों का विकास किया जाएगा। अंतरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च का एलान किया गया था, जिसे मंगलवार को प्रस्तुत किए गए बजट में भी कायम रखा गया। इसके लिए राज्यों को 1.50 लाख करोड़ रुपये बिना ब्याज के देने की घोषणा की गई है। 4

समृद्ध उद्योग

मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन के लिए देश के 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के लोन की गारंटी होगी। 5

समृद्ध खजाना

हर महीने 1.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी संग्रह, सरकारी कंपनियों से मिलने वाले लाभांश में भारी वृद्धि का असर सरकारी खजाने पर साफ दिख रहा है। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को 4.9 प्रतिशत पर सीमित करने की बात कही है और अगले वित्त वर्ष 2025-26 में घाटे को 4.5 प्रतिशत पर लाने का विश्वास जताया है। इसके साथ कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क हटाया गया है। 6

समृद्ध सोच

आम बजट में बड़े सुधारों की तरफ बढ़ने की सरकार की मंशा तो दिखती है, लेकिन इसका तरीका बदला नजर आता है। वह भूमि जैसे अटके सुधारों को लेकर अब केंद्र के स्तर पर कम और राज्यों की तरफ से अधिक कदम उठाने को प्रोत्साहित करना चाहती है। सरकार ने परोक्ष तौर पर यह भी संकेत दे दिया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंशा नहीं है। 7

राजनीति

बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पर विशेष ध्यान सटीक राजनीति को प्रदर्शित करती है। आंध्र में सत्तारूढ़ तेदेपा राजग की सबसे बड़ी साझेदार है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जदयू है जो बिहार में सरकार चला रही है। ऐसे में दोनों राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। पूर्वोदय योजना के जरिये केंद्र सरकार की नजर अन्य राज्यों में राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की भी है। 8

****

डाटा शक्ति

देश कैसे बदल रहा है और आने वाले समय में देश में किस तरह के बदलाव आएंगे, जानिए आंकड़ों की जुबानी।

नौ आधार करेंगे बेड़ा पार

भारत के पास एक बड़ी युवा आबादी है। उपजाऊ जमीन है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हमारे पास ऐसे सभी जरूरी संसाधन हैं, जिनकी मदद से हम 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने बजट में ऐसे 9 क्षेत्रों की पहचान की है, जो आने वाले समय में भारत को विकासशील से विकसित देश की कतार में खड़ा करेंगे।

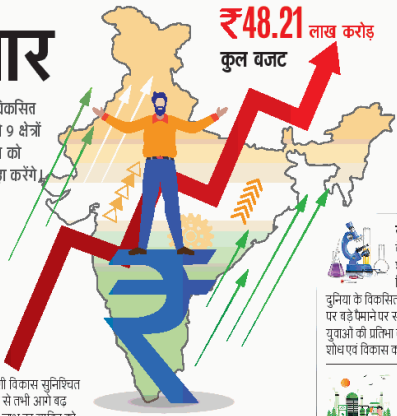

कृषि क्षेत्र : सदी के छठें दशक में भारत में अनाज की किल्लत हुआ करती थी। हमें अपनी जरूरतों के लिए अनाज आयात करना पड़ता था। आज का भारत न सिर्फ अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की अनाज की जरूरतें भी पूरी कर रहा है। इस लिहाज से भारत के कृषि क्षेत्र ने शानदार सफलता दर्ज की है। हालांकि हम अभी कृषि क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का पूरी तरह से दोहन नहीं कर पाए हैं। आने वाले दिनों में नीतिगत बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिससे कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा।

45.0% भारतीय काम कर रहे हैं मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में

18.1% योगदान कर रहा है देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र

कौशल विकास : भारत के पास युवाओं की एक बड़ी आबादी है। ये युवा शिक्षित भी हैं। लेकिन बहुत से युवाओं के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से स्किल नहीं है। हर दो स्नातकों में से एक के पास नौकरी के लिए जरूरी स्किल नहीं है। आने वाले समय में युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा।

51.5% युवाओं के पास नौकरी के लिए जरूरी स्किल नहीं है।

60.0% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है भारत में

मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

आने वाले समय में केंद्र सरकार मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर फोकस करेगी। इसके तहत उन लोगों की शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिनको अभी तक विकास का फायदा नहीं मिल पाया है। सरकार देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करना चाहती है। देश तेजी से तभी आगे बढ़ सकता है, जब विकास का लाभ हर व्यक्ति को मिले। इसके तहत सरकार आदिवासी समुदाय को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विशेष प्रयास करेगी।

मैन्यूफैक्चरिंग एवं सेवाएं : एमएसएमई सेक्टर की मजबूती आने वाले वर्षों में भारत की ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए राज्य और स्थानीय स्तर पर नियमों को कम किया जाएगा। एमएसएमई अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी, पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलाजी और लंबित श्रम सुधार एमएसएमई सेक्टर की प्रमुख चुनौतियां हैं।

45.0% योगदान है एमएसएमई का मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में

50.0% हिस्सेदारी है जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर की

इन्फ्रास्ट्रक्चर : आर्थिक विकास की गति बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकारी निवेश के साथ निजी क्षेत्र का निवेश भी जरूरी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ने से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उनकी आय बढ़ती है। भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। केंद्र सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन खर्च कर रही है। आने वाले वर्षों में खर्च और बढ़ाया जाएगा।

शहरी विकास : रोजगार और शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार शहरों को ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले केंद्र के तौर पर विकसित करेगी। इसके अलावा शहरों में आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिहाज से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

नवाचार, शोध एवं विकास : केंद्र सरकार देश में नवाचार और शोध एवं विकास को बढ़ावा के लिए वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराएगी। दुनिया के विकसित देश नवाचार और शोध एवं विकास पर बड़े पैमाने पर संसाधन खर्च कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं की प्रतिभा का दोहन करने के लिए नवाचार और शोध एवं विकास का मजबूत इकोसिस्टम जरूरी है।

ऊर्जा सुरक्षा : भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 33-35 प्रतिशत तक घटाने और स्वच्छ ऊर्जा आधारित बिजली की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का वादा किया है। केंद्र सरकार इसके लिए सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा सहित स्वच्छ ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर जोर देगी।

आर्थिक सुधार : 1990 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद देश में कई आर्थिक सुधार किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि सुधार और श्रम सुधारों को लागू करना समय की जरूरत है।

बजट के बाजीगर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना सातवां बजट पेश किया है। बजट में सरकार विकास का रोडमैप पेश करती है। इससे सरकार की प्राथमिकताओं का भी पता चलता है। आइये जानते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट तैयार करने वाले अधिकारियों के बारे में।

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट सहित लगातार सात बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनमिक्स की पढ़ाई की है। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार में 2014-19 के बीच वाणिज्य और रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। वे कर्नाटक से राज्य सभा की सदस्य हैं।

अजय सेठ, सचिव, आर्थिक मामले विभाग

कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आइएएस अधिकारी अजय सेठ आर्थिक मामले विभाग के सचिव हैं। उन्होंने मंत्रालयों की मांग को लेकर समन्वय और बजट दस्तावेज का मसौदा तैयार करने सहित बजट को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। सेठ को भारत का पहला सावरेन ग्रीन बांड जारी करने का श्रेय दिया जाता है।

टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव

टीवी सोमनाथन वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बजट से जुड़े विचार विमर्श के लिए अहम कड़ी हैं। वे 2019 में वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव बने थे और 2021 में उनको वित्त सचिव बनाया गया। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आइएएस अधिकारी हैं।

संजय मल्होत्रा, सचिव, राजस्व विभाग

राजस्थान कैडर के 1990 बैच के अधिकारी संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव हैं। बजट प्रक्रिया में मल्होत्रा कर राजस्व बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संजय मल्होत्रा जीएसटी काउंसिल की बैठकों में राज्य और केंद्र के हितों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए भी काम करते हैं।

तुहिन कांत पांडे, सचिव, दिपम

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे के पास विनिवेश के लक्ष्य को अंतिम रूप देने और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लाभांश के जरिये संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी है। तुहिन कांत पांडे ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। उनकी देखरेख में एयर इंडिया का सौदा हुआ था

विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग

विवेक जोशी वित्त मंत्री की बजट टीम में नए सदस्य हैं। वे नवंबर 2022 को वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव के तौर पर वित्त मंत्रालय में आए थे। विवेक जोशी हरियाणा कैडर के 1989 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त रह चुके हैं।

वी अनंत नागेशवरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार

वी अनंत नागेशवरन मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीइए) हैं। सीइए अर्थशास्त्रियों की टीम के साथ आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। आम तौर पर विश्लेषक आर्थिक सर्वेक्षण से ही अनुमान लगाते हैं कि बजट की दिशा क्या होगी। 2022 में सीईए का प्रभार संभालने वाले नागेशवरन ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से एमबीए किया है और इसेनबर्ग स्कूल आफ मैनेजमेंट से पीएचडी की डिग्री हासिल की है।

बाजार के बोल

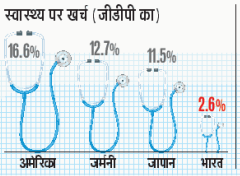

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते ही सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि बाद में बाजार संभल गया। आइये जानते हैं बीते वर्षों में बजट के दिन बाजार की प्रतिक्रिया कैसी रही है।

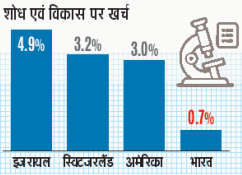

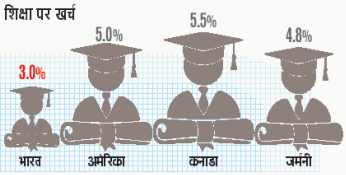

8 बार गिरावट दर्ज की है शेयर बाजार ने पिछले 10 वर्ष में बजट के दिन

106 अंक की गिरावट दर्ज की थी सेंसेक्स ने 2024 के अंतरिम बजट के दिन

4.7% की बढ़त के साथ बंद हुआ था निफ्टी 2021 का बजट पेश होने के बाद

वर्ष	वित्तमंत्री	सेंसेक्स में बदलाव**
2014	अरुण जेटली	↓ 0.3 (-72)
2015		↑ 0.5 (142)
2016		↑ 0.6 (152)
2017		↑ 1.7 (486)
2018		↓ 0.16 (-58)
2019*	पीयूष गोयल	↑ 0.59 (212)
2019	निर्मला सीतारमण	↓ -0.99 (-395)
2020		↓ -2.43 (-988)
2021		↑ 5 (2315)
2022		↑ 1.46 (848)
2023		↑ 0.27 (158)
2024*		↓ -0.15 (-106)
2024		↓ -0.09 (-73)

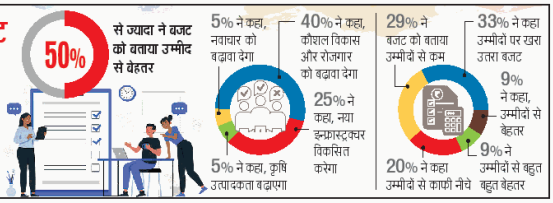

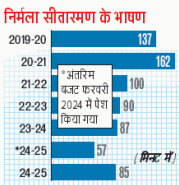

* अंतरिम बजट **प्रतिशत (प्वाइंट)

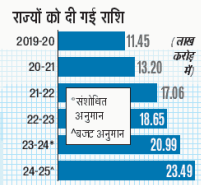

4.0% की रेंज में निफ्टी में उतार चढ़ाव रहा है बजट के दिन पिछले वर्षों के दौरान

₹7,300 करोड़ आवंटित किए गए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए

₹21,336 करोड़ का आवंटन मेट्रो परियोजना के लिए। 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य।

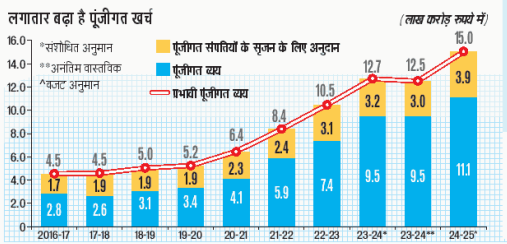

₹8,000 करोड़ आवंटित किए गए अमृत मिशन पर। 2015 में शुरू किया गया था मिशन

₹86,000 करोड़ की धनराशि मिली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए

₹60,000 करोड़ आवंटित किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए

बजट एक नजर में

विषय	2022-23 वास्तविक	2023-24 अनुमान	2023-24 सं. अनुमान	2024-25 बजट अनुमान
1. राजस्व प्राप्तियां	23,83,206	26,32,281	27,28,412	31,29,200
2. कर राजस्व	20,97,786	23,30,631	23,26,524	25,83,499
3. करभिन्न राजस्व	2,85,421	3,01,650	4,01,888	5,45,701
4. पूंजी प्राप्तियां	18,09,951	18,70,816	17,14,130	16,91,312
5. ऋणों की वसूली	26,161	23,000	27,338	28,000
6. अन्य प्राप्तियां	46,035	61,000	33,122	50,000
7. उधार और अन्य देयताएं	17,37,755	17,86,816	16,53,670	16,13,312
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	41,93,157	45,03,097	44,42,542	48,20,512
9. कुल व्यय (10+13)	41,93,157	45,03,097	44,42,542	48,20,512
10. राजस्व खाते पर	34,53,132	35,02,136	34,94,036	37,09,401
11. ब्याज भुगतान	9,28,517	10,79,971	10,63,871	11,62,940
12. पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	3,06,264	3,69,988	3,03,787	3,90,778
13. पूंजी खाते पर	7,40,025	10,00,961	9,48,506	11,11,111
14. राजस्व घाटा (10-1)	10,69,926	8,69,855	7,65,624	5,80,201
15. प्रभावी राजस्व घाटा (14-12)	7,63,662	4,99,867	4,61,837	1,89,423
16. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)]	17,37,755	17,86,816	16,53,670	16,13,312
17. प्राथमिक घाटा (16-11)	8,09,238	7,06,845	5,89,799	4,50,372

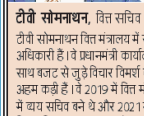

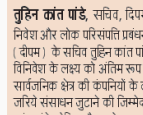

(सभी राशि करोड़ रुपये में हैं)

विकसित देशों के मुकावले भारत का खर्च

स्वास्थ्य पर खर्च (जीडीपी का)

शोध एवं विकास पर खर्च

शिक्षा पर खर्च

नौ वर्षों में दोगुने से अधिक हो गया सर्विस सेक्टर का निर्यात

158 वित्त वर्ष 2014-15

341 वित्त वर्ष 2023-24

(अरब डालर में)

उम्मीदों से बेहतर बजट

केंद्रीय बजट 2024 में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है जिसे जनता का भी साथ मिलता दिख रहा है। लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 50 प्रतिशत से ज्यादा भारतीयों ने इस बजट को उम्मीद से बेहतर बताया है। पेश किए गए नवीनतम बजट पर जनता का मूड को जानने के लिए भारत के 227 जिलों में यह सर्वेक्षण किया गया।

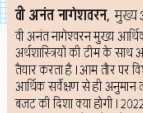

50% से ज्यादा ने बजट को बताया उम्मीद से बेहतर

निर्मला सीतारमण के भाषण

4.3% है भारत के सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी विश्व के कुल सर्विस सेक्टर के निर्यात में

राज्यों को दी गई राशि

13,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट आफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनोटेक्नोलाजी में

1 लाख से अधिक पेटेंट दिए गए हैं वित्त वर्ष 24 तक

5,978 पेटेंट दिए गए थे वित्त वर्ष 15 तक

लगातार बढ़ा है पूंजीगत खर्च

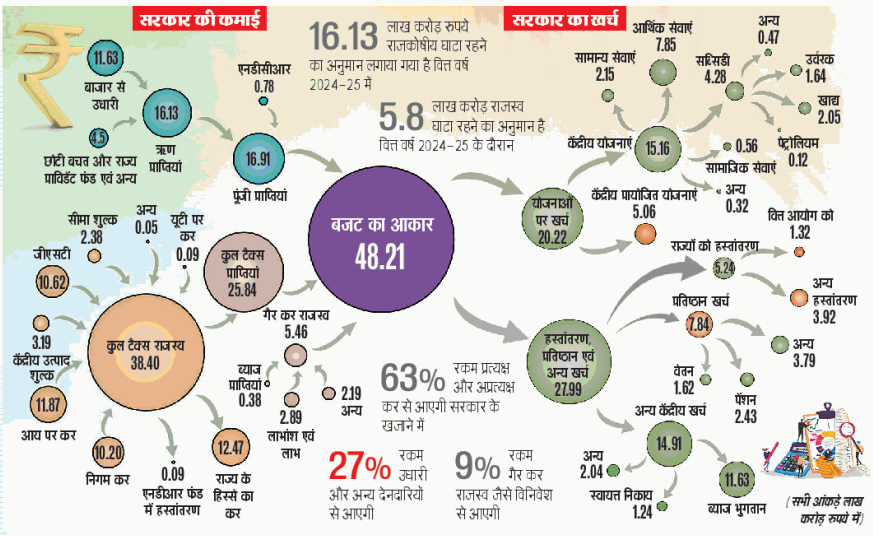

****

राष्ट्रीय संस्करण

विभाजन के 10 साल बाद खत्म हुआ आंध्र प्रदेश का विशेष पैकेज का इंतजार

>> 8

वर्ष 8 अंक 45

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, बुधवार, 24 जुलाई, 2024

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 16

संपादकीय

वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार: माना जा रहा था कि चुनावी झटके के बाद

बजट कुछ लोकलुभावन हो सकता है, लेकिन सरकार ने उचित ही उससे किनारा किया। **धर्मकीर्ति जोशी** का दृष्टिकोण।

समावेशी विकास के हरसंभव उपाय: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सतत आर्थिक वृद्धि का खाका नजर आता है। **विवेक देवराय** और **आदित्य सिन्हा** का आलेख।

● पेज-10

विमर्श

राजनीतिक संतुलन के साथ विकास पर जोर: केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार दिखता है। इसमें विकसित भारत की आकांक्षा के साथ राजनीतिक संतुलन साधने का भी प्रयास दिखता है। **हर्ष वर्धन त्रिपाठी** का आलेख।

समावेशी नीतियों पर जोर: बजट आम तौर पर लोकलुभावनवाद से प्रेरित रहे हैं, पर मोदी सरकार इससे बचती रही है। इसके बजाय विकास व समावेशी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती रही है। यह बजट भी उसी राह पर है। **डा. अश्विनी महाजन** का दृष्टिकोण।

● पेज-11

एक्स, गूगल को बिरला की बेटी के खिलाफ पोस्ट हटाने का निर्देश

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आइआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स और गूगल को 24 घंटे के अंदर अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। अंजलि बिरला ने मानहानि मुकदमा दायर कर दावा किया है कि झूठा आरोप लगाकर इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो प्रसारित किया जा रहा है कि अपने पिता के प्रभाव के कारण उन्होंने पहले प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण की। (पेज-9)

अबकी बार रोजगार

मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में विकसित भारत का रोडमैप, लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज

आमबजट 2024-25

- दो लाख करोड़ रुपये से 4.10 करोड़ नए रोजगार के अवसर बनेंगे
- ग्रामीण विकास के लिए खोला खजाना, 2.66 लाख करोड़ का आवंटन
- बिहार और आंध्र प्रदेश पर सरकार का विशेष ध्यान
- नौ प्राथमिकताओं के स्तंभ पर बनेगा विकसित भारत

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

नई दिल्ली: तीसरी बार लगातार सत्ता में लौटी मोदी सरकार का पहला आम बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का रोडमैप दिखाता है, लेकिन यह बजट सरकार के समक्ष मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों को साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। इस क्रम में अगले पांच वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करके 4.10 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित करने, आम मध्यम वर्ग को आयकर में थोड़ी राहत देने, ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का आवंटन जैसी घोषणाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश बजट के केंद्र में जिस तरह से रोजगार को रखा गया है, वह भी सरकार के व्यावहारिक अप्रोच को दिखाता है। वित्त मंत्री ने न तो लोकलुभावन वादे किए हैं और न ही बड़े सुधारों का वादा। हालांकि, राजकोषीय प्रबंधन का उनका फार्मूला सफल दिखता है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश किया, जो एक रिकार्ड है। उन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया और उनका अभिभाषण सिर्फ 1.25 घंटे का रहा। लेकिन, यह फरवरी, 2024 में पेश अंतरिम बजट के सोच व नीतियों की निरंतरता को कायम रखने वाला रहा। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आम बजट में विकसित भारत का विस्तृत रोडमैप पेश करने का वादा किया था और मंगलवार को उन्होंने यह किया भी। रोडमैप के तहत नौ प्राथमिकताएं तय की गई हैं। ये हैं कृषि में उत्पादकता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, मैन्यूफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन (शोध व विकास) और अगली पीढ़ी के सुधार। गौर से देखा जाए तो इन सभी सेक्टरों में जो घोषणाएं की गई हैं, उनमें से अधिकांश सीधे या परोक्ष तौर पर रोजगार के अवसर को बढ़ाने वाली हैं।

कोई आश्चर्य नहीं कि वित्त मंत्री के अभिभाषण में रोजगार शब्द का कुल 57 बार इस्तेमाल किया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात हो, रोजगारपरक उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाने का फैसला हो, ज्यादा रोजगार देने के लिए निजी सेक्टर को प्रोत्साहित करने वाली घोषणा हो या पांच वर्षों में उद्योग के मुताबिक 20 लाख प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करने की घोषणा...ये सब रोजगार के मोर्चे पर उठ रहे राजनीतिक सवालों का जवाब दे सकती हैं। रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में कुल दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे 4.10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने का लक्ष्य रखा गया है। सनद रहे कि एक दिन पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2030 तक देश में हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत बताई गई है।

ग्रामीण विकास के लिए बजट में 2.66 लाख करोड़ रुपये और ढांचागत विकास के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान सरकार की नीतिगत निरंतरता को ही दिखाता है। देश में कुल तीन करोड़ नए आवास बनाने का एलान किया गया है। इन उपायों से देश की अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, जिससे लंबे समय तक आर्थिक विकास दर को 7-8 प्रतिशत बनाए रखने में मदद मिलेगी।

स्टार्टअप सेक्टर पर लगाए जाने वाले एंजेल टैक्स को समाप्त करने का एलान: वित्त मंत्री ने स्टार्टअप सेक्टर पर लगाए जाने वाले एंजेल टैक्स को समाप्त करने का एलान किया है। इस टैक्स व्यवस्था से स्टार्टअप कंपनियां काफी परेशानी महसूस कर रही थीं और उन्हें विदेशी निवेश लाने में परेशानी हो रही थी। इसी तरह से सूचीबद्ध कंपनियों में दीर्घकालिक व अल्पकालिक निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं, जबकि संपत्तियों या दूसरे पूंजीगत लाभ पर टैक्स की दर घटाई गई है। इससे शेयर बाजार में छोटे निवेशकों को झटका लग सकता है। एफडीआइ नियमों को और आसान बनाने की घोषणा भी इसमें है। साथ ही भारतीय कंपनियों को विदेश में रुपये में निवेश करने का प्रोत्साहन है। मोबाइल फोन के साथ ही सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है, जिससे इनका आयात सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं को औसतन 17,500 रुपये की कर बचत होगी। पूंजीगत लाभ गणना को लेकर नियमों को भी आसान बनाया गया है।

बजटीय प्रविधानों से पूरी की बिहार और आंध्र प्रदेश की मांग >> पेज 3

7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

- इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया
- फैमिली पेंशन से जुड़े स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 रु. किया गया

राजीव कुमार ● जागरण

नई दिल्ली: इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसका फायदा यह होगा कि अब इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत टैक्स फाइलिंग करने वालों को 7.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और करदाता सालाना 17,500 रुपये तक की बचत कर सकेंगे। अभी नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7.5 लाख रुपये तक की सालना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वेतनभोगियों को टैक्स व्यवस्था में इस बदलाव का लाभ मिलेगा।

इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में कोई राहत नहीं दी गई है। सरकार अब नई टैक्स व्यवस्था को ही प्रोत्साहित कर रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि उनका उद्देश्य टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण करना है। पुरानी व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार की बचत के तहत टैक्स में छूट का प्रविधान है। पेंशनर्स को मिलने वाली फैमिली पेंशन से जुड़े स्टैंडर्ड डिडक्शन को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से चार करोड़ वेतनभोगी-पेंशनभोगी को लाभ मिलेगा।

> गत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी टैक्स फाइलिंग के तहत अब तक चार करोड़ रिटर्न भरे जा चुके हैं और इनमें से 70 प्रतिशत करदाताओं ने फाइलिंग के लिए टैक्स की नई व्यवस्था को चुना है। इस हिसाब से नई टैक्स व्यवस्था में किए गए बदलाव से 70 प्रतिशत करदाताओं को लाभ मिलने जा रहा है।
>
> **-संजय मल्होत्रा**, राजस्व सचिव

> स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने से 15 लाख या इससे अधिक आय वालों को 7,500 रुपये का फायदा मिलेगा। वहीं, टैक्स स्लैब में बदलाव से अतिरिक्त रूप से 10,000 रुपये तक की बचत होगी। इससे पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
>
> **-एमके गुप्ता**, टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया ● एएनआइ

1,200 अंक तक गिरा सेंसेक्स, फिर संभला बाजार

संबंधित >> पेज 6

निर्मला के भाषण में कई मंत्रालयों पर चुप्पी

जाब्यू, नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में एक बात चौंकाने वाली रही। लगभग डेढ़ घंटे के भाषण में रक्षा, गृह, रेलवे, स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय के लिए कोई घोषणा तो दूर, पुरानी उपलब्धियों को गिनाने में भी चुप्पी दिखी। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि बजट को प्राथमिकताओं पर केंद्रित रखा गया था। सरकार में कुछ बातें निरंतरता में होती हैं। फरवरी में पेश वोट आन अकाउंट में रेल व स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर कुछ घोषणाएं की गई थीं। उस वक्त अधिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने, 9-14 वर्ष की बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण जैसी बात कही गई थी। उसी तरह रेल यात्रियों के लिए 40 हजार डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुसार बदलने जैसा जिक्र था। सूत्रों का कहना है कि वह सरकार के वादे का हिस्सा है। इन मंत्रालयों का बजट भी बढ़ाया गया है। रही बात गृह और रक्षा की तो वहां सरकार अपनी तय दिशा से बढ़ रही है।

नीट दोबारा नहीं, फिर से जारी होंगे नतीजे

- सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा दोबारा कराने का आदेश देने से किया इन्कार
- फिजिक्स के एक सवाल के सही विकल्प पर आइआइटी की रिपोर्ट स्वीकारी
- एनटीए को आइआइटी की रिपोर्ट के मुताबिक फिर रिजल्ट जारी करने को कहा
- इससे नीट क्वालीफाई करने वाले करीब 13 लाख छात्रों की रैंक पर पड़ेगा असर

माला दीक्षित ● जागरण

नई दिल्ली : मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को रद कर नए सिरे से कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने साफ किया कि नीट दोबारा नहीं होगा। साथ ही कहा कि रिकार्ड पर ऐसा कोई डाटा या साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर नीट में बड़े स्तर पर प्रश्नपत्र लीक के बारे में प्रणालीगत खामियों के संकेत मिलते हों जिसके कारण पूरी परीक्षा की शुचिता भंग हुई हो। लिहाजा पूरी परीक्षा रद करने का आदेश देना न्यायोचित नहीं होगा। दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से 23 लाख से ज्यादा छात्रों पर गंभीर असर होगा जो परीक्षा में शामिल हुए थे, साथ ही मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश का शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाएगा कोर्ट ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से वंचित वर्ग के छात्र भी प्रभावित होंगे जिनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। हालांकि कोर्ट ने माना कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट रद कर दोबारा कराने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन फिजिक्स के एक सवाल के सही विकल्प पर आइआइटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को उसके मुताबिक नए सिरे से नीट का रिजल्ट जारी करने को कहा है। इससे नीट क्वालीफाई करने वाले करीब 13 लाख छात्रों की रैंक पर असर पड़ेगा क्योंकि नियम के मुताबिक सही जवाब के चार अंक मिलते हैं और गलत जवाब पर एक अंक कट जाता है। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने नीट में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों पर चार दिन बहस सुनने के बाद मंगलवार को दिए। कारणों के साथ विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

केंद्र सरकार और एनटीए ने कोर्ट में परीक्षा रद करने का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि पूरी परीक्षा रद कर नए सिरे से नीट का आयोजन कराने से ईमानदार व मेहनती छात्रों के हित प्रभावित होंगे। एनटीए ने भी पूरी परीक्षा रद करने का विरोध करते हुए कहा था कि पेपर लीक की घटनाएं पटना और हजारीबाग तक सीमित हैं। परीक्षा में प्रणालीगत नाकामी नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं एवं केंद्र व एनटीए की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की बहस सुनने और सीबीआइ, बिहार पुलिस व बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट देखने के बाद यह फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को लेकर जिन छात्रों को व्यक्तिगत शिकायत है, वे कानून के मुताबिक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत मांग सकते हैं।

कोर्ट ने आदेश में माना कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था, लेकिन इस बारे में सीबीआइ की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जांच अभी चल रही है और रिपोर्ट के मुताबिक हजारीबाग और पटना में पेपर लीक का लाभ लेने वाले 155 छात्र थे। कोर्ट ने कहा चूंकि दागी छात्रों की पहचान की जा सकती है इसलिए दोबारा पूरी परीक्षा कराने की दलीलें स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। अगर सीबीआइ जांच में आगे छात्रों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर उन छात्रों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। कोई भी छात्र जो इस फर्जीवाड़े में शामिल रहा है और लाभार्थी रहा है, वह प्रवेश जारी रखने का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने समय की बर्बादी, प्रश्नपत्र के सेट में परिवर्तन और भाषा संबंधी मुद्दों के कारण 1,563 छात्रों के लिए पुनःपरीक्षा आयोजित करने के एनटीए के निर्णय को भी बरकरार रखा।

गुमराह करने के लिए माफी मांगें राहुल गांधी और विपक्ष : प्रधान

नई दिल्ली : नीट-यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों व अभिभावकों को गुमराह करने और देश की पूरी परीक्षा प्रणाली को उन्होंने जिस तरह से निंदित किया है, उसके लिए उन्हें बच्चों- अभिभावकों के साथ पूरे शिक्षण समाज से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। (पेज-12)

उप्र के 45 नकल माफिया पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

- मेरठ, बागपत और कौशांबी में दर्ज तीन मुकदमों में हैं आरोपित
- जांच कर रही एसटीएफ, संपत्ति जब्त करने की होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मेरठ

नकल माफिया पर शिकंजा कसने के अभियान में मेरठ, बागपत और कौशांबी में दर्ज मुकदमों में 45 नकल माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता भंग करने के उद्देश्य से प्रश्नपत्र आउट करने का आरोप है। इन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती, आरओ-एआरओ और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का प्रश्नपत्र लीक कराया था। आरोपितों ने पेपर लीक कराकर अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है। अब इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

एसटीएफ एएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने पर मेरठ में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 22 आरोपित थे। गिरोह के मास्टरमाइंड रवि अत्री, राजीव नयन मिश्रा, विक्रम पहल और अमित सिंह हैं। इन्होंने आरओ-एआरओ भर्ती का पेपर भी लीक कराया था।

उक्त मामले में कौशांबी में मास्टरमाइंड समेत 23 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। राहुल चौधरी समेत चार आरोपितों ने टीईटी का पेपर लीक कराया था। उनके खिलाफ बागपत में मुकदमा दर्ज है। 49 आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाई गई है, लेकिन मेरठ के चार आरोपितों के नाम कौशांबी में दर्ज मुकदमे में भी हैं। इसलिए गैंगस्टर के कुल आरोपितों की संख्या 45 है। तीनों मुकदमों के 45 आरोपितों में से 30 को जमानत मिल चुकी है। इन सभी की अब गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी होगी। 15 आरोपित अभी जेल में हैं। इनकी संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए गए हैं।

प्रमुख आरोपितों में ये हैं शामिल

हरियाणा : महेंद्र शर्मा (जींद), सतीश धनखड़ (गुरुग्राम), विक्रम पहल (जींद निवासी दिल्ली पुलिस का सिपाही)

बिहार : डा. शुभम मंडल (पटना), राजीव नयन मिश्रा उर्फ राहुल मिश्र (प्रयागराज), सुभाष प्रकाश (मधुबनी), अमरजीत शर्मा (गया)।

मध्य प्रदेश : सुनील रघुवंशी (भोपाल)।

राज्यपाल की बगैर अनुमति तृकां विधायकों को दिलाई गई शपथ

कोलकाता : बंगाल में राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के चार विधायकों को मंगलवार को विधानसभा में शपथ दिलाई। इस कदम के बाद राजभवन के साथ टकराव और बढ़ने के आसार हैं। (पेज-12)

जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री पर विभाजित फैसला

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों (जीएम सरसों) की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति संबंधी मामले में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अनुमति देने के खिलाफ फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस संजय करोल ने बिक्री को मंजूरी देने के जीईएसी के फैसले को बरकरार रखा। (पेज-12)

कनाडा में हिंदू मंदिर को फिर बनाया गया निशाना

ओटावा : कनाडा में हिंदू मंदिर को फिर निशाना बनाया गया है। देश में एडमंटन शहर में सोमवार सुबह बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे पाए गए। वैंकूवर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने कनाडा की जिम्मेदार एजेंसियों से आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए घटना की जांच की मांग की है। (पेज-14)

प्रशिक्षु आइएएस का मामला

अब पूजा के माता-पिता की वैवाहिक स्थिति पर सवाल

प्रशिक्षण के दौरान नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी कार में लालबत्ती लगाने के बाद आईं सुर्खियों में, फर्जी तरीके से यूपीएससी की परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का लाभ लेने का है आरोप

- पारिवारिक आय शून्य दिखाने को किया था माता-पिता के अलग होने का दावा

पुणे, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने पुणे पुलिस से विवादास्पद प्रशिक्षु आइएएस अफसर पूजा खेडकर के माता-पिता की वैवाहिक स्थिति की जानकारी मांगी है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने यह निर्देश पूजा पर यह आरोप लगने के बाद दिया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने माता-पिता के अलग होने का दावा कर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) गैर क्रीमी लेयर का लाभ लिया।

खेडकर पर हाल ही में पुणे जिला कलेक्ट्रेट में प्रशिक्षण के दौरान नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी कार में लालबत्ती लगाने और अपने वरिष्ठ अधिकारी के केबिन को जबरन हथियाने का आरोप लगा था। जिलाधिकारी ने इसकी शिकायत राज्य के मुख्य सचिव से कर दी थी। इसके बाद पूजा का वहां से स्थानांतरण कर दिया गया था।

अपनी इन्हीं मनमानी को लेकर जब वह सुर्खियों में आईं तो उनके द्वारा विगत में की गई सभी गलतियों की परतें खुलती गईं। उनके विरुद्ध दिल्ली में गलत बयानी और गलत तथ्य पेश करने के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 2022 की परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद करने के संबंध में एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रशिक्षु आइएएस पूजा खेडकर। एएनआइ/फाइल

पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें यह बताने के लिए कहा है कि क्या पूजा खेडकर के माता-पिता तलाकशुदा हैं।

फिलहाल पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई है। यूपीएससी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) गैर क्रीमी लेयर कोटा का लाभ उठाने के लिए खेडकर ने दावा किया था कि उनके माता-पिता अलग हो गए थे। वह अपनी मां के साथ रह रही थीं। अपने माक इंटरव्यू के एक वीडियो में खेडकर से पूछा गया कि उनके परिवार की आय को शून्य क्यों दिखाया गया है, जबकि उनके पिता एक लोक सेवक थे। वह कहती नजर आ रही हैं कि उनके माता-पिता अलग हो गए थे और वह अपने पिता के संपर्क में नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि पूजा के दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर भी सवाल उठे हैं।

रत्न भंडार की लेजर स्कैनिंग पर निर्णय एएसआइ की रिपोर्ट के बाद

भुवनेश्वर : ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) विभाग की टीम दो-चार दिनों में पुरी श्रीमंदिर के रत्न भंडार के अंदर निरीक्षण शुरू कर देगा। उसकी रिपोर्ट के बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि रत्न भंडार की लेजर स्कैनिंग होगी या नहीं। निरीक्षण से रत्न भंडार की मौजूदा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। (पेज-13)

अमेरिका में कमला हैरिस इतिहास रचने को तैयार

वाशिंगटन : अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समर्थन जुटा कर इतिहास रचने को तैयार हैं। पार्टी के चार हजार प्रतिनिधियों में से 2,538 ने समर्थन किया है, जो उम्मीदवारी के लिए जरूरी 1,976 प्रतिनिधियों के समर्थन से अधिक है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एपी के सर्वे में सामने आई है। (पेज-14)

पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ का षड्यंत्र विफल, जवान बलिदान

जागरण संवाददाता, राजौरी

लांस नायक सुभाष चंद्र। स्रोत : पीआरओ डिफेंस

हाथरस के रहने वाले थे सुभाष चंद्र, 10 दिनों में घुसपैठ की यह तीसरी साजिश

पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार तड़के जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ के षड्यंत्र को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। आतंकियों को पीछे खदेड़ने के दौरान एक जवान बलिदान हो गया। वीरगति पाने वाले जवान सुभाष चंद्र उत्तर प्रदेश के हाथरस के निवासी थे।

जानकारी के अनुसार तड़के करीब चार बजे आतंकियों के एक दल ने कृष्णा घाटी सेक्टर के बट्टल क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने का प्रयास किया। सेना के जवानों ने चेतावनी दी तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी वापस भागने को मजबूर हो गए। बलिदानी जवान का पार्थिव शरीर राजौरी में सेना के 150 जनरल अस्पताल लाया गया है, जहां पर श्रद्धांजलि के उपरांत पार्थिव शरीर को हाथरस के लिए रवाना किया जाएगा।

बता दें कि 10 दिनों में घुसपैठ की यह तीसरी साजिश थी। 14 जुलाई को कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ का प्रयास किया था। वहां भी सेना ने तीन आतंकियों को ढेर कर पाकिस्तान के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया था। 18 जुलाई भी को केरन से ही घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें दो आतंकी मारे गए।

****

समृद्ध युवा

महिला कामगारों के लिए सरकार उद्योगों के सहयोग से हास्टल और शिशु गृहों की स्थापना करेगी

चुनाव में मुद्दा रही बेरोजगारी से निपटने का रोडमैप तैयार

प्रधानमंत्री रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के लिए दो लाख करोड़ रुपये का पैकेज

नीलू रंजन ● जागरण

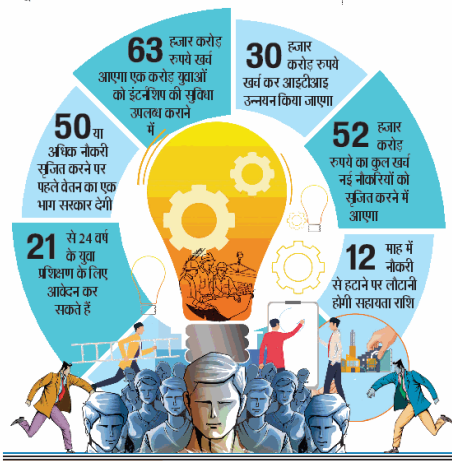

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने बेरोजगारी की समस्या से निपटने पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में पूरा जोर दिया गया है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में रोजगार शब्द का प्रयोग 57 बार किया। बजट की नौ प्राथमिकताओं में भी रोजगार और कौशल विकास दूसरे स्थान पर है। आने वाले दो से चार साल में चार करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस पर दो लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पैकेज के तहत निजी कंपनियों के लिए तीन तरह के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। पहले प्रोत्साहन पैकेज में निजी कंपनी में पहली बार नौकरी पाने वाले युवा की पहले महीने के वेतन का भुगतान सरकार करेगी। शर्त यह है कि उस युवा का वेतन प्रति माह एक लाख रुपये से कम होना चाहिए। इस वेतन का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा, लेकिन दूसरी किस्त से पहले युवा को आनलाइन वित्तीय साक्षरता का पाठ्यक्रम सीखना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रति युवा अधिकतम सहायता की राशि 15 हजार रुपये निर्धारित की गई है। 12 महीने से पहले नौकरी से निकालने पर नियोक्ता कंपनी को सरकार से मिली राशि वापस करेगी। इससे एक साल में एक करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। दो साल तक चलने वाली इस योजना पर 23 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

4.1 करोड़ युवाओं को पांच सालों में रोजगार देने की व्यवस्था बनी

1 करोड़ युवाओं को पांच हजार रुपये का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा

एक हजार आइटीआइ का उन्नयन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा

निर्मला सीतारमण ने देश की 500 बड़ी कंपनियों में पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं के लिए प्रशिक्षण का एलान किया है। इस योजना के तहत 21 से 24 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। एक करोड़ युवाओं के इंटर्नशिप पर कुल 63 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा अगले पांच साल में 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक हजार आइटीआइ का उन्नयन होगा, इससे 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जा सकेगा।

नई नौकरी सृजित करने पर नियोक्ताओं को सहायता: ईपीएफओ में अंशदान करने वाले नियोक्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरी सृजित करने पर सहायता दी जाएगी। ईपीएफओ में नियोक्ता और कर्मचारी की राशि के एक हिस्से का भुगतान सरकार करेगी। शर्त यह है कि नौकरी पाने वाला युवा पहले ईपीएफओ में शामिल न हुआ हो और वेतन प्रतिमाह एक लाख रुपये से अधिक न हो। यह सहायता पहले महीने के वेतन के रूप में दी जाने वाली सहायता से अलग होगी। अनुमान है कि इससे दो सालों में 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस पर कुल 52 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

पहली बार नौकरी में वेतन का एक हिस्सा सरकार देगी: इसके अलावा एक साल में 50 या उससे अधिक नई नौकरी सृजित करने वाले कारपोरेट और गैर-कारपोरेट प्रतिष्ठानों में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के वेतन का एक हिस्सा सरकार देगी। पहले और दूसरे साल में वेतन का 24 प्रतिशत, तीसरे साल में 16 और चौथे साल में आठ प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच बराबर बांटी जाएगी। यहां भी एक लाख रुपये प्रतिमाह से कम वेतन की शर्त है। लेकिन प्रतिमाह 25 हजार से अधिक का वेतन होने पर भी प्रोत्साहन राशि इतने ही वेतन के हिसाब से होगी। 50 लाख युवाओं को नौकरी मिलने का अनुमान है व 32 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा।

एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, मिलेगा भत्ता

अरविंद पांडेय, जागरण

नई दिल्ली: पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए ज्यादा नहीं भटकना होगा, बल्कि उन्हें देश की शीर्ष पांच सौ कंपनियों में तुरंत ही इंटर्नशिप का एक बड़ा मौका मिलेगा। जहां रोजगार से जुड़ा 12 महीनों के प्रशिक्षण के साथ ही हर महीने पांच हजार रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी मिलेगा। इस दौरान छह हजार रुपये की एकमुश्त मदद अलग से दी जाएगी। इस स्कीम के तहत अगले पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य है। हर साल करीब 20 लाख छात्र लाभांवित होंगे, लेकिन यह स्कीम पूरी स्थिति बदल देगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर वर्ष लगभग डेढ़ करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर बाहर निकलते हैं।

इंटर्नशिप स्कीम के तहत इंटर्नशिप व प्रशिक्षण लागत पर होने पर कुल खर्च का 10 प्रतिशत हिस्सा कंपनियां अपने सीएसआर फंड से खर्च कर सकती हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों में शुरू किए चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप अनिवार्य है, जिसके चलते सरकार इस पर जोर दे रही है। अभी स्नातक के बाद भी छात्र के पास कोई रोजगारपरक कौशल नहीं होता है। इस स्कीम के पीछे मुख्य लक्ष्य इसी समस्या से पार पाना है।

इस स्कीम की राह में एक और बड़ी चुनौती, जो देखने को मिल सकती है, वह कंपनियों की रुचि भी होगी। सरकार ने भले ही पांच सौ शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कराने का एलान कर दिया है लेकिन कंपनियां कितना रुचि दिखाती हैं, यह प्रश्न है। साथ ही इन शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप करने के लिए हमारे छात्र किस स्तर तक तैयार होते हैं।

500 शीर्ष कंपनियों में मिलेगा इंटर्नशिप का मौका

- पढ़ाई पूरी करते ही युवाओं को इंटर्नशिप कराने की बड़ी पहल
- इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक को छह हजार रुपये की मदद अलग से

बजट बोल

यह बजट युवाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश की भावी पीढ़ी को मजबूती देने के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं।

- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

सरकार ने 'कुर्सी बचाओ' बजट पेश किया है। सहयोगियों को खुश करने के लिए अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए हैं। यह बजट कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र और पिछले कुछ बजट की नकल है। आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी गई।

-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

यह देखकर अच्छा लगा कि सरकार ने रोजगार और कौशल विकास को पहली प्राथमिकता दी है। इससे यह पता चलता है कि सरकारी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और कुछ अर्थशास्त्रियों की तरह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के झूठे दावों से प्रभावित नहीं है।

-राजीव कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग

'आईना' देख कौशल विकास योजना को अब नया रूप

जितेंद्र शर्मा ● जागरण

नई दिल्ली: युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए इस बार अधिक चिंतित दिखी सरकार ने न सिर्फ चहुंओर संभावनाओं को टटोला है, बल्कि वास्तविकता का 'आईना' देखते हुए प्रयासों को नया रंग-रूप देते नजर आई है। यहां साफ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के चौथे चरण को लागू करने की जल्दबाजी दिखाने की बजाए तीन चरणों से सबक लेते हुए जमीन मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाया है। इस बार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) के कायाकल्प के प्रति गंभीरता बरतते हुए पांच वर्ष में एक हजार आइटीआइ को अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। महत्वपूर्ण यह कि इसमें राज्यों को भी साझेदार बनाया गया है।

मोदी सरकार ने कौशल विकास की भविष्य की जरूरत मानते हुए पहले कार्यकाल में ही कौशल विकास एवं उद्यमीशलता मंत्रालय की स्थापना की। उसमें सबसे प्रमुखता से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की, जिसमें कई कौशल कार्यक्रम शामिल किए गए। इस योजना के तीन चरण पूरे होने के बाद भी आशातीत सफलता नहीं मिली। विशेषज्ञों ने नए सुधारों की आवश्यकता जताई, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की रूपरेखा तय कर ली गई, लेकिन चिंता का सबब यह तथ्य रहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या जोड़ ली जाए, तब भी देशभर में औपचारिक तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं का आंकड़ा मात्र 4.4 प्रतिशत ही है, जबकि अनौपचारिक रूप से यह 16.6 प्रतिशत युवाओं ने लिया।

सरकार के पास यह रिपोर्ट भी आई कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ढांचागत या अकादमिक स्तर वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। वह भी तब, जबकि बीते दो कार्यकाल में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय चरणवार ढंग से 1,396 आइटीआइ के उन्नयन पर करोड़ों रुपये खर्च कर चुका है। उद्योगों की भागीदारी भी आशा अनुरूप नहीं रही। बहरहाल, अब सरकार ने पीएमकेवीवाई के मद में कोई आवंटन न करते हुए सबसे अधिक ध्यान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपग्रेडेशन पर लगाया है। प्रधानमंत्री पैकेज के रूप में योजना को शामिल करते हुए पांच वर्ष में एक हजार आइटीआइ को अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। इन्हें स्किल हब के रूप में विकसित करते हुए कौशल की गुणवत्ता बढ़ाने, उद्योग की आवश्यकता अनुसार नए पाठ्यक्रम शामिल करने, वर्तमान पाठ्यक्रमों के पुनर्निधारण और हब आइटीआइ में अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पांच वर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकारें 20,000 करोड़, जबकि उद्योग समूह सीएसआर फंड को सम्मिलित करते हुए 10,000 करोड़ रुपये खर्च अंशदान देंगे। इसके साथ ही पांच राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में भी विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन प्रयासों के माध्यम से पांच वर्ष में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास का है।

उल्लेखनीय है कि इस बार सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का बजट 4,520 करोड़ रुपये रखा है, जबकि 2023-24 का बजट 3,260.18 करोड़ रुपये था। तब की तुलना में जो लगभग 1,259 करोड़ की वृद्धि हुई है, उसमें से एक हजार करोड़ तो इस वर्ष आइटीआइ अपग्रेड करने वाले मद में ही खर्च किया जाना है।

4.4% युवा देश भर में औपचारिक रूप से प्रशिक्षण लेते हैं

20 लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य पांच वर्ष के लिए रखा, पीएमकेवीवाइ के चौथे चरण को अभी विराम

1,396 आइटीआइ के उन्नयन में पिछले दो वर्ष में करोड़ों रुपये खर्च किए गए

अर्थव्यवस्था में नारी शक्ति की बढ़ेगी भागीदारी

माला दीक्षित ● जागरण

नई दिल्ली: मोदी सरकार का शुरू से मानना रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने और जीडीपी को दहाई अंकों में पहुंचाने के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना और कार्यबल में उनकी भागीदारी जरूरी है। सरकार की यह सोच इस बजट में भी दिखाई देती है। बजट में 'महिला संचालित विकास' को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक रुपये के आवंटन की व्यवस्था की गई है। साथ ही कामकाजी महिलाओं की जिंदगी आसान बनाने के लिए सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कहा कि महिला कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। इन सुविधाओं से कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। मोदी सरकार शुरू से 'वुमेन लेड डेवलपमेंट' की बात करती रही है, बजट में भी यह दिखाई देता है। इसे बढ़ावा देने के लिए बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की व्यवस्था की गई है। यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की ओर संकेत करता है। महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें अचल संपत्ति की मालकिन बनने को प्रोत्साहन देने की भी एक नीति बजट में दी गई है। बजट में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों में स्टांप शुल्क कम करने पर विचार किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगी। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कुल बजट में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 2023-24 के बजट में इस मंत्रालय का बजट 25,448.68 करोड़ रुपये था जो कि इस बार बढ़ा कर 26,092.19 कर दिया गया है।

- महिला संचालित विकास को मिलेगा बढ़ावा
- संपत्ति पंजीकरण में महिलाओं को खास राहत
- कामकाजी महिला छात्रावासों की होगी स्थापना

25,449 करोड़ रुपये पिछले बजट में दिए गए थे

26,092 करोड़ रुपये का बजट इस बार रखा गया है

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को 1,225 करोड़ रुपये आवंटित

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को 1,225.27 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। पिछले वर्ष के बजट 1,225.01 करोड़ रुपये से यह 0.02 प्रतिशत अधिक है।

बजट का एक हिस्सा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को समर्पित है, जिसमें 615.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण खरीदने के लिए 315 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना में 130 करोड़ रुपये से 165 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना के लिए 135 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के 67 करोड़ रुपये थे। शैक्षणिक सहायता प्राथमिकता बनी है, दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 142.68 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो उच्च शिक्षा से उन्हें सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र के लिए राशि 76 से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी गई है।

315 करोड़ रुपये सहायक उपकरण खरीदने के लिए देने की घोषणा की

अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने को बनेगा तंत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार बुनियादी शोध और मूलभूत विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का संचालन करेगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि सरकार अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप एक लाख करोड़ रुपये की योजना के साथ व्यावसायिक स्तर पर प्राइवेट क्षेत्र की ओर संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी।

सीतारमण ने समुद्र मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये भी आवंटित किए, जिसके तहत सरकार समुद्र के 6,000 मीटर की गहराई तक मानवयुक्त पनडुब्बी समुद्रयान लांच करने की योजना बना रही है ताकि गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज की जा सके और उनके सतत उपयोग के लिए तकनीक विकसित की जा सके। मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 3,064.80 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें समुद्र मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये शामिल हैं।

डीएसआइआर के लिए आवंटित 6,323.41 करोड़ रुपये में से 6,265.80 करोड़ रुपये विज्ञानी और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए निर्धारित किए गए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को 2023-24 के संशोधित अनुमानों में 4,891.78 करोड़ रुपये के मुकाबले 8,029.01 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। आवंटन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए है, जिसे 2023-24 के संशोधित अनुमानों में पांच करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले 427 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग को पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में प्राप्त 1607.32 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,275.70 करोड़ रुपये मिले हैं।

- विज्ञानी व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए निर्धारित किए 6,266 करोड़ रुपये

600 करोड़ रुपये वित्त मंत्री ने समुद्र मिशन के लिए आवंटित किए

मुद्रा स्कीम में ऋण सीमा दोगुनी 10 से बढ़ाकर की गई 20 लाख

दिल्ली में फुटवियर क्लस्टर की एक फैक्ट्री में चप्पल बनाता श्रमिक ● जागरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम में सरकार ने ऐसे ईमानदार उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है, जो तरुण श्रेणी में पंजीकृत हैं और उन्होंने अपना पुराना ऋण समय पर चुका दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब वे बैंकों से इस श्रेणी में 20 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे। अभी तक इस स्कीम के तहत वे इस श्रेणी में सिर्फ 10 लाख रुपये तक का ही ऋण लेने के लिए पात्र थे।

बजट में सरकार ने पीएम मुद्रा स्कीम में बदलाव का यह एलान तब किया है, जब यह स्कीम छोटे-छोटे उद्यमों से जुड़े लोगों को अपने उद्यम को मजबूती देने में पिछले वर्षों में काफी सफल साबित हुई है। स्कीम के तहत आठ वर्षों में लगभग 41 करोड़ लोगों को लाभ दिया गया है। इनमें सबसे अधिक लाभार्थी शिशु श्रेणी के थे, जिन्हें स्कीम के तहत 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया गया। इनकी संख्या पिछले आठ वर्षों में करीब 34 करोड़ रही है। इसके साथ ही इस स्कीम के तहत किशोर श्रेणी में करीब छह करोड़ लोगों को लाभ किया गया है। इनमें लोगों को अपने उद्यम को चलाने के लिए 50 हजार से पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

गौरतलब है कि पीएम मुद्रा स्कीम का एलान अप्रैल, 2015 में किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब से लेकर अब तक इस स्कीम के तहत लोगों को करीब 23 लाख करोड़ का ऋण बांटा जा चुका है। इस स्कीम के तहत तीन श्रेणियों में लोन दिए गए थे। इनमें पहली शिशु श्रेणी, दूसरी किशोर श्रेणी और तीसरी तरुण श्रेणी है।

- तरुण श्रेणी के उद्यमियों पर सरकार ने दिखाई दरियादिली
- पहले लिए ऋणों को चुकाने पर ही मिलेगा नया ऋण

उच्च शिक्षा की पढ़ाई देश में करने पर 10 लाख तक सस्ता लोन

अरविंद पांडेय ● जागरण

नई दिल्ली: उच्च शिक्षा की राह में पैसों की कमी अब आड़े नहीं आएगी। बजट में इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया है। गरीब और कमजोर वर्ग के ऐसे विद्यार्थी, जो सरकार की किसी दूसरी स्कीम या नीति से लाभान्वित नहीं हैं, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने को सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। उन्हें देश में ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने पर अब 10 लाख रुपये तक का सस्ता शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा।

हर साल एक लाख विद्यार्थियों को इसका योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान विद्यार्थियों को वार्षिक ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट का एक ई-वाउचर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस पहल से उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) की गति में भी तेजी जाएगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश की ओर रुख करने वालों का पलायन भी थमेगा।

वैसे तो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए शिक्षा ऋण की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है, लेकिन मौजूदा समय में इस ऋण की वार्षिक ब्याज दर करीब 10 प्रतिशत है। इसके साथ ही सात लाख रुपये से अधिक का शिक्षा ऋण लेने पर अभी गारंटी देनी होती है। इसके अतिरिक्त इनमें ढेर सारी तकनीकी दिक्कतें भी हैं। फिलहाल सिर्फ उन्हीं संस्थानों में पढ़ाई करने पर शिक्षा ऋण दिया जाता है, जो नैक (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडेशन काउंसिल) या एनआइआरएफ (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) की रैंकिंग में शामिल होते हैं।

खास बात यह है कि इस ऋण को चुकाने में भी विद्यार्थियों को काफी सहूलियतें सरकार की ओर से से प्रदान की गई हैं। यानी विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार ऋण को किश्तों में चुका सकेंगे।

उच्च शिक्षा को लेकर सरकार का यह रुझान उस समय देखने को मिला है, जब उच्च शिक्षा के जीईआर को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिशा में सरकार तेज गति से काम कर रही है।

मौजूदा समय की बात करें तो देश में उच्च शिक्षा का जीईआर करीब 28 प्रतिशत है। यानी उच्च शिक्षा हासिल करने वाले आयु वर्ग के सौ विद्यार्थियों में अभी 28 ही उच्च शिक्षा हासिल करने तक पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में, इसे अगले 10 वर्षों में करीब दोगुना करने के लिए इस तरह के और भी उपायों को लागू करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं, वर्ष 2023 में करीब 12 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। हालांकि, इनमें बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है, जिन्हें देश के अच्छे संस्थानों में दाखिला नहीं मिल पाता है।

- दूसरी किसी स्कीम या नीतियों से लाभान्वित नहीं होने वाले एक लाख छात्रों को मिलेगा यह लाभ
- विद्यार्थियों को वार्षिक ब्याज दर में तीन प्रतिशत की छूट के लिए ई-वाउचर मिलेगा
- इस पहल के जरिये उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात की गति में तेजी आएगी

12 लाख विद्यार्थी ने वर्ष 2023 में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेशों का रुख किया था

50 प्रतिशत जीईआर वर्ष 2035 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

****

समृद्ध किसान

2013-14 में कृषि का बजट 21933.50 करोड़ था, जो 2024-25 में 1.52 लाख करोड़ हो गया

कृषि और इससे संबंधित उद्योगों की स्थिति

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। यहां गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, काफी, मसाले और दालों सहित फसलों की एक विशाल श्रृंखला है, जो बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष बाजार का आकार (अरब डालर)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
283.68	267.90	276.37	279.00	259.71	288.78	277.01

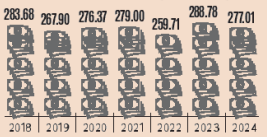

फसलवार संरचना (करोड़ हेक्टेयर)

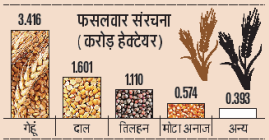

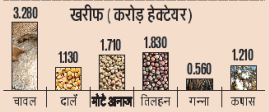

गेहूं	दाल	तिलहन	मोटा अनाज	अन्य
3.416	1.601	1.110	0.574	0.393

खरीफ (करोड़ हेक्टेयर)

चावल	दालें	मोटे अनाज	तिलहन	गन्ना	कपास
3.280	1.130	1.710	1.830	0.560	1.210

विश्व बाजार में भारत की उपस्थिति

कृषि का बढ़ता निर्यात

वित्तीय वर्ष	निर्यात
2020	35.09
2021	41.25
2022	50.21
2023	53.12
2024	48.9

(आंकड़े अरब डालर में)

कृषि उत्पाद एवं संबद्ध क्षेत्र में निर्यात विस्तार

चावल	10.43
समुद्री उत्पाद	7.37
मसाले	4.25
भैंस का मांस	3.74
चीनी	2.82
विविध संसाधित	1.65

लहलहाती फसलों के लिए कृषि क्षेत्र को खाद-पानी

अरविंद शर्मा ● नई दिल्ली

नई दिल्ली : आम बजट में अन्नदाता को सबसे ऊपर रखा गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी पुरानी योजनाओं को बरकरार रखते हुए खेती कारोबार में व्यापक परिवर्तन के साथ किसानों के लिए कुछ नई सौगातों की भी घोषणा की गई है। खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसान कल्याण का ध्यान रखते हुए सर्वाधिक फोकस खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और जलवायु के अनुरूप खेती के विकास पर किया गया है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व्यवस्था की वृहद समीक्षा के साथ नए निवेश की बात कही गई है। इसके लिए सरकारी क्षेत्र के साथ निजी निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्नदाता को प्रधानमंत्री की चार प्रमुख जातियों में से एक बताया गया और कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए इनपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सरकार ने लगभग सभी प्रमुख फसलों के लिए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है, जो खेती की लागत से 50 प्रतिशत अधिक है। बजट में कृषि पर आधारित सारांश किसानों को खेती के वर्तमान तरीके से निकालकर प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने का प्रयास है। परंपरागत खाद्यान्न फसलें धान और गेहूं के अतिरिक्त कृषि के सभी क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाकर अर्थव्यवस्था को गति देना समय की मांग है। इसलिए नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए एक लाख 52 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो फरवरी में अंतरिम बजट के आवंटन से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है।

किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत बागवानी समेत 32 फसलों की 109 सर्वाधिक पैदावार वाली किस्में जारी की जाएंगी, जो नई के साथ-साथ जलवायु के अनुकूल भी होंगी। अगले दो वर्षों के दौरान एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सहायता राशि एवं प्रमाण पत्र देने के साथ-साथ उनके उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। इसका प्रबंधन कृषि वैज्ञानिक संस्थाओं एवं पंचायतों की देखरेख में किया जाएगा। बजट में दलहन एवं तेलहन की पैदावार बढ़ाकर किसानों के लिए अतिरिक्त आय के प्रबंधन के प्रयासों पर फोकस किया गया है। एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने ईमानदारी से स्वीकार किया था कि तमाम प्रयासों के बावजूद किसानों की आय अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पाई है। इसलिए कृषि में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए तकनीक एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ भंडारण एवं विपणन व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी जैसी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए भी एक कार्यनीति बनाई जा रही है। अंतरिम बजट में 'आत्मनिर्भर तिलहन अभियान' शुरू करने की बात कही गई थी, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा।

छह करोड़ किसानों और उनकी जमीन के विवरण को किया जाएगा एकत्र

कृषि में सूचना विषमता को दूर करने एवं किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास का वादा किया गया है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों के सहयोग से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू किया जाएगा। इसके तहत तीन वर्षों में किसानों और उनकी जमीन का विवरण जुटाना है। डीपीआई के जरिए इस वर्ष खरीफ फसलों का चार सौ जिलों में डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके तहत लगभग छह करोड़ किसानों और उनकी जमीन के विवरण को एकत्र किया जाएगा।

अमृतसर में धान की फसल पर उर्वरक छिड़कते हुए एक किसान ● एएफपी

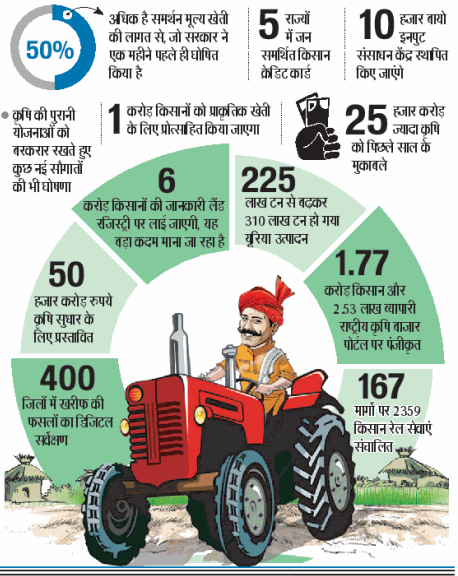

50% अधिक है समर्थन मूल्य खेती की लागत से, जो सरकार ने एक महीने पहले ही घोषित किया है

5 राज्यों में जन समर्थित किसान क्रेडिट कार्ड

10 हजार बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे

- कृषि की पुरानी योजनाओं को बरकरार रखते हुए कुछ नई सौगातों की भी घोषणा

1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

25 हजार करोड़ ज्यादा कृषि को पिछले साल के मुकाबले

6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, यह बड़ा कदम माना जा रहा है

225 लाख टन से बढ़कर 310 लाख टन हो गया यूरिया उत्पादन

50 हजार करोड़ रुपये कृषि सुधार के लिए प्रस्तावित

1.77 करोड़ किसान और 2.53 लाख व्यापारी राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर पंजीकृत

400 जिलों में खरीफ की फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण

167 मार्गों पर 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित

25 हजार ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़क

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ग्रामीण भारत को सड़कों से जोड़ने की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण का विस्तार करने की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में घोषणा की है। पीएमजीएसवाई के इस चौथे चरण में 25000 उन ग्रामीण बसावटों को हर मौसम के अनुकूल पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। गांवों को सीधे सड़क संपर्क से जोड़ने की इस योजना के तहत उन सभी ग्रामीण बसावटों तक पक्की सड़क पहुंचना है जिनकी आबादी सौ से अधिक है।

वित्तमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजटीय आवंटन के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के चौथे चरण के विस्तार की घोषणा करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए राशि आवंटित करने की बात कही।

पीएमजीएसवाई के तहत लगभग सभी ग्रामीण इलाकों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है और तीसरे चरण के दौरान उन ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण करने की योजना को भी मंजूरी दी गई थी जिन पर आवागमन का दबाव ज्यादा है।

4 चरण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का किया जाएगा विस्तार

2 करोड़ और ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य है योजना के तहत

100 से अधिक आबादी वाली ग्रामीण बसावटों को इस योजना से जोड़ा जाएगा

ग्रामीण विकास के बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, प्रेट्र : ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2024-25 के बजट में 1,77,566.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1,57,545 करोड़ रुपये के परिव्यय से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, संशोधित अनुमानों की तुलना में यह वृद्धि लगभग 3.7 प्रतिशत है। मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय की मध्य-वर्ष समीक्षा 1,71,069.46 करोड़ थी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट आवंटन की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मदद करेगा। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना (मनरेगा) के लिए आवंटन 86 हजार करोड़ रुपये है, जो पिछले बजट में किए गए 60 हजार करोड़ रुपये से लगभग 43 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर कुल व्यय 86 हजार करोड़ रुपये था, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए किए गए आवंटन के समान है। 2022-23 में सरकार ने बजट में मनरेगा के लिए 73 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि बजट दस्तावेज के अनुसार वास्तविक व्यय 90,805 करोड़ रुपये था। यह योजना प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इसके तहत एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए आवंटन 54,500.14 रुपये है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य दो करोड़ और ग्रामीण आवास बनाना है।

तीन करोड़ लखपति दीदी बनेंगी सक्षम

राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका के लिए आवंटन 15,047 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के 14,129.17 करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग छह प्रतिशत अधिक है। योजना के लिए संशोधित अनुमान भी 14,129.17 करोड़ रुपये है। चौहान ने कहा, यह बजट गरीबों के लिए नई जिंदगी लेकर आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। यह बजट तीन करोड़ 'लखपति दीदियों' को सक्षम बनाने में भी मदद करेगा, जो प्रति वर्ष एक लाख रुपये कमाएंगी। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

गांवों के लिए बनेगी सहकारिता नीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : 'सहकार से समृद्धि' को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र को व्यवस्थित करने और ग्रामीण क्षेत्रों का चौतरफा विकास के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने जा रही है। आम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसके सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। मसौदा तैयार किया जा रहा है। राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभिन्न सहकारी समितियों के साथ अन्य हितधारकों से विमर्श के बाद जल्द ही नई नीति की घोषणा होगी।

सरकार की योजना सभी जिलों में सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना की है। अभी देश में दो लाख पंचायतों में एक भी सहकारी संस्था नहीं है। दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बनानी है। अभी इनकी संख्या लगभग एक लाख है। अगले पांच वर्ष में दो लाख पैक्स का निर्माण करना है। केंद्र में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय के गठन के बाद नई नीति का मसौदा तैयार करने को समिति का गठन दो सितंबर 2022 को अमित शाह के नेतृत्व में किया गया था।

सब्जियों के दाम पर नियंत्रण के लिए बनाए जाएंगे क्लस्टर

- क्लस्टर ऐसी जगहों के नजदीक होंगे, जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं
- टमाटर एवं प्याज जैसी जल्द खराब होने वाली सब्जियों के संग्रहण व भंडारण की व्यवस्था करेगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जलवायु परिवर्तन एवं मौसम की दुश्वारियों के बीच सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को राहत दिलाने की चिंता भी आम बजट में दिखी है। सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के बीच सामंजस्य के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ये क्लस्टर वैसी जगहों के नजदीक होंगे, जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता रहते हैं। मतलब जहां अधिक खपत होगी उसी के आसपास सब्जियों की खेती का प्रबंध किया जाएगा।

सरकार को यह निर्णय हाल के वर्षों में सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि के चलते लेना पड़ा है। देखा गया है कि मौसमी सब्जियों का उत्पादन कम नहीं होता है। फिर भी आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के चलते देश के एक हिस्से में अचानक कुछ सब्जियों की कमी हो जाती है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने टमाटर एवं प्याज जैसी जल्द खराब होने वाली सब्जियों के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन की व्यवस्था करेगी।

झींगा पालन को बढ़ावा: बजट में जलकृषि की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत झींगा पालन के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर का नेटवर्क बनाया जाएगा।

बजट बोल

यह बजट कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वरदान है। यह किसानों, महिलाओं, युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के जीवन में 'क्रांतिकारी बदलाव' लाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसानों के सशक्तीकरण वाला वजट है।

- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

बजट में बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। यह बजट भारत के लिए नहीं, बल्कि केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए पेश किया गया बजट है। यह बजट पक्षपाती और गरीब विरोधी है। बजट राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और जनविरोधी है.

- ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री बंगाल

यह बजट महिलाओं की बढ़ती भूमिका की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, कौशल कार्यक्रमों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन आर्थिक समावेशिता बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

-जयश्री दास वर्मा, प्रेसिडेंट, फिक्की एफएलओ

बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत का अब भी इंतजार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस बार के बजट में एक घोषणा जो तय मानी जा रही थी वही नहीं हुई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाले तीन दवाओं को आयात कर से पूरी तरह से मुक्त कर कैंसर मरीजों को राहत जरूर दी। लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये तक सालाना मुफ्त की इलाज की सुविधा देने का वायदा भी बजट का हिस्सा नहीं बन सका। इसी तरह से बच्चियों को सरवाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान को हरी झंडी की मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके लिए भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के शामिल नहीं किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी हैरान हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान भारत में शामिल किए जाने और सरवाइकल कैंसर के टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने के बजट में एलान की पूरी उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे के कारण को बताने में अपनी असमर्थता जताई। एसोसिएशन आफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स आफ इंडिया के महानिदेशक डाक्टर गिरिधर ज्ञानी ने भी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत में शामिल नहीं किए जाने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत इलाज पर खर्च की सीमा में संशोधन की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन बजट में इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

वित्त मंत्री ने कैंसर की तीन दवाइयों को आयात कर से मुक्त करने के अलावा एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स बेसिक कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन का एलान किया। इसका उद्देश्य एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स के देश के भीतर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य बजट में सबसे अधिक बढ़ोतरी बायोटेक्नोलाजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हुई है। इसके लिए बजट 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का बजट भी बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये से अब 90 करोड़ रुपये किया गया है। लेकिन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का बजट 200 करोड़ रुपये पर स्थिर है।

70 साल से अधिक के बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ टला

- सरवाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की बात थमने से अधिकारी भी हैरान

कृषि : कल, आज और कल...

जेएनएन, नई दिल्ली : भारत में कृषि का इतिहास बहुत पुराना है। यह लगभग 1,100 वर्षों की अवधि में विकसित हुआ है। हमारे धर्मग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि हम सदैव किसान प्रधान या कृषि प्रधान देश रहे हैं। भारत वर्ष 1950 तक भुखमरी के दौर में था। 1950 से 70 तक हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी। 1970-2000 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गई। यानी हमारे देश में आबादी की तुलना में पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। वर्ष 2000 के बाद से खाद्य सुरक्षा की स्थिति में गए। आज भारत दूसरों को अनाज निर्यात व वितरित करने की स्थिति में है। निर्भरता से आत्मनिर्भर होने के सफर को कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है :

नागपुर के पास हिंगना गांव में एक किसान कपास के खेत में जुताई करते हुए ● प्रेट्र

जरूरत: चार गुना उत्पादन वृद्धि

एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक हमारी आबादी 160 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन 314 मिलियन टन है। हमें हर साल चार गुना वृद्धि करनी होगी, तभी वर्ष 2050 तक अपनी 400 मिलियन टन की आवश्यकता पूरी कर पाएंगे।

मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमारे लगभग 26 प्रतिशत बागवानी उत्पादों को फसल के बाद नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि हम उस 26 प्रतिशत को बचाने में सफल हो गए तो हमारा उत्पादन प्रभावी रूप से 26 प्रतिशत और बढ़ सकता है।

पानी में 25 प्रतिशत और उर्वरक के उपयोग में 20 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य

कृषि वास्तव में युवाओं के लिए लाभकारी हो सकती है। भारत में कई कृषि-आधारित स्टार्ट-अप लांच किए गए हैं और काफी प्रगति कर रहे हैं। यह युवाओं के लिए कृषि में रोजगार खोजने और क्षेत्र में सुधार करने का एक बड़ा अवसर है। सरकार का इरादा आय को दोगुना करने का है। वे उर्वरकों के उपयोग को 20 प्रतिशत तक कम करना चाहते हैं। साथ ही पानी के उपयोग में 25 प्रतिशत कमी लाना होगी। इसके जरिये मीथेन उत्सर्जन में लगभग 45 प्रतिशत कमी का लक्ष्य है।

भारत वैश्विक स्तर पर कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा

7.5% हिस्सा है वैश्विक कृषि उत्पादन में भारत का

18% योगदान है कृषि उत्पादों का भारत के जीडीपी में

निर्यात: भारत कृषि उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। मध्य पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप प्रमुख देश है, जहां उत्पाद निर्यात होते हैं

50% रोजगार कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्यबल को मिलता है भारत में

4% उपलब्धता है मीठे पानी का भारत में वैश्विक स्तर पर

23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं किसानों को (19 दिसंबर 2023 तक)

आदिवासियों के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की। साथ ही संबंधित मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा। सरकार ने बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 6,399 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति के लिए बजटीय आवंटन 2023-24 के 230 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर 2024-25 में 165 करोड़ रुपये हो गया है।

- आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है मुख्य उद्देश्य

5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा, 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल किया जाएगा

बजट आवंटन में वृद्धि

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आवंटन 2023-24 के 2,959.43 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 6,611.69 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के लिए वित्तीय सहायता 2023-24 के 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और रोजगार-सह-आय सृजन जैसे क्षेत्रों में अंतराल को पाटने के लिए अधिसूचित एसटी आबादी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन प्रदान किया जाता है।

बजटीय प्रविधानों से पूरी की बिहार और आंध्र प्रदेश की मांग

प्रथम पृष्ठ से आगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के प्रमुख सहयोगी दल जदयू और तेदेपा के राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास तौर पर घोषणाएं की हैं। दोनों दल अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे, जिसे एक तरह से बजटीय प्रविधानों के जरिये पूरा किया गया है। बिहार में एक्सप्रेसवे, बिजली परियोजना, हवाई अड्डों के निर्माण जैसे ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए, केंद्र सरकार की तरफ से कुल 60 हजार करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा है, जबकि आंध्र प्रदेश को केंद्र की मदद से 15 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिलाई जाएगी। इस अतिरिक्त बोझ के बावजूद सरकार के खजाने की स्थिति बेहद मजबूत है और राजकोषीय घाटे को चालू वित्त वर्ष के दौरान 4.9 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत पर लगाने को लेकर वित्त मंत्री पूरी तरह से आशान्वित हैं। आम बजट 2024-25 के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये और व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि बाजार से उधारी 11.63 लाख करोड़ रुपये का है। वहीं बिहार को बजट में प्रविधान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेषराज्य से कम कुछ मंजूर नहीं है। वहीं भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र बिहार के लिए खजाना खोल दिया है।

****

समृद्ध शहर

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग बढ़ाने पर दिया है जोर

30 लाख आबादी वाले 14 शहरों के विकास को लगेंगे पंख

तमाम असुविधाओं से घिरे शहरों को फिर से विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा

3 करोड़ नए घर बनाने का एलान कर चुकी है नरेन्द्र मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी की पहली कैबिनेट बैठक में

- शहरों को विकास के केंद्र बनाने का लक्ष्य उनमें आर्थिक और ट्रांजिट प्लानिंग के जरिये किया जाएगा पूरा

169 शहरों में 10 हजार पीएम ई-बस चलाने की योजना लाई गई थी पिछले वर्ष शहरी परिवहन के लिए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: शहरों को विकास का इंजन होना चाहिए, इस सोच के साथ 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार तमाम असुविधाओं से घिरे शहरों को फिर से विकसित करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी बनाने जा रही है। इस योजना पर क्रियान्वयन और पैसे का इंतजाम करने के तौर-तरीके बाद में तय किए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के साथ ही इस योजना के दायरे में जो शहर आ सकते हैं, उनमें हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, कोझिकोड, लखनऊ, त्रिशूर, कोच्चि, इंदौर, कानपुर, नागपुर और कोयबंटूर शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में शहरी विकास से जुड़ी कुछ अहम घोषणाएं कीं, लेकिन सुधार की ज्यादातर अपेक्षा राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई। सौ शहरों में संचालित स्मार्ट सिटी मिशन लगभग पूरा हो जाने के बाद शहरों में देखे जा सकने वाले सुधारों का अभाव महसूस किया जा रहा है। इस लिहाज से अपेक्षा थी कि शहरी विकास की कोई नई योजना सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि शहरी परिवहन के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई।

शहरी परिवहन के लिए पिछले वर्ष 169 शहरों में 10 हजार पीएम ई-बस चलाने की योजना लाई गई थी, जिसकी अभी टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार शहरों के विकास के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। शहरों को विकास के केंद्र बनाने का लक्ष्य उनमें आर्थिक और ट्रांजिट प्लानिंग के जरिये पूरा किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि टाउन प्लानिंग योजनाओं के सहारे शहरों के आसपास के इलाके को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा। समस्या यह है कि टाउन प्लानिंग राज्यों के एजेंडे में ही नजर नहीं आता। शहरी सुधार से संबंधित एक रिपोर्ट के मुताबिक 75 प्रतिशत से अधिक शहरों में कोई टाउन प्लानर ही नहीं है।

शहरों में आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की सहायता का एलान

वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरों में आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2.2 लाख करोड़ रुपये की सहायता देने का भी एलान किया। उन्होंने कहा, 'पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।' मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में पहली कैबिनेट बैठक में पीएम आवास योजना के तहत शहरों और गांवों में तीन करोड़ नए घर बनाने का एलान कर चुकी है। इसके तहत गांवों में दो करोड़ और शहरों में एक करोड़ घर बनने हैं। शहरों में घर बनाने के लिए केंद्र सरकार लोन पर ब्याज में सब्सिडी देगी, जिससे लोगों को किफायती कर्ज मिल सके।

पारदर्शी रेंटल हाउसिंग बाजार

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि शहरों में एक प्रभावशाली और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट तैयार किया जाएगा। बड़ी संख्या में शहरी आबादी किराये के ठिकानों पर निर्भर है और इसके लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले माडल किरायेदारी कानून की पहल की थी। सीतारमण ने कहा कि इसमें पारदर्शिता के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। ऐसा होने पर किराये के लिए घरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। शहरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी माडल से छात्रावास जैसी सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए केंद्र फंड देगा।

शहरों में सौ साप्ताहिक बाजार

शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही रेहड़ी-पटरी के तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए चुनिंदा शहरों में सौ साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई है। रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए कर्ज उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना का केंद्र संचालन कर रहा है। साप्ताहिक बाजार भी उसी कड़ी का हिस्सा होंगे।

सौ शहरों में पेयजल, स्वच्छता और सीवेज ट्रीटमेंट की है योजना

- उपचारित जल का सिंचाई के लिए किया जाएगा इस्तेमाल
- आसपास के इलाकों के टैंकों को भरने में भी होगा प्रयोग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अमृत परियोजना पर क्रियान्वयन के बीच केंद्र सरकार ने शहरों में स्वच्छता और पेयजल की समुचित आपूर्ति पर नए सिरे से ध्यान देने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों का साथ जरूरी है। बजट में इन दोनों अहम क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, इस अपेक्षा के साथ कि राज्य सरकारें इनके प्रति गंभीरता दिखाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र, राज्य और कर्ज देने वाले बैंक मिलकर सौ बड़े शहरों में पेयजल की आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई परियोजनाओं के जरिये काम करेंगे।

खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकलेगा, उसका इस्तेमाल सिंचाई के काम में किया जाएगा। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में स्थित टैंकों को भरने में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। शहरी विकास के संदर्भ में एक अन्य घोषणा में सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को इसके लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे स्टैंप ड्यूटी कम करें, खासकर संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं के लिए इसे और कम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार राज्यों के लिए इसे शहरी सुधार की अहम कसौटी बना सकती है यानी यह भी उन्हें सहायता देने की एक शर्त हो सकती है।

बजट बोल

'यह बजट समावेशी विकास, सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह दूरदर्शी बजट तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही दीर्घकालिक समृद्धि के लिए मजबूत ढांचा भी तैयार करेगा।

- **जेपी नड्डा**, भाजपा अध्यक्ष

'यह जानकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस का लोकसभा 2024 का घोषणापत्र पढ़ा है। इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लिखित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन को अपना लिया है।'-

-**पी. चिदंबरम**, पूर्व वित्त मंत्री

कैंसर की तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर सरकार ने बहुत सराहनीय फैसला लिया है। ये दवाएं महंगी थी। अब यह आशा भी बढ़ने लगी है कि कैंसर के इलाज से संबंधित मशीनों पर भी ड्यूटी कम होगी।'

पीएन अरोड़ा, चेयरमैन, यशोदा सुपरस्पेशलिटी हास्पिटल

इन्फ्रा विकास में निरंतरता की झलक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार की नीतिगत निरंतरता की झलक बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी नजर आई। अंतरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च का एलान किया गया था, जिसे मंगलवार को प्रस्तुत बजट में भी कायम रखा गया। वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास को अपने नौ में से सातवां फोकस बताया। राज्यों को 1.50 लाख करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिना ब्याज के देने की घोषणा की है।

पिछले कुछ वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में किए गए निवेश का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए फरवरी में रिकार्ड आवंटन किया गया था। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह कहा भी कि पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में किए गए कार्य का अर्थव्यवस्था पर कई स्तरों पर सकारात्मक असर पड़ा है। पूंजीगत खर्च के लिए किया गया 11.11 लाख करोड़ का आवंटन जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके लिए सही नीतियों और नियम-कायदे बनाने का इरादा व्यक्त किया गया है। सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही राय व्यक्त की गई थी।

11.11 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है

- सड़क परिवहन का आवंटन आठ हजार करोड़ रुपये बढ़ा
- रेलवे और उड्डयन क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी की गई है। मंत्रालय को 2,78,000 करोड़ रुपये मिले हैं और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा एनएचएआइ का है, जिसके खाते में 1.68 लाख करोड़ रुपये डाले गए हैं। आश्चर्यजनक रूप से रेलवे के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। रेलवे का बजट इस बार 2.55 लाख करोड़ है, जो पिछली बार 2.43 करोड़ ही था। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि बजट में इस बार अन्य मदों समेत रेलवे के लिए कुल 2,62,200 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। रेल मंत्री के अनुसार बजट में मिली अधिकांश धनराशि का व्यय ट्रेनों की सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में किया जाएगा। इसके साथ ही स्वचालित रेल रक्षा प्रणाली 'कवच' के इंस्टालेशन पर कार्य होगा। उड्डयन मंत्रालय के लिए पिछली बार से कम राशि दी गई है। उड्डन मंत्रालय को इस बार 2357 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि पिछली बार यह राशि 2922 करोड़ रुपये थी। क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत 502 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 348 करोड़ कम हैं। रेलवे की तरह उड्डयन मंत्रालय के संदर्भ में भी कोई बड़ा एलान नहीं किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले 2.19 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ रुपये आवंटित हुए है, जिसमें से 1,43,275.90 करोड़ सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआइएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों को मिलेंगे। अंतरिम बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय को 2,02,868.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

सीआरपीएफ को जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के विरुद्ध अभियानों, मध्य और पूर्वी भारत में नक्सलियों तथा पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के विरुद्ध अभियानों के लिए तैनात किया जाता है। बीएसएफ देश की सीमाओं की रक्षा करती है। सीआइएसएफ परमाणु संयंत्रों, हवाईअड्डों और मेट्रो नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती है। आइटीबीपी चीन-भारत सीमा की रक्षा करती है। एसएसबी भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करती है, जबकि असम राइफल्स म्यांमार के साथ भारत की सीमा की रक्षा करती है। सीबीआइ को 951.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर को आवंटित किए गए 42,277.74 करोड़ रुपये

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। बजट में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 5,985.82 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5,862.62 करोड़ रुपये, लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 2,648.97 करोड़ रुपये तथा लक्षद्वीप को 1,490.10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट में जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए 1,309.46 करोड़ रुपये (2023-24 में 578.29 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को 1,606.95 करोड़ रुपये (2023-24 में 1,666.38 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।

- खुफिया ब्यूरो (आइबी) को 3,823.83 करोड़ रुपये, दिल्ली पुलिस को 11,180.33 करोड़ रुपये, स्पेशल प्रोटक्शन ग्रुप (एसपीसी) को 506.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आइबी भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है, दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा करती है और एसपीजी प्रधानमंत्री को सुरक्षा करती है।
- बार्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रबंधन के लिए 3,756.51 करोड़ रुपये और पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 3,152.36 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 1,105 करोड़ रुपये, विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं और गृह मंत्रालय की योजनाओं के लिए 9,305.43 करोड़ रुपये, सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 3,199.62 करोड़ रुपये और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए 1,050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल को 1,248.91 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सरकार के आतिथ्य और मनोरंजन पर खर्च किया जाएगा। आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास तथा राज्य सरकारों को अनुदान आदि के लिए 6,458 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- सेफ सिटी परियोजना को 214.44 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विवि को 80 करोड़ तथा राष्ट्रीय रक्षा विविय को 90 करोड़ रुपये आवंटित।
- केंद्रीय बजट में सीबीआइ को 951.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान में सीबीआइ को अपने खर्चों के लिए 968.86 करोड़ रुपये मिले थे।

अर्धसैनिक बलों को किया गया बजट आवंटन			
	सीआरपीएफ 31,543.20 करोड़ रुपये	बीएसएफ: 25,472.44 करोड़ रुपये	सीआइएसएफ: 14,331.89 करोड़ रुपये
	आइटीबीपी: 8,634.21 करोड़ रुपये	एसएसबी: 8,881.81 करोड़ रुपये	असम राइफल्स: 7,428.33 करोड़ रुपये

जमीन से लेकर आसमान तक मजबूत होता विकास का बुनियादी ढांचा

जेएनएन, नई दिल्ली: पिछले 10 वर्षों में देश का बुनियादी ढांचा इस कदर मजबूत हुआ है कि विकास की गाड़ी इस पर सरपट दौड़ लगा सके। सड़कों के निर्माण को ही गति नहीं मिली है, टोल प्लाजा पर लगने वाला समय भी कम हुआ है। रेलवे में निवेश बढ़ा है। हवाई यात्रियों के लिए सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में ही 84 लाख से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है।

सड़कों के निर्माण को गति मिली और टोल प्लाजा पर लगने वाला समय हुआ कम

रेलवे में निवेश बढ़ा और हवाई यात्रियों के लिए सुविधाओं में लगातार हो रहा है इजाफा

ऊर्जा (नवीकरणीय)
मार्च 2024 के अंततक 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी।

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014 से 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ का नया निवेश हुआ।

नागरिक उड्डयन: बढ़ेंगी सुविधाएं

21 हवाई अड्डों पर नये टर्मिनल भवन बनाये जायेंगे इसी वित्तवर्ष में

6 करोड़, 20 लाख यात्रियों के लिए प्रति वर्ष यात्री प्रबंधन क्षमता में वृद्धि

नागरिक विमानन: लंबी छलांग
लाजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में देश की रैंक वर्ष 2014 में 44 के मुकाबले सुधरकर वर्ष 2023 में 22 हो गई।

ऊर्जा (बिजली)
- भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50 प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत 48.42 बिलियन किलोवाट हुई और बिजली बिलों में 9,335 करोड़ की वार्षिक बचत हुई।

सड़क: तेज होती रफ्तार
3 गुना तक बढ़ गई राष्ट्रीय राज मार्ग निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2024 के बीच

16 गुना कम हो गया टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय। वर्ष 2014-24 के दौरान टोल डिजिटलीकरण से यह संभव हुआ।

रेलवे परिवहन: बढ़ रहा पूंजीगत व्यय
77% की वृद्ध वित्त वर्ष 20 से 24 के बीच हुई है रेलवे पर पूंजीगत व्यय में। नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण में महत्वपूर्ण निवेश किया गया।

शहरी क्षेत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना: 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई और 84 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो गया।

अमृतमिशन: 83,327 करोड़ रुपये की लागत वाली 5,999 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। 51,434 करोड़ रुपये लागत वाली 5,304 परियोजनाएं पूरी हुईं।

मेट्रोरेल/आरआरटीएस: 945 किलोमीटर लाइन पर सेवा चालू है। 27 शहरों में 939 किलोमीटर लाइन निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 24 में 86 किलोमीटर और चालू हो जाएंगी।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी: 63.07 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय इकाइयों का निर्माण किया गया। 6.37 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए गए।

इस वर्ष भी जनगणना की संभावना नहीं, सिर्फ 1309 करोड़ आवंटित

3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे 2021-22 में

578 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे 2023-24 में

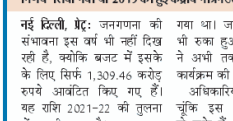

12 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर

8,754.23 करोड़ रुपये की लागत से 2021 की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था 2019 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में

नई दिल्ली, प्रेट्र: जनगणना की संभावना इस वर्ष भी नहीं दिख रही है, क्योंकि बजट में इसके के लिए सिर्फ 1,309.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि 2021-22 की तुलना में काफी कम है। उस समय जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में 8,754.23 करोड़ रुपये की लागत से 2021 की जनगणना कराने और 3,941.35 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गौरतलब है कि जनगणना और एनपीआर का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जनगणना कार्य अब भी रुका हुआ है और सरकार ने अभी तक इसके लिए नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

अधिकारियों ने बताया कि चूंकि इस वर्ष आम चुनाव हो चुके हैं, इसलिए 2024 में जनगणना का कार्य नहीं हो सकेगा। बजट 2024-25 के अनुसार, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए 1,309.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

2023-24 में 578.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है। यह कार्य जब भी होगा तो यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर प्रदान करेगी।

निकायों के सुधरे बिना नहीं संवरेंगे शहर

मनीष तिवारी • जागरण

- 1,150 करोड़ डिजिटल अर्बन मिशन के लिए
- विशेषज्ञों की राय-पहले निकायों को जवाबदेह बनाने की जरूरत

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी विकास को उन नौ क्षेत्रों में गिनाया, जो देश की प्रगति और आर्थिक विकास का स्तंभ साबित होने जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई ठोस खाका, खासकर बुनियादी सुधार की बातें कम से कम उनके बजट भाषण में नजर नहीं आईं। उन्होंने शहरों में लैंड रिकार्ड यानी जमीन के दस्तावेज के डिजिटाइजेशन का अवश्य एलान किया। जीआइएस मैपिंग के साथ यह रिकार्ड शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है।

शहरी मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार लैंड रिकार्ड का डिजिटाइजेशन निकायों को संपत्तियों के रिकार्ड रखने में सहायता करेगा, पर सवाल यह है कि राज्य सरकारें क्या निकायों को यह अवसर और अधिकार देंगी कि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला कर सकें। क्या वे शहरों के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने के लिए तैयार हैं।

शहरों के ढांचे पर निगाह रखने वाले संगठन जनाग्रह के पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट प्रमुख प्रभात कुमार कहते हैं कि शहरों के विकास के लिए शून्य से सोचना होगा। शहरों के विकास के लिए साहसिक परिकल्पना की जरूरत है।

शहरों का विकास राज्यों का विषय है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, खासकर अपने निकायों की जवाबदेही और उनके उत्तरदायित्व को लेकर। केंद्र सरकार ने 10 वर्ष में शहरी विकास के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन गौर कीजिए यह अब भी कुल बजट का 1.7 प्रतिशत ही है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2030 में शहरों में रहने वाली आबादी 40 प्रतिशत से अधिक होगी। यह आबादी बेहतर माहौल में जीने की हकदार है। इस बजट में ही शहरी विकास के लिए कुल आवंटन का 67 प्रतिशत केवल दो मदों के लिए है-पीएम आवास योजना और मेट्रो ट्रांजिट। जाहिर है, शहरी विकास के दूसरे विषय प्राथमिकता में छूट जाते हैं। केंद्र सरकार इस पर जोर दे रही है कि राज्य शहरी सुधारों को अपनाएं। उन्हें सहायता भी इसी कसौटी पर निर्भर की गई है।

जमीन के रिकार्ड के डिजिटाइजेशन के बिना वे न तो राजस्व अर्जित कर पा रहे हैं और न ही नागरिकों को सुविधा दे पा रहे हैं। शायद अब वे 1,150 करोड़ रुपये राष्ट्रीय अर्बन डिजिटल मिशन के सहारे आगे बढ़ें। उन्हें स्टैंप ड्यूटी को भी तार्किक बनाना होगा।

शहरी विकास के लिए प्रमुख खर्च

8,000 करोड़ रुपये अमृत योजना

2,400 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी मिशन

1,300 करोड़ रुपये पीएम ई बस सेवा

5,000 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन

30,170 करोड़ रुपये पीएम आवास योजना

24,931 करोड़ मेट्रो प्रोजेक्ट

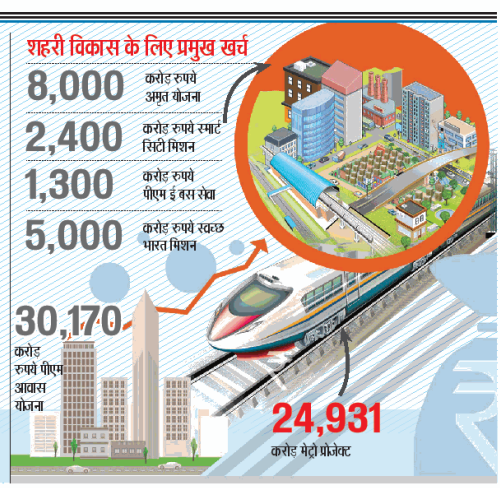

****

2013-14 में रक्षा बजट 2.03 लाख करोड़ था, जो अब 6.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी तीन गुना।

विकास से मिली उद्योगों के उत्पाद को रफ्तार

उद्योगों को मिल रही रफ्तार देश में हो रहे विकास का आईना कही जा सकती है। चाहे वह इलेक्ट्रानिक उत्पाद, कोयला उत्पादन की बात हो, इन सेक्टर ने हर मोर्चे पर बाजी मारी है। दवा उद्योग की बात करें तो भारत का दवा बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है।

घरेलू खपत के रूप में कोयला उत्पादन में सुधार

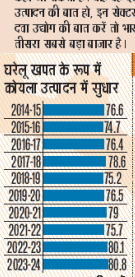

वर्ष	सुधार (प्रतिशत में)
2014-15	76.6
2015-16	74.7
2016-17	76.4
2017-18	78.6
2018-19	75.2
2019-20	76.5
2020-21	79
2021-22	75.7
2022-23	80.1
2023-24	80.8

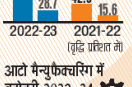

इलेक्ट्रानिक उत्पाद और निर्यात में वृद्धि

	निर्यात	उत्पादन
2022-23	62.5	28.7
2021-22	42.9	15.6

(वृद्धि प्रतिशत में)

आटो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी 2023-24

कार	7.1
मालवाहक	16
दोपहिया	10.3

(वृद्धि प्रतिशत में)

विश्व की फार्मेसी

- 2019-20 और 2020-21 दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बिक्री कारोबार का पांच प्रतिशत
- भारत का दवा बाजार मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा
- शीर्ष 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से आठ भारत में स्थित
- सभी जिलों में 12,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए देश भर में

पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस

सरकार का एक प्लान है जो पेशेवरों, सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा के फायदे देता है।

1.28 लाख करोड़ से अधिक का निवेश

8.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष)

10.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन/बिक्री

फलते फूलते स्टार्ट अप और नवोन्मेषी इको सिस्टम

- 2023-24 के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट आफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलाजी में अधिक डीपीआइआइ, टी मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप होंगे।
- स्वीकृत पेटेंटों की संख्या वित वर्ष 2014-2015 में 5978 में 17 गुना बढ़कर 2023-24 में 1,03,057 हो गई है।

100 शहरों में प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क

राजीव कुमार ● जागरण

- ऐसे पार्कों में होती हैं किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़ी सभी सुविधाएं
- सौ पार्कों से होगा 100 प्रकार की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन

12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत

नई दिल्ली: मैन्युफैक्चरिंग देश के विकास और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। औद्योगिक क्लस्टर, जहां पर एक ही जगह किसी आइटम के निर्माण से जुड़ी तमाम चीजें उपलब्ध होती हैं, के विकास से मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाती है और उसकी लागत भी कम हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में देश के 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। केंद्र, राज्य और निजी सेक्टर की आपसी सहभागिता से प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़ी सभी सुविधाएं होंगी।

प्लग एंड प्ले सुविधा वाले पार्क में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी तमाम सुविधाएं जैसे भवन, बिजली, पानी, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार माल को बाजार तक या पोर्ट तक ले जाने की सुविधा पहले से मौजूद होती है। उद्यमी को उस औद्योगिक पार्क में जाकर सिर्फ उत्पादन शुरू करना होता है। मुख्य रूप से नए उद्यमियों को मैन्युफैक्चरिंग के प्रति आकर्षित करने के लिए प्लग एंड प्ले माडल लाया जाता है। चीन व अन्य देशों में वर्षों से प्लग एंड प्ले माडल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहां कई जगहों पर उद्यमी को मशीन तक लगाने की जरूरत नहीं होती। प्लग एंड प्ले माडल के तहत उद्यमी अपनी इच्छानुसार एक निश्चित अवधि तक औद्योगिक पार्क या क्लस्टर में निर्माण करते हैं। कारोबार बड़ा होने पर वे किसी अन्य जगह अपनी यूनिट लगा लेते हैं। भारत में भी उद्यमी काफी समय से प्लग एंड प्ले सुविधा की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले सुविधा वाले औद्योगिक क्लस्टर या पार्क के विकसित होने से कम से कम 100 प्रकार की वस्तुओं (आइटम) का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। एक औद्योगिक पार्क में एक आइटम से जुड़े उत्पादन की तमाम सुविधाएं दी जा सकती हैं। चीन की तरह किसी वस्तु की बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता भारत में नहीं होने से कई बार यूरोप व अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहकर भी भारत को आर्डर नहीं दे पातीं। प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्कों का पूरा खाका उद्योग विभाग तैयार करेगा।

मैन्युफैक्चरिंग के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए बजट में औद्योगिक पार्क में ही श्रमिकों के रहने के लिए आवास निर्माण के लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। श्रमिकों के लिए कम किराए वाले आवास निजी-सरकारी सहभागिता माडल पर तैयार होंगे।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि देश के किन हिस्सों में इन पार्कों का निर्माण होगा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इंडस्ट्रियल कोरिडोर का निर्माण चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार एमएसएमई को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे सकती थी ताकि वे नए निवेश के लिए प्रोत्साहित होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ लेने के लिए 100 करोड़ से अधिक के निवेश की जरूरत होती है। इसलिए एमएसएमई इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

अंतिम मील कनेक्टिविटी को सीमा सड़क संगठन को 6,500 करोड़ रुपये आवंटित

सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ-साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में शामिल एजेंसियां बजट आवंटित करने में प्राथमिकता में हैं। इसके तहत पूंजी व्यय के लिए सीमा सड़क संगठन को 6,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ लद्दाख में 13,700 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरफील्ड के विकास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत की दक्षिणी पंचायत के लिए स्थायी पुल कनेक्टिविटी, हिमाचल प्रदेश में 4.1 किमी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकू ला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग और कई अन्य परियोजनाओं को भी इस आवंटन का फायदा मिलेगा।

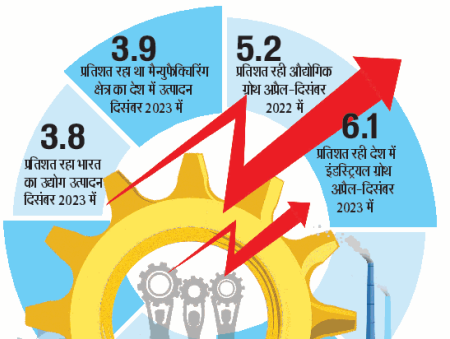

रक्षा क्षेत्र का आवंटन बढ़ाया पर बजट भाषण में जिक्र नहीं

संजय मिश्र ● जागरण

6.22 लाख करोड़ का रक्षा बजट, देश के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत

1.72 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च, वेतन में 30 तो पेंशन पर 22 प्रतिशत

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली : केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को करीब 6.22 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है जो अन्य सभी मंत्रालयों की तुलना में सबसे अधिक है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा जहां वेतन-पेंशन पर खर्च होगा, वहीं पूंजीगत खर्च के लिए करीब 1,72,000 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित हुआ है। इसमें से 1,05,518 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वदेशी रक्षा कंपनियों से रक्षा उत्पादों की खरीद पर खर्च की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पूंजीगत खर्च में इस विशेष कोटे का उद्देश्य देश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट आवंटन में बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा भी कि पूंजीगत व्यय तीनों सैन्य बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा तथा रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' को और गति मिलेगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने करीब डेढ़ घंटे के भाषण के दौरान रक्षा बजट के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि बजटीय आवंटन के ब्योरे में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय के आवंटन की जानकारियां दी गईं। पूर्ण बजट में चालू वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल 6,21,940.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कुल बजटीय अनुमान का लगभग 12.90 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन की तुलना में यह लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक है और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक है। रक्षा बजट के कुल आवंटन में 27.66 प्रतिशत पूंजीगत खर्च, जीविका और सैन्य परिचालन तैयारियों पर व्यय के लिए 14.82 प्रतिशत, वेतन-भत्ते के लिए 30.66 प्रतिशत, पेंशन 22.70 प्रतिशत तथा रक्षा मंत्रालय के तहत नागरिक संगठनों के लिए 4.17 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। रक्षा पेंशन के लिए कुल आवंटन 1,41,205 करोड़ रुपये है जो लगभग 32 लाख पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन पर खर्च किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय बजट से प्रसन्न नजर आया और उसके अनुसार बजट आवंटन में पूंजीगत व्यय की राशि से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। 1.72 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत आवंटन वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 9.40 प्रतिशत अधिक है। इस आवंटन का मकसद चालू और अगले वित्त वर्ष में बड़े रक्षा खरीद के जरिये महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण गैप को भरा जाएगा। साथ ही सेनाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, घातक हथियारों, लड़ाकू विमानों, पोतों, पनडुब्बियों, प्लेटफार्मों, मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोनों, विशेषज्ञ वाहनों आदि से लैस करने पर भी यह राशि खर्च होगी। सेनाओं की परिचालन तत्परता को अधिक आवंटन का मकसद सैन्य बलों को हर समय युद्ध के लिए तैयार रखना है।

सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकार्ड : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेशकर पूर्व पीएम मोरारजी देसाई का रिकार्ड तोड़ दिया। तस्वीर में वर्ष 2019, 2020, 2021 (बाएं से दाएं ऊपर), 2022, 2023, अंतरिम बजट 2024 (बाएं से दाएं नीचे) तथा बिल्कुल दाएं 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करने जातीं सीतारमण। प्रेट्र

दुर्लभ खनिजों का उत्पादन बढ़ाने को मिशन लांच करेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: तांबा और लिथियम जैसे दुर्लभ खनिजों का उत्पादन बढ़ाने, रीसाइक्लिंग और विदेश में ऐसे खनिजों के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार एक मिशन लांच करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जल्द आफशोर (समुद्र) खनन के लिए पहले दौर की नीलामी लांच करेगी।

तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिज तेजी से बढ़ी स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए आवश्यक घटक हैं। विंड टर्बाइन और बिजली नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों में इनका प्रयोग होता है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की गति बढ़ने के साथ इन खनिजों की मांग भी बढ़ रही है। मिशन में टेक्नोलाजी विकास, प्रशिक्षित श्रमबल, उत्पादकों के दायित्वों का विस्तार, फ्रेमवर्क और अनुकूल वित्त प्रणाली का गठन होगा। भारत अभी दुर्लभ खनिजों के आयात पर निर्भर है। पिछले वर्ष सरकार ने 30 दुर्लभ खनिजों की सूची जारी की थी।

ऊर्जा सुरक्षा : आत्मनिर्भरता पर जोर

- पारंपरिक ऊर्जा की जगह अपारंपरिक ऊर्जा अपनाने पर आएगी वृहद नीति
- देश में लगेंगे माड्यूलर व छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र
- पंप्ड स्टोरेज विद्युत परियोजनाओं पर बनाई जाएगी नई नीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : विकसित भारत बनने के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी शर्त है, लेकिन इसके लिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। सौर और पवन ऊर्जा को लेकर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है। अब फोकस परमाणु ऊर्जा और पंप्ड स्टोरेज जैसे उन क्षेत्रों पर है, जहां भारत बहुत ज्यादा संभावनाएं देख रहा है। आम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा सुरक्षा को इस बजट की नौ प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक दर्शाया। उन्होंने देश में ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की घोषणा की है, जो यह बताएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का महत्व स्थापित होगा। यह दस्तावेज ऊर्जा सेक्टर में रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी हल बताएगा।

वित्त मंत्री ने बजटीय प्रस्ताव में निकेल, कोबाल्ट, कापर, लिथियम जैसे कुछ उत्पादों के आयात पर शुल्क घटाने का भी एलान किया है। इन उत्पादों का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा व दूसरे ऊर्जा क्षेत्रों में होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि परमाणु उर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले 25 आवश्यक धातुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दो उत्पादों पर मूल आयात शुल्क (बीसीडी) को कम कर दिया गया है। वैसे इस कदम का फायदा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और बैट्री बनाने वाले सेक्टर को भी होगा।

हाल के वर्षों में कुछ देशों ने छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सफलता हासिल की है। वित्त मंत्री ने देश में छोटे रिएक्टर की स्थापना करने और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने की बात कही है। इस सेक्टर में शोध व अनुसंधान के लिए केंद्र की तरफ से फंड दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि बहुत ही प्रभावशाली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाने की स्वदेशी प्रौद्योगिकी भारत ने तैयार कर ली है। पहली बार इसके तहत 800 मेगावाट क्षमता का एक प्लांट सरकारी क्षेत्र की एनटीपीसी और बीएचईएल मिलकर स्थापित करेंगी। इसके लिए आवश्यक राशि का इंतजाम सरकार की तरफ से होगा। यह पूरी तरह से भारतीय उत्पादों व प्रौद्योगिकी से तैयार बिजली संयंत्र होंगे, जो कोयला आधारित होते हुए भी पर्यावरण को बहुत कम क्षति पहुंचाते हैं।

बजट बोल

केंद्र सरकार यह बजट "विकासोन्मुखी" है। यह पूर्ण रूप से सबका साथ, सबका विकास की बात करता है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में बजट में की गई घोषणाओं से पूर्वी भारत देश का "आर्थिक केंद्र" बनकर उभरेगा।
- किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री

वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से प्रेरणा ली है। इंटर्नशिप प्रोग्राम कांग्रेस के प्रस्तावित अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पर आधारित है। हालांकि इसमें सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के गारंटी देने बजाय मनमाने लक्ष्य (एक करोड़ इंटर्नशिप) रखे गए हैं।
- जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव

बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर अर्थव्यवस्था को न केवल आगे बढ़ाएगा बल्कि निजी निवेश में भी वृद्धि करेगा। यह बजट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मांग को बढ़ाने का भी काम करेगा।
- नागेश कुमार, निदेशक, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान

ई-कोर्ट परियोजना को 1500 करोड़

- अदालती रिकार्ड एवं पुराने और लंबित दोनों तरह के मामलों का होगा डिजिटलीकरण

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : कानून मंत्रालय की ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपये के प्रविधान हैं। तीसरे चरण में निचली अदालतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना है।

चार वर्षों में लागू होने वाले तीसरे चरण में 2,038.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सभी अदालती रिकार्ड एवं पुराने और लंबित दोनों तरह के मामलों का डिजिटलीकरण होगा। इससे कुल 3,108 करोड़ दस्तावेज का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तीसरे चरण के तहत सिस्टम को 'क्लाउड तकनीक' पर स्थानांतरित किया जाएगा और 25 पेटाबाइट स्टोरेज की अनुमानित लागत 1,205.20 करोड़ होगी। परियोजना का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाकर मामलों की सुनवाई के लिए वर्चुअल कोर्ट को स्थापित करना और उसका विस्तार करना है। कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत भारतीय न्यायपालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम बनाने के लिए ई-कोर्ट परियोजना 2007 से लागू किया गया है।

कर विवाद कम करने पर जोर

सरकार ने कर मामलों में विवादों को कम करने के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना-दो लाने का प्रस्ताव किया। दोबारा आकलन की कार्रवाई शुरू करने की समय सीमा में कमी लाने को अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने की भी घोषणा हुई। बजट के अनुसार, आकलन वर्ष समाप्ति के बाद तीन साल से लेकर पांच साल तक की अवधि वाले आयकर मामलों को फिर खोला जा सकेगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि मामला 50 लाख रुपये या उससे अधिक का हो। तलाशी के मामलों में भी तलाशी के वर्ष से पहले छह साल की समय सीमा का प्रस्ताव किया गया है।

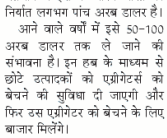

ई-कामर्स के जरिये निर्यात बढ़ाने के लिए बनाए जाएंगे हब

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने पीपीपी मोड में ई-कामर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हब स्थापित करने का एलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये हब एक ही छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। एमएसएमई व पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने में सक्षम बनाने को पीपीपी मोड में ई-कामर्स निर्यात हब स्थापित होंगे।

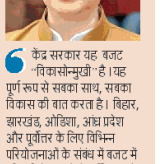

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन हब में त्वरित सीमा शुल्क निकासी जैसी सुविधाएं होंगी और ये प्रमुख कार्गो केंद्रों के पास स्थित होंगे। शुरु में 10-15 हब स्थापित होंगे, अच्छा प्रोत्साहन मिला तो बाद में विस्तार करेंगे। वर्तमान में इस के जरिये भारत का निर्यात लगभग पांच अरब डालर है।

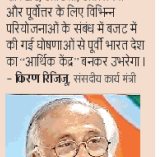

आने वाले वर्षों में इसे 50-100 अरब डालर तक ले जाने की संभावना है। इन हब के माध्यम से छोटे उत्पादकों को एग्रीगेटर्स को बेचने की सुविधा दी जाएगी और फिर उस एग्रीगेटर को बेचने के लिए बाजार मिलेंगे।

एमएसएमई को आसान कर्ज सुविधा, गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद

- सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के लोन की गारंटी होगी

40% से अधिक योगदान देता है एमएसएमई देश के जीडीपी व निर्यात दोनों में

बजट में मशीनरी खरीदने को क्रेडिट गारंटी स्कीम लांच की गई है। प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश के जीडीपी और निर्यात दोनों में ही 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देने वाले एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को सबसे अधिक कठिनाई कर्ज लेने में ही आती है। इस बार के बजट में सरकार ने इस समस्या को दूर करने की कोशिश की है। कई बार एमएसएमई इसलिए भी अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि उनके पास नई मशीनरी खरीदने के लिए पूंजी नहीं होती है और बैंक बिना किसी गिरवी या थर्ड पार्टी गारंटी के उन्हें मशीनरी के लिए जल्दी कर्ज नहीं देता है। इस बार के बजट में मशीनरी की खरीदारी के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लांच की गई है। इस स्कीम के तहत सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के लोन की गारंटी होगी। कर्ज लेने वाले एमएसएमई को सिर्फ अपफ्रंट गारंटी फीस देनी होगी।

डिजिटल ट्रांजेक्शन के आधार पर भी एमएसएमई को लोन दिए जाएंगे। बजट के मुताबिक बैंक एमएसएमई को डिजिटल लेनदेन के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें लोन देगा। कई ऐसे छोटे उद्यमी हैं जो अकेले ही कारोबार करते हैं और उनके टर्नओवर का मूल्यांकन करना आसान नहीं होता है हालांकि वे डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। इस प्रकार के उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा। कारोबारी परेशानी की वजह से एमएसएमई का कारोबार कई बार दिक्कत में आ जाता है और वे बैंक के कर्ज को नहीं चुका पाते हैं। एक से अधिक किस्त नहीं चुका पाने पर उनका खाता स्पेशल मेंशन खाता बन जाता है और वे एनपीए घोषित होने के कगार पर आ जाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें बैंक से भविष्य में कर्ज नहीं मिलने में कठिनाई होती है। एमएसएमई को इस परेशानी से बचाने के लिए अलग से फंड बनाने की घोषणा की गई है।

एमएसएमई से जुड़े सभी बड़े क्लस्टर में अगले तीन साल में सिडबी अपनी शाखा खोलेगा और सीधे तौर पर वहां के एमएसएमई को लोन देगा। इस साल 24 ऐसी शाखा खोलने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाने पर उन्हें काफी फायदा हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य आइटम से जुड़े एमएसएमई सेक्टर में उनकी गुणवत्ता जांच को लेकर 50 यूनिट खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई इन दिनों 45 दिनों के भीतर भुगतान के नियम से परेशान चल रहे हैं क्योंकि किसी भी खरीदारी के 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि उद्यमी की आय बन जाती है और उस पर टैक्स लग जाता है। एमएसएमई 45 दिन की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बजट में उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया।

निर्यात प्रोत्साहन के लिए ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा

एमएसएमई के निर्यात प्रोत्साहन के लिए बजट में ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा की गई है। ये हब निजी-सरकारी सहभागिता से बनाए जाएंगे, जहां एक ही जगह पर निर्यात करने संबंधी सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। इसका फायदा यह होगा कि छोटे-छोटे बुनकर, पेंटर या घरों में सामान बनाकर बेचने वाले उद्यमी भी अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। ई-कामर्स पोर्टल से उन्हें आर्डर मिलेंगे और इस ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब की मदद से वे आसानी से अपने सामान का निर्यात कर सकेंगे।

बात पते की

राजकोषीय घाटा 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह 2024-25 के लिए फरवरी में पेश अंतरिम बजट में अनुमानित 5.1 प्रतिशत से कम है।

अमृतसर-कोलकाता गलियारे से उद्योग जगत में आएगी क्रांति

नीरज कुमार मिश्र ● जागरण

डोभी (गया) : अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्री कारिडोर गया जिले के डोभी प्रखंड से होकर गुजरेगा। इसके लिए जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर खरांटी पंचायत में दस मौजों की 1650 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इनमें 1113.92 एकड़ जमीन में मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर बनाया जाएगा। लक्ष्य लगभग एक हजार एक हजार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का है। बची हुई जमीन पर सड़क, खुली जगह व यूटिलिटी सर्विस सेंटर बनेंगे। अधिग्रहित जमीन के साठ प्रतिशत से अधिक जमीन को ग्रीन एरिया रखने का लक्ष्य है। यह गलियारा बिहार के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरेगा। इससे देश के सात राज्यों के बीस शहरों को सीधा लाभ होगा। इसमें बिहार का गया भी शामिल है। देश के बीसों शहर उद्योग के मामले में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। केंद्र सरकार इस गलियारे की स्वीकृति पूर्व में दे चुकी है।

****

समृद्ध खजाना

एक्स-रे मशीन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक्स-रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर आयात शुल्क अब पांच प्रतिशत

मजबूत हुआ सरकार का खजाना, काबू में रहेगा घाटा

- फिर से राजकोषीय संतुलन पर आगे बढ़ी सरकार
- रुपये पर दिखेगा असर, महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी

4.9 प्रतिशत रहेगा राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में

50 हजार करोड़ की चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान

2.10 लाख करोड़ रुपये पिछले दिनों आरबीआइ ने केंद्र सरकार को हस्तांतरित किए थे

32.07 लाख करोड़ रुपये सरकार की कुल प्राप्तियां

5.1% राजकोषीय घाटे को रखने की बात अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कही थी।

7.8% सब्सिडी के बिल में कटौती करने का प्रस्ताव

4.13 लाख करोड़ की सब्सिडी पिछले वित्त वर्ष में दी गई थी

4.5% से अगले वर्ष घाटे को नीचे लाने का वित्त मंत्री ने रखा लक्ष्य

11.63 लाख करोड़ रुपये बाजार से उधारी के जरिये जुटाने की सरकार की है योजना

48.21 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय रहा सरकार का

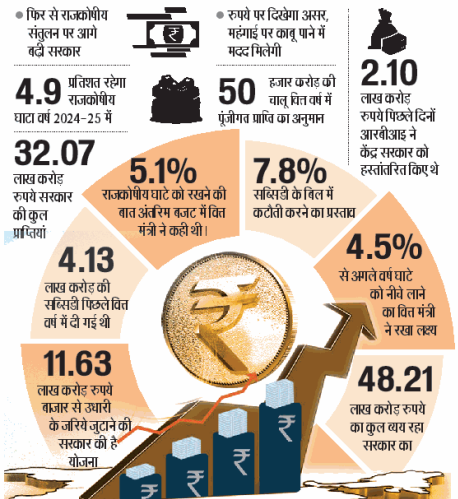

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पिछले दिनों जब आरबीआइ ने केंद्र सरकार को अपने खाते से 2.10 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे, तभी यह साफ हो गया था कि कोविड महामारी के झंझावातों से सरकारी खजाने की नौका बाहर निकल चुकी है। हाल के महीनों में लगातार हर महीने 1.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी संग्रह, सरकारी कंपनियों से मिलने वाले लाभांश में भारी वृद्धि का असर भी साफ होता दिख रहा है। तभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को 4.9 प्रतिशत पर सीमित करने की बात कही है और अगले वित्त वर्ष 2025-26 में घाटे को 4.5 प्रतिशत (सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में) पर लाने का विश्वास जताया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को 5.1 प्रतिशत पर रखने की बात कही थी। इसके साथ ही सरकार ने सब्सिडी के बिल में 7.8 प्रतिशत की कटौती करते हुए इसे 3.81 लाख करोड़ रुपये पर लाने का प्रस्ताव रखा है। कई विशेषज्ञों ने सरकारी खजाने की मजबूत स्थिति को देखते हुए कहा है कि जल्द ही अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग में सुधार कर सकती हैं। जिस तरह से राजकोषीय घाटा काबू में आया है, इसका असर रुपये पर भी दिखेगा और इससे सरकार को महंगाई पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा है कि कोविड के दौरान राजकोषीय संतुलन को लेकर जो कदम उठाए गए थे, उसका लाभ हुआ है। हमारा लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है। इस राह पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2026-27 में हमारा प्रयास प्रति वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार रखना है कि केंद्र सरकार के ऋण व जीडीपी का अनुपात लगातार कम होता जाए। वर्ष 2024-25 के लिए उधारियों को छोड़ कर सरकार की कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये की और कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये का रहा है। इस साल सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके 14.01 लाख करोड़ रुपये और बाजार से उधारी के जरिये 11.63 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। यह दोनों राशि पिछले साल से कम रहेंगी।

सब्सिडी के बिल में 7.8 प्रतिशत की कमी भी बताती है कि सरकार राजकोषीय संतुलन को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सेक्टर को इस साल कुल 3,81,175 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में 4.13 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बतौर सब्सिडी दी गई थी। खाद्य सब्सिडी 2,12,332 करोड़ रुपये से घटाकर इस साल 2,05,250 करोड़ रुपये, उर्वरक सब्सिडी 1,88,894 करोड़ रुपये से घटाकर 1,64,000 करोड़ रुपये और एलपीजी सब्सिडी 12,240 करोड़ रुपये से घटाकर 11,925 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव किया गया है।

विनिवेश से 50 हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिवेश और संपत्ति मौद्रिकरण के जरिये 50 हजार करोड़ रुपये जुटाए जाने का लक्ष्य रखा है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सचिव तुहिन कांत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (सीपीएसई) को 56,260 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने का अनुमान है। अंतरिम बजट में सीपीएसई से 48 हजार करोड़ रुपये का अनुमान जताया गया था।

तुहिन कांत • फाइल फोटो

बजट में आरबीआइ, बैंकों और और वित्तीय संस्थानों से चालू वित्त वर्ष में 2,32,874 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने की उम्मीद जताई गई है। यह अंतरिम बजट के अनुमान 1.02 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। इसमें यह भारी वृद्धि आरबीआइ से 2.11 लाख करोड़ का लाभांश मिलने के कारण की गई है। चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत प्राप्ति 50 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान घटाकर 30 हजार करोड़ रुपये किया गया है।

बैंकों के कर्ज वितरण में दोहरे अंक में वृद्धि

बुधवार 24 जुलाई, 2024

2023-24 में बैंकों ने पिछले दो वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अधिक लोन बांटा। इससे पूंजीकरण में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा इस साल शेयर बाजार में भी काफी उछाल देखा गया। निफ्टी-50 इंडेक्स भी बढ़ा।

118.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटा बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान
15% वृद्धि 2020-21 के मुकाबले रही

136.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरण रहा बैंकों की ओर से 2022-23 के दौरान।
20.2% वृद्धि 2021-22 के मुकाबले रही

164.3 लाख करोड़ रुपये का लोन बांटा बैंकों ने 2023-24 में
20.10% वृद्धि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले

124% हुआ 2023-24 में बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात जो 2018-19 में 77% था

बीते वित्त वर्ष में भारतीय शेयर बाजारों का बेहतर प्रदर्शन

10.9 लाख करोड़ रुपये की पूंजी का निर्माण किया प्राथमिक बाजारों या आइपीओ ने 2023-24 में

9.3 लाख करोड़ रुपये की पूंजी का निर्माण हुआ था 2022-23 में प्राथमिक बाजारों के जरिये

53.4 लाख करोड़ रुपये हुआ म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 2023-24 के अंत में। वित्त वर्ष के दौरान इसमें 14 लाख करोड़ की वृद्धि रही है।

26.8% की वृद्धि रही निफ्टी-50 इंडेक्स में बीते वित्त वर्ष के दौरान, जो 2022-23 के दौरान -8.2 थी

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

बजट बोल

उज्ज्वल, समृद्ध भविष्य हम सभी की प्रतीक्षा कर रहा है। यह दूरदर्शी बजट सतत विकास, नवाचार और स्थायी प्रगति को बढ़ावा देता है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करता है। - **नितिन गडकरी**, केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए की गई घोषणाएं 'सरकार बचाने' का प्रयास है। सरकार ने किसानों और नौजवानों के साथ पूरे देश की अनदेखी की है। देश का नौजवान आधी-अधूरी नहीं, बल्कि पक्की नौकरी चाहता है। -**अखिलेश यादव**, सपा अध्यक्ष

प्रतिभूति लेनदेन कर और अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर के मोर्चे पर बाजार सरकार से कड़े कदमों की उम्मीद कर रहा था। हालांकि यह कदम बदलाव की दिशा में छोटा प्रयास है। अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। -**आशीष चौहान**, एमडी और सीईओ, एनएसई

मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन को कई वस्तुओं के आयात शुल्क में कटौती

- कैंसर की तीन दवाएं, मोबाइल फोन और चार्जर होंगे सस्ते
- लेदर व टेक्सटाइल के कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग के साथ निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती की है तो कुछ में बढ़ोतरी का एलान भी किया है। कच्चा माल सस्ती दरों पर मिलने से लागत कम होगी और वैश्विक बाजार में वे आसानी से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। लेदर और टेक्सटाइल जैसे रोजगारपरक सेक्टर अपने कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती की मांग कर रहे थे और सरकार ने बजट में उनकी मांग मान ली है।

बजट में मोबाइल फोन, चार्जर एडाप्टर के आयात पर लगने वाले 20 प्रतिशत शुल्क को 15 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। इस फैसले से अब मोबाइल फोन व चार्जर एडाप्टर पहले की तुलना में पांच प्रतिशत सस्ते हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है। निर्यात में करीब 100 गुना वृद्धि के साथ भारतीय मोबाइल फोन उद्योग अब परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क घटाने से घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा और लागत कम होने से भारत में बनने वाले मोबाइल फोन निर्यात बाजार में आसानी से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। मोबाइल फोन उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन (आइसीईए) के चेयरमैन पंकज मोहिन्द्रू ने कहा कि हमने मोबाइल फोन, इसके सर्किट बोर्ड और चार्जर/एडाप्टर पर शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग इन घोषणाओं से उत्साहित है और इससे निर्माण, निर्यात तथा हमारी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे उत्पाद में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है और इन सेक्टर के निर्माण के प्रोत्साहन के लिए बजट में सभी प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर लगने वाले 2.5-10 प्रतिशत शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कैंसर की तीन दवा ट्रासटूजूमब डेरूक्सटिकेन, ओसिमर्टिनिब, डूरवालूमाब पर लगने वाले 10 प्रतिशत शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह कदम कैंसर रोगियों को बहुत राहत प्रदान करेगा। लेदर गारमेंट, फुटवियर बनाने में इस्तेमाल होने वाले उच्च गुणवत्ता वाले फिनिश्ड लेदर पर लगने वाले 10 प्रतिशत आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। एक्स-रे मशीन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर आयात शुल्क को 15 से पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

बीएसएनएल की बदलेगी सूरत, टेलीकाम सेक्टर को 1.28 लाख करोड़ मिले

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसमें से अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए निर्धारित की गई है। कुल प्रस्तावित आवंटन में से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित खर्चों के लिए हैं, जिसमें बीएसएनएल में टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन और पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है। इसे बीएसएनएल की सूरत बदलने की दिशा में प्रयास माना जा रहा है।

2024-25 में इस मांग के लिए शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ (1,11,915.43 करोड़ रुपये और 17,000 करोड़ रुपये) है। 17,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रविधान 'यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड' के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा होता है और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा, भारतनेट और अनुसंधान विकास के लिए किया जाएगा।'

सोना-चांदी खरीदना होगा सस्ता, आयात पर शुल्क घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने ज्वेलरी उद्योग के साथ आम आदमी को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात पर लगने वाले बेसिक यानी मूल सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव पेश किया है।

बजट प्रस्ताव के अनुसार, अब सोने और चांदी की पट्टियों के आयात पर कुल छह प्रतिशत सीमा शुल्क लगेगा। अभी तक इनके आयात पर कुल 15 प्रतिशत सीमा शुल्क लग रहा था। इसी तरह सोना-चांदी की डोर या धागों के आयात पर 5.35 प्रतिशत शुल्क लगेगा। अभी इन पर 14.35 प्रतिशत शुल्क लग रहा था। यह नई दरें 24 जुलाई 2024 से लागू होंगी। इस तरह प्लेटिनम, पैलेडियम, आस्मियम, रूथेनियम और इरेडियम धातुओं के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को भी 15.4 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत किया गया है।

इसके अलावा कीमतों धातुओं से बने सिक्कों के आयात पर लगने वाले शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत किया गया है। वहीं, सोना-चांदी की ज्वेलरी के आयात पर भी शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत किया गया है। उद्योग को राहत देने के लिए कुछ धातु समाधानों, धातु यौगिक और कैटेलिक कन्वर्टर की मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल के लिए प्लेटिनम और पैलेडियम आयात पर अब पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा। अभी इस श्रेणी में आयात शुल्क की दर 7.5 प्रतिशत थी। स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फेरो निकेल और ब्लिस्टर कापर से बेसिक सीमा शुल्क को हटाया गया है। अभी इनके आयात पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क लग रहा था।

तस्करी कम करने में मदद मिलेगी: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारतीय कारोबार के सीईओ सचिन जैन का कहना है कि यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे सोने की तस्करी में कमी आएगी। साथ ही ईमानदार उद्योग हितधारकों को कारोबार के लिए एकसमान अवसर मिलेंगे।

- सोने-चांदी की पट्टियों पर कुल सीमा शुल्क छह प्रतिशत किया गया
- प्लेटिनम, पैलेडियम जैसी धातुओं के आयात पर शुल्क 6.4 प्रतिशत किया
- सोना-चांदी की डोर या धागों के आयात पर 5.35 प्रतिशत शुल्क लगेगा

3,350 रुपये घटा सोने का मूल्य, 73,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा

आयात शुल्क में कमी के बाद सोना और चांदी के मूल्य में चार प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट हुई है। आल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में सोने के मूल्य में 3,350 रुपये की गिरावट आई है और यह 73,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसी प्रकार चांदी का मूल्य 3,500 रुपये घटकर 87,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। बीते पांच सत्रों में चांदी के मूल्य में 6,900 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। वहीं, वायदा बाजार एमसीएक्स में भी सोने के मूल्य में करीब पांच प्रतिशत की गिरावट रही और यह 68,914 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसी प्रकार चांदी करीब साढ़े चार प्रतिशत घटकर 85,067 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

शेयर बाजार से कमाई पर देना होगा ज्यादा टैक्स

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से कमाई पर अब अधिक टैक्स देना होगा। बजट में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की बिक्री से शार्ट टर्म (एक साल के भीतर) में होने वाले कैपिटल गेन पर अब 15 की जगह 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं लांग टर्म (एक साल से अधिक) में बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन पर 10 की जगह 12.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इससे शेयर बाजार के खुदरा निवेशक हतोत्साहित हो सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स में इस बदलाव से सरकार को 15 हजार करोड़ रुपये सालाना मिलने की उम्मीद है। अब तक 16 करोड़ से अधिक डिमैट अकाउंट खुल चुके हैं।

15,000 करोड़ सरकार को सालाना मिलने की उम्मीद है कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव से

- शार्ट टर्म पर होने वाले कैपिटल गेन पर अब 15 की जगह 20 प्रतिशत कर देना होगा

सरकार का कहना है कि उसने कैपिटल गेन की टैक्स दर का सरलीकरण किया है, क्योंकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की बिक्री या प्रापर्टी की बिक्री पर जो 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगता था, उसे घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में सूचीबद्ध कंपनियों के म्यूचुअल फंड से होने वाले सालाना 1.25 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी। गैर सूचीबद्ध या अन्य संपदा को दो साल के बाद बेचने पर उसे लांग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। लांग टर्म में रियल एस्टेट की बिक्री पर अभी 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि शेयर बाजार से कमाई पर जो टैक्स वसूला गया, उनमें 88 प्रतिशत टैक्स देने वालों की सालाना कमाई 15 लाख से अधिक थी।

स्टार्टअप व इनोवेशन के प्रोत्साहन के लिए एंजल टैक्स किया समाप्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: सरकार ने बजट में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। इससे स्टार्टअप को बड़ी राहत मिली है। संप्रग सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2012 में एंजल टैक्स लगाया गया था, जिसे स्टार्टअप अपने विकास में बड़ी बाधा मान रहे थे। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन की जरूरत है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एंजल टैक्स को हटाने का फैसला किया गया है। अगर कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है, उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता है।

मान लीजिए किसी स्टार्टअप की फेयर वैल्यू एक करोड़ है और वह 1.5 करोड़ रुपये एंजल निवेशकों से जुटाता है तो 50 लाख रुपये पर एंजल टैक्स लगेगा। वर्ष 2012 में टैक्स लगाते समय सरकार की यह सोच थी कि बाहरी निवेश की आड़ में मनी लांड्रिंग की जा सकती है। जानकारों का कहना है कि एंजल टैक्स को समाप्त करने से स्टार्टअप को फंड जुटाना आसान हो जाएगा। स्टार्टअप अब इनोवेशन पर अधिक खर्च कर सकेंगे और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। एंजल टैक्स की वजह से नए स्टार्टअप को फंड जुटाने में कठिनाई होती थी और विदेश से फंड जुटाने वालों को शक की नजर से देखा जाता था।

विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लांच : इनकम टैक्स से जुड़े विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने फिर से विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लांच करने की घोषणा की है। चार साल पहले भी विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर व सर्विस टैक्स संबंधित 60 लाख रुपये तक के विवाद पर टैक्स ट्रिब्यूनल में दो करोड़ के विवाद के लिए हाई कोर्ट में तो पांच करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। बजट में टैक्स संबंधी प्रविधान को और सरल बनाने का भी एलान किया गया है। इसके तहत पुराने रिटर्न का फिर से मूल्यांकन हो सकेगा। हालांकि सिर्फ 50 लाख या इससे अधिक राशि वाले कर मामले में ही तीन साल से अधिक पुराने मामले का फिर ले मूल्यांकन होगा।

स्टार्टअप अब इनोवेशन पर अधिक खर्च कर सकेंगे और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी, युवाओं को होगा फायदा

कर सरलीकरण प्रक्रिया की पहल

धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस के लिए कर सरलीकरण प्रक्रिया की पहल करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अनेक भुगतानों पर पांच प्रतिशत टीडीएस दर को घटाकर दो प्रतिशत किया जा रहा है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को एक प्रतिशत से कम करके 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। टीसीएस की राशि को वेतन पर कटौती किए जाने वाले टीडीएस की गणना में लाभ का प्रस्ताव भी लाया गया है।

एफएंडओ लेनदेन पर टैक्स बढ़ाने से 1200 अंक तक गिरा सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र: बजट में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) पर प्रतिभूति लेनदेन पर कर बढ़ाने के प्रस्ताव के बीच बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। दिन के कारोबार के दौरान 1200 अंकों की गिरावट की भरपाई करते हुए 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 73.04 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,429.04 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 30.20 अंक या 0.12 प्रतिशत गिरकर 24,479.05 पर आ गया। दिन के कारोबार में यह 435.05 अंक या 1.77 प्रतिशत गिरकर 24,074.20 पर आ गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तावों की घोषणा के दौरान सूचकांक दिनभर उच्च और निम्न के बीच घूमता रहा।

वित्त मंत्री द्वारा एफएंडओ व्यापार पर एसटीटी (सिक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स) में बढ़ोतरी और इक्विटी पर लांग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (एलटीसीजी) में वृद्धि की घोषणा के बाद एक समय सेंसेक्स 1,277.76 अंक या 1.58 प्रतिशत गिरकर 79,224.32 के निचले स्तर पर आ गया था। हालांकि, बाद में कर छूट और सीमा शुल्क में कटौती जैसे एलान ने उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और एफएमसीजी शेयरों को बढ़ाने में मदद प्रदान की, जिससे शेयरों को दिन के निचले स्तर से उबरने में मदद मिली।

छह प्रतिशत बढ़ा टाइटन : सेंसेक्स पैक में टाइटन ने छह प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाई। वहीं आइटीसी ने पांच प्रतिशत से अधिक की बढ़त हासिल की। अदाणी पोर्ट्स, एनटीपीसी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक्नोलाजीज और सन फार्मा ने भी तेजी दर्ज की। हालांकि, लार्सन एंड टूब्रो, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक आफ इंडिया, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक गिरकर बंद हुए।

पिछले तीन बजट दिनों में बढ़त के साथ बंद हुआ था बाजार : पिछले तीन बजट दिनों में शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे। 2023 में, बजट के दिन, बीएसई बेंचमार्क 158.18 अंक या 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,708.08 पर बंद हुआ। 2022 में, सेंसेक्स 848.40 अंक या 1.46 प्रतिशत उछलकर 58,862.57 पर बंद हुआ, जबकि 2021 में बजट घोषणाओं के बाद यह 2,314.84 अंक या पांच प्रतिशत बढ़कर 48,600.61 पर पहुंच गया। 2020 में, बीएसई बेंचमार्क 987.96 अंक या 2.48 प्रतिशत गिरकर 39,735.53 पर आ गया था। हालांकि, 2019 में यह 212.74 अंक या 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 36,469.43 पर पहुंच गया था। बजट के दिनों में की बात करें तो एक फरवरी, 2023 को एनएसई निफ्टी 45.85 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर 17,616.30 पर आ गया। 2022 में बजट के दिन निफ्टी 237 अंक या 1.37 प्रतिशत बढ़कर 17,576.85 पर बंद हुआ। एक फरवरी, 2021 को निफ्टी 646.60 अंक या 4.74 प्रतिशत बढ़कर 14,281.20 पर बंद हुआ।

तीन पैसा गिरा रुपया: बजट में सरकार द्वारा पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाए जाने के बाद मंगलवार को रुपया डालर के मुकाबले तीन पैसे गिरकर 83.69 के स्तर पर बंद हुआ।

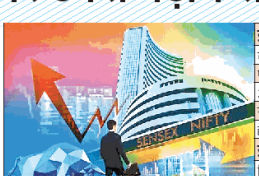

बाजार के नजरिए से शार्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (एसटीसीजी) को 20 प्रतिशत और लांग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (एलटीसीजी) को 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाना एक बड़ा झटका है। हमें छोटी अवधि में नकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार रखना होगा। -**संजय सिन्हा**, संस्थापक, सिट्रस एडवाइजर्स

सोने और चांदी पर मौजूदा शुल्क 15 प्रतिशत है। इसमें मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत और पांच प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर शामिल है। -**हरीश वी**, कमोडिटीज प्रमुख, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज

इन सेक्टर में रही तेजी	
कंज्यूमर ड्यूरेबल	2.45%
एफएमसीजी	2.48%
आइटी	0.82%
सर्विसेज	0.62%
हेल्थकेयर	0.59%

इन सेक्टर में आई गिरावट	
रियल्टी	2.15%
कैपिटल गुड्स	2.03%
इंडस्ट्रियल	1.48%
फाइनेंशियल सर्विसेज	1.27%
मेटल	1.02%

आभूषण कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी

सोने और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत करने के एलान के बाद आभूषण का काम करने वाली कंपनियों के शेयरों में 14 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। त्रिभुवनदास भीमजी झवेरी का शेयर 13.86 प्रतिशत बढ़कर 155.30 रुपये पर बंद हुआ। टाइटन 6.63 प्रतिशत बढ़कर 3,468.15 रुपये पर बंद हुआ।

****

समृद्ध सोच

वित्त मंत्री ने कहा, सरकार उत्पादकता में सुधार, बाजारों व क्षेत्रों को अधिक कार्यकुशल बनाने के प्रयास करेगी

पेट्रोलियम कंपनियों में 30 हजार करोड़ की पूंजी डालने की योजना रद

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों में 30 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने की योजना को समाप्त कर दिया है। यह फैसला 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में पेट्रोलियम कंपनियों को हुए रिकार्ड मुनाफे के बाद लिया गया है।

सीतारमण ने पिछले साल एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के लिए वार्षिक बजट पेश करते हुए इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में 30 हजार करोड़ रुपये की पूंजी (इक्विटी) डालने की घोषणा की थी, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों कंपनियों की ऊर्जा बदलाव की योजनाओं का समर्थन किया जा सके।

इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के मैंगलोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रणनीतिक भूमिगत भंडारणों को भरने के लिए कच्चा तेल खरीदने हेतु 5,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा था। वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में दोनों योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। बजट दस्तावेजों में 2024-25 में तीन पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पूंजी सहायता के लिए शून्य आवंटन दिखाया है, जबकि 2023-24 के बजट में 30,000 करोड़ का प्रविधान किया गया था। इस साल फरवरी में अंतरिम बजट में 15 हजार करोड़ की राशि दिखाई गई थी। बजट में संशोधित आवंटन में 2023-24 को व्यय के रूप में 0.01 करोड़ व 2024-25 के बजट प्रविधान में शून्य दिखाया गया है।

2023-24 में पेट्रोलियम कंपनियों को हुए रिकार्ड मुनाफे के बाद सरकार ने लिया फैसला

5,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा था रणनीतिक भूमिगत भंडारणों को भरने के लिए

अगले दौर के सुधारों में राज्यों की होगी बड़ी भूमिका

आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनेगा, तय किए जाएंगे आगामी सुधारों के नए लक्ष्य

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

नई दिल्ली : आम चुनाव 2024 के प्रचार में पीएम नरेन्द्र मोदी ने भरोसा जताया था कि उनकी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बड़े सुधारों को लागू करेगी। मंगलवार को घोषित आम बजट 2024-25 में बड़े सुधारों की तरफ बढ़ने की उनकी सरकार की मंशा तो दिखती है, लेकिन इसका तरीका बदला नजर आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक नए आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाने की घोषणा की है। इसके तहत विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सुधारों के नए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार की मंशा यह भी साफ दिखती है कि वह भूमि जैसे अटके सुधारों को लेकर अब केंद्र के स्तर पर कम और राज्यों की तरफ से अधिक कदम उठाने को प्रोत्साहित करना चाहती है। ऐसा करने वाले राज्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार उत्पादकता में सुधार और बाजारों व क्षेत्रों को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए सुधार करेगी। इनमें भूमि, श्रम, पूंजी क्षेत्र में सुधार भी शामिल है। इनमें से कई सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग व आम सहमति आवश्यक है, क्योंकि राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव है। सुधारों को तेजी से लागू करने में राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र की तरफ से उन्हें 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की है। केंद्र और राज्य मिलकर जो सुधार करेंगे, उनमें प्रमुख है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार। इसके तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की पहचान संख्या या भू-आधार निर्धारित किया जाएगा। पूरे मानचित्र का डिजिटलीकरण किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के आधार पर मौजूदा भू-मानचित्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। भू-रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी और कृषक (खेती योग्य जमीन) रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा।

इसी तरह से शहरी क्षेत्र में भी सभी जमीन के रिकार्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। जमीन की तरह श्रम सुधार भी सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। आम बजट 2024-25 में श्रम संबंधी सुधार को सरकार की प्राथमिकताओं में एक बताया गया है, लेकिन इस बारे में कोई बड़ी घोषणा करने से परहेज किया गया है।

50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा केंद्र की ओर से सुधार करने वाले राज्यों को

40 से 35 प्रतिशत की गई विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर बजट में

कंपनियों को विदेश में रुपये में निवेश के लिए मिलेगा प्रोत्साहन

मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में एफडीआइ को प्रोत्साहन देने को लेकर कोई बड़ी घोषणा तो नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री का यह वादा जरूर है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत से बाहर जाने वाले निवेश के नियमों को आसान किया जाएगा। प्राथमिकताओं के आधार पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जो कंपनियां देश के बाहर निवेश कर रही हैं, उन्हें भारतीय रुपये के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अभी यह निवेश मुख्य तौर पर डालर में होता है। भारत सरकार ने वर्ष 2023 से अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भी रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। इस क्रम में बता दें कि वित्त मंत्री ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत में कारपोरेट टैक्स की दर को मौजूदा 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का एलान किया है। यह भारत में विदेशी निवेश को बढ़ा सकता है। 2023-24 में भारत में कुल 44.42 अरब डालर का एफडीआइ आया था।

सुधारों को लेकर पहले की घोषणाओं पर चुप्पी, श्रम संहिता पर भी स्थिति साफ नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्थिक सुधारों को लेकर कुछ नया सोच तो सरकार की तरफ से दिखाया गया है, लेकिन पूर्व में बड़े सुधारवादी कदमों को लेकर वित्त मंत्री की चुप्पी साफ तौर पर दिख रही है। बजट अभिभाषण में ना तो सरकार की विनिवेश नीति को आगे बढ़ाने की बात है और ना ही पूर्व में बैंक निजीकरण को लेकर जो घोषणाएं की गई थीं, उनको लेकर कोई दिशा मिलती है। इसी तरह से श्रम संहिता को लेकर भी सरकार स्थिति साफ करती नहीं दिख रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश से सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है। यह आंकड़ा फरवरी, 2024 में पेश अंतरिम बजट के मुताबिक ही है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने सिर्फ 30 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा था।

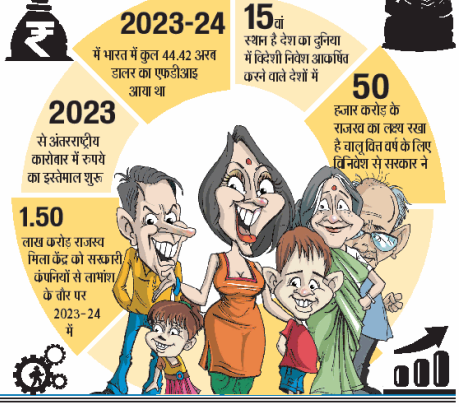

बजट बोल

यह बजट समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह बजट भारत को 2027 तक पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कापी भी नहीं कर पाया 'नकलची बजट'! बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी 'रेवड़ियां' बांट रहा है। ये तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है।

- मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

बजट में प्रस्तावित कई सुधार उपाय राज्यों पर निर्भर हैं। ऐसे सुधारों की सफलता संघ और राज्य समन्वय पर निर्भर है। ये सुधार तभी संभव होंगे जब राज्य सरकारें राजकोषीय स्वायत्तता से समझौता किए बिना ऐसे सुधारों को करने के लिए तैयार हों।

-पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर, एनआइपीएफपी

भूटान के विकास पर अधिक खर्च मालदीव के लिए आवंटन में कमी

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय बजट में भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप भूटान को विकास संबंधी मदद के रूप में सर्वाधिक 2068 रुपये आवंटित किये गये, जबकि मालदीव पर खर्च की जाने वाली राशि को पिछले साल के 770 करोड़ से घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। मालदीव को आवंटित की जाने वाली राशि में कटौती ऐसे समय में की गई है जब चीन के प्रति झुकाव रखने वाले मोहम्मद मुइज्जू के द्विपीय देश का राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया गया है।

बजट में विदेश मंत्रालय (एमईए) को इस वित्त वर्ष के लिए कुल 22,154 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि पिछले साल का आवंटन 29,121 करोड़ रुपये था। संसद में फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में विदेश मंत्रालय को समान आवंटन किया गया था। अंतरिम बजट में मालदीव को विकास के मद में दी जाने वाली सहायता राशि 600 करोड़ रुपये आंकी गई थी। बजट दस्तावेज के अनुसार, अब मालदीव को किया गया आवंटन केवल 400 करोड़ रुपये है।

22,154 करोड़ केंद्रीय बजट में आवंटित किए गए विदेश मंत्रालय को

वित्त वर्ष 2024-25 में भूटान के लिए आवंटित राशि 2068 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल यह राशि 2398 रुपये थी। अफगानिस्तान के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए उस देश के लिए 200 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। वर्ष 2023-24 में अफगानिस्तान के लिए आवंटन 220 करोड़ रुपये था। भारत की ओर से पड़ोसी प्रथम नीति पर आगे बढ़ते हुए बजट में यह आवंटन किया गया है। बजट के तहत लिए गए निर्णय के भविष्य में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।

वित्तीय सुधार पर आएगा नया एजेंडा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। भारत के वित्तीय सेक्टर में वैसे तो लगातार संशोधन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब इसमें समग्र तौर पर नई नीति बनाने की मंशा जताई गई है। इसके लिए सरकार पंचवर्षीय एजेंडा लेकर सामने आने वाली है। इसकी घोषणा आम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति दस्तावेज लाएगी। यह अगले पांच वर्षों के लिए कार्यसूची निर्धारित करेगा और सरकार, विनियामकों, वित्तीय संस्थाओं और बाजार भागीदारों का मार्गदर्शन करेगा।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार दो अन्य अहम कदम उठाने जा रही है। इसमें एक है ऋण वसूली प्राधिकरणों को मजबूत बनाना। इससे बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) को तेजी से घटाने में मदद मिलेगी। जब से दिवालिया कानून (आइबीसी) लागू हुआ है, तब से ऋण वसूली प्राधिकरणों की भूमिका सीमित हुई है, लेकिन इनकी अहमियत अब भी है।

आइबीसी के संदर्भ में सीतारमण ने कहा है कि अभी तक इससे एक हजार कंपनियों का समाधान किया गया है। इससे इन कंपनियों से 3.3 लाख करोड़ रुपये की वसूली ऋणदाताओं को हुई है। दिवालिया प्रक्रिया को सरकार और तेज करेगी। खास तौर पर इसके अपीलीय प्राधिकरणों को और मजबूत किया जाएगा। अतिरिक्त अपीलीय अधिकरणों की स्थापना होगी। अलग-अलग सेक्टर में विशेष अधिकरण स्थापित किए जाएंगे।

5 वर्षों की तय होगी कार्यनीति, ऋण वसूली प्राधिकरणों को मजबूत बनाया जाएगा

1 हजार कंपनियों का समाधान किया गया है अब तक दिवालिया कानून के माध्यम से

जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनोमी विकसित की जाएगी

वित्तीय क्षेत्र में सुधार के साथ ही सरकार ने ग्रीन टेक्नोलाजी के लिए जरूरी वित्तीय सुविधा जुटाने को लेकर भी कुछ अहम घोषणा की है। जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनोमी (क्षेत्रों को वर्गीकृत करने की प्रणाली) विकसित की जाएगी। इसके साथ ही व्यवसाय करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का काम भी तेज किया जाएगा। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों को अपनी व्यवस्था सुधार कार्य योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह केंद्र सरकार के जनविश्वास विधेयक 2.0 से अलग होगा।

कौशल विकास व रोजगार को एक ही सूत्र में पिरोया

5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लक्ष्य को विशेषज्ञों ने सराहनीय बताया

- शिक्षा और रोजगार संबंधी बजट को विशेषज्ञों ने सराहा, कुशल कर्मियों की होगी पूर्ति
- योजनाओं से नियोक्ता व कर्मचारी दोनों को लाभ देने का काम, दिखेंगे अच्छे परिणाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : एचआर और तकनीकी शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने युवाओं के लिए कौशल विकास, इंटर्नशिप और रोजगार सृजन की व्यवस्था किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कार्य क्षेत्र में कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार के इस बजट को विकसित भारत का सोच को साकार करने वाला बताया है।

टीमलीज डिग्री एप्रेंटिसशिप के चीफ स्ट्रेटजी आफिसर सुमित कुमार ने कहा कि पांच सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को पांच सालों में रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य सराहनीय है। विभिन्न योजनाओं के तहत शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को एक ही सूत्र में पिरो दिया गया है। आगे की ऐसी सोच के जरिये ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। इसीतरह क्वेस कार्प के सीईओ गुरुप्रसाद श्रीनिवासन ने कहा, 'कौशल पर जोर देने और रोजगार की योजनाओं से 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। सरकार ने समग्रता की योजना से नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को लाभ देने का काम किया है। महिलाओं के कार्यबल की भागीदारी पर भी जोर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में उनकी अहम भूमिका मानी गई है।'

पर्ल एकेडमी की प्रेसिडेंट अदिति श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने नौकरियों की भारी मांग की पूर्ति के लिए कुशलता में कमी और सामाजिक असमानता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। क्राफ्टशाला के संस्थापक और सीईओ वरुण सातिया ने कहा कि उपयुक्त उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा के लिए दस लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी। पीयरसन इंडिया के कंट्री हेड विनय कुमार स्वामी ने कहा कि अगले पांच सालों में बीस लाख से अधिक युवाओं को कौशल विकास के अवसर देना और एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना सराहनीय कदम है। जीनियस कंसल्टेशन के सीएमडी आरपी यादव ने कहा कि मौजूदा बजट से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विशेष रूप से नौकरियों का सृजन होगा।

सरकार का संकेत, बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना

जागरण ब्यूरो नई दिल्ली : पेंशन हाल के चुनावों में राजनीतिक बहस का एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। आम बजट 2024-25 में भी पेंशन को लेकर कुछ खास संकेत हैं। परोक्ष तौर पर यह तो संकेत दे दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव और उसके पहले राज्यों के चुनाव में भाजपा को जो जीत मिली थी उससे सरकार पेंशन के मुद्दे पर अब बैकफुट पर नहीं है। यही वजह है कि उसने नई पेंशन स्कीम में ही कुछ बदलाव करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। इसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरफ से भी रचनात्मक दृष्टिकोण वाला सुझाव मिला है। अब एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने माता-पिता अभिभावकों द्वारा अव्यस्क बच्चों के लिए अंशदान पर आधारित एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। व्यस्कता की आयु होने पर इस योजना को आसानी से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। सरकार का यह फैसला पेंशन को लेकर मौजूदा विमर्श का एक व्यवहारिक समाधान निकालने की कोशिश है। अभी नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत नौकरी में आने के बाद आम तौर पर लोग खाता खोलते हैं। एनपीएस-वात्सल्य के तहत बचपन से ही बुढ़ापे में आने वाली पेंशन के लिए पैसा जमा करने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी। जानकार बता रहे हैं कि यह वर्ष 2040 के बाद के भारत की तैयारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2040 के बाद भारत में बुजुर्गों की संख्या में धीरे-धीरे इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में बुजुर्गों के लिए वित्तीय संसाधनों की सुविधा का इंतजाम उक्त कदम से किया जा सकेगा।

2040 के बाद देश में बुजुर्गों की संख्या में धीरे-धीरे होगा इजाफा

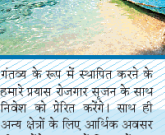

- नई पेंशन स्कीम में ही कुछ बदलाव करने की है तैयारी
- बच्चों के लिए अभिभावक खोल सकेंगे पेंशन खाता, होगा लाभ

नियोक्ताओं के एनपीएस में योगदान पर कर कटौती 14 प्रतिशत

नई कर व्यवस्था के तहत नई पेंशन योजना (एनपीएस) को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए वित्त मंत्री ने नियोक्ताओं द्वारा एनपीएस पर किए जाने वाले व्यय की कटौती को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह नई कर व्यवस्था को चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों के कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक के इस व्यय की कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से प्रतिष्ठित करने का प्रयास

माला दीक्षित ● जागरण

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वह हमेशा लोगों को विदेश के बजाय भारतीय पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। इस बजट में सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के प्रयासों की बात की है। हालांकि सरकार का जोर बिहार और ओडिशा के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने पर ज्यादा है, लेकिन देश के भीतर घरेलू क्रूज संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

2,479.62 करोड़ किया गया है पर्यटन मंत्रालय का बजट बढ़ाकर, विष्णुपद व बोधगया मंदिरों का कारिडोर बनाने का प्रयास

1,692.10 करोड़ का था पिछले वित्त वर्ष में पर्यटन मंत्रालय का बजट, अब बजट से क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलने की है उम्मीद

- क्रूज संचालन करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव
- बिहार और ओडिशा के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने पर दिया गया ज्यादा ध्यान

मंगलवार को वित्त मंत्री ने बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपायों और प्रस्तावों को पेश किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है और वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयास रोजगार सृजन के साथ निवेश को प्रेरित करेंगे। साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर भी खुलेंगे। बजट में बिहार में गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया मंदिरों का कारिडोर बनाने और राजगीर के हिन्दू, बौद्ध, जैन मंदिरों व नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही ओडिशा के दर्शनीय सौंदर्य, मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्यों और प्राचीन समुद्री तट को श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित और विकसित करने की बात कही गई है।

आजकल पर्यटन का एक नया रूप क्रूज पर्यटन का चलन बढ़ रहा है। भारत में क्रूज पर्यटन की संभावनाओं को समझते हुए रोजगार का सृजन करने वाले इस उद्योग को प्रोत्साहित करने की बात भी बजट में कही गई है। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में घरेलू क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का सृजन होगा।

सरकार पर्यटन को किस हद तक महत्व दे रही है इसका पता पर्यटन मंत्रालय के बजट को देखने से भी चलता है। पिछले बजट में पर्यटन मंत्रालय का बजट 1,692.10 करोड़ था जो इस बजट में बढ़ा कर 2,479.62 करोड़ कर दिया गया है।

11,500 करोड़ से बदलेगी कोसी-सीमांचल की तस्वीर

माधबेन्द्र ● जागरण

भागलपुर : आम बजट में किए गए प्रविधान से बहुप्रतीक्षित कोसी-मेची अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना पर तो काम शुरू होगा ही, साथ ही 20 से अधिक योजनाओं को भी मूर्तरूप दिया जाएगा। बजट में इसके लिए 11,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कोसी और सीमांचल के जिलों की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ रही है। बरसात के समय कोसी और इसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ से कई इलाके डूब जाते हैं। आवागमन ठप हो जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान खेती-किसानी को होता है। इस इलाके में जल प्रबंधन बड़ी चुनौती रही है। सरकार ने बजट में इस ओर ध्यान दिया है। कोसी-मेची अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना से जहां एक ओर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में दो लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। वहीं बाढ़-बरसात के समय कोसी के अतिरिक्त जल को मेची नदी के जरिये महानंदा में भेजकर जल प्रबंधन भी किया जाएगा।

कोसी-मेची लिंक से लाभ : मेची महानंदा की सहायक नदी है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत पूर्वी तटबंध से 76.20 किमी नहर बनाकर उसे मेची नदी से जोड़ा जाएगा, ताकि कोसी के पानी को मेची के जरिये महानंदा में भेजा जा सके और इन नदियों के बेसिन में नहरों का विकास कर सिंचाई सुविधा को विस्तार दिया जा सके। इसके तहत अररिया में करीब 69 हजार हेक्टेयर, किशनगंज में 39 हजार हेक्टेयर, पूर्णिया में 69 हजार हेक्टेयर और कटिहार में 35 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। बताते चलें कि कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना 49 साल पहले ही बनाई गई थी। कतिपय कारणों से यह मूर्तरूप नहीं ले सकी। 2022 में इस परियोजना को स्वीकृति मिली। इस परियोजना में 1397 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

****

राजनीति

26,000 करोड़ रुपये का प्रबंध किया जाएगा बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए बजट में। इस राशि से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे एवं बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे के विकास के साथ-साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली एवं दरभंगा सड़क संपर्क योजनाओं पर काम होगा

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बहार का एक्सप्रेस-वे

अरविंद शर्मा • जागरण

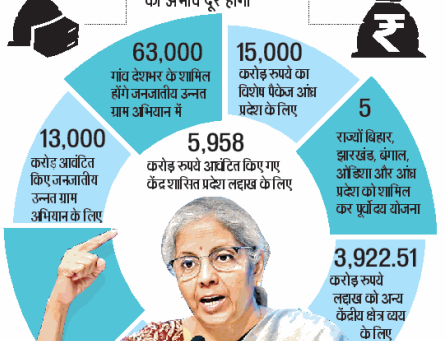

नई दिल्ली: केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका और डबल इंजन सरकार का असर आम बजट में भी दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में बिहार को ही केंद्र में रखा। विशेष राज्य का दर्जा तो खैर संवैधानिक रूप से भी संभव नहीं है, लेकिन राज्य में एक्सप्रेस-वे निर्माण से लेकर पर्यटन को प्रोत्साहन एवं बाढ़ नियंत्रण तक की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का खजाना खोल दिया। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार को लगभग 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सौगात दी है। बिहार में अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में आम बजट में बिहार के लिए घोषणाओं को राजनीति के नजरिए से भी देखा जा रहा है।

मात्र दो दिन पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में जदयू की ओर से बिहार के लिए विशेष राज्य या विशेष पैकेज की मांग की गई थी। इस दौरान केंद्र का ध्यान बिहार की बड़ी आपदा बाढ़ की ओर भी आकृष्ट किया गया था। एक दिन पहले सदन में केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के आग्रह को संवैधानिक प्रविधान का हवाला देकर खारिज कर दिया था। इस पर बिहार में विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष की काफी किरकिरी की थी। किंतु वित्त मंत्री ने मंगलवार को बजट के जरिए न केवल बिहार की झोली भर दी, बल्कि भाषण में बार-बार उन योजनाएं एवं उसके लिए आवंटित राशि का विशेष तौर पर उल्लेख किया।

बिहार को गरीब राज्य के रूप में जाना जाता है। राज्य में उद्योग-धंधे के साथ आधारभूत संरचना का अभाव है। केंद्र की सहायता से अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर पड़ने वाले गया जिले के डोभी में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। इसे अन्य सांस्कृतिक केंद्रों के लिए आधुनिक अर्थव्यवस्था के माडल के रूप में विकसित किया जाना है, जो विकास भी विरासत भी का प्रतिबिंब होगा। बिहार को पूर्वोदय योजना में शामिल कर आर्थिक अवसरों का सृजन किया जाएगा।

पर्यटन मानचित्र पर भी बिहार: बिहार को पर्यटन मानचित्र पर भी उभारने की योजना है। गया स्थित विष्णुपद मंदिर एवं बोधगया के महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थस्थल एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों तीर्थस्थलों की काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर माडल के अनुरूप समग्र विकास करने की योजना है। राजगीर के लिए समग्र विकास की पहल होगी। वहां के हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीर्थस्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास टूरिज्म सेंटर की तरह किया जाएगा, ताकि इसका पुराना गौरव लौट सके।

2400 मेगावाट के नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी भागलपुर के पीरपैंती में

बिहार को और क्या-क्या मिला

बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए बजट में 26 हजार करोड़ रुपये का प्रबंध किया जाएगा। इस राशि से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे एवं बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे के विकास के साथ-साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली एवं दरभंगा सड़क संपर्क योजनाओं पर काम होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त बिहार में 21 हजार चार सौ करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे कोसी-मेची नदी अंतरराज्यीय लिंक, बैराजों और सिंचाई परियोजनाओं समेत 20 अन्य चालू योजनाओं के लिए वित्तीय मदद मिलेगी।

बजट की फुहार से नीतीश प्रसन्न, ठंडी पड़ी विशेष राज्य के दर्जे की मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए एकमुश्त 59 हजार चार सौ नौ करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर वित्त मंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को बहुत हद तक ठंडा कर दिया है। लंबे समय से विशेष राज्य की मांग और इसके लिए पटना से नई दिल्ली तक आंदोलन करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने भी बजट में राज्य के लिए विशेष प्रविधान पर संतोष प्रकट किया है। उन्होंने संकेत दिया कि वह विशेष दर्जा के साथ-साथ विशेष सहायता की भी मांग कर रहे थे। उनकी यह मांग पूरी हो गई है। नीतीश को भरोसा है कि केंद्र सरकार से बिहार को और कुछ मिलेगा। कहा- हम उम्मीद करते हैं कि नए बजटीय प्रविधान से राज्य का तेज विकास होगा।

जदयू के शांत होने के बाद मुख्य विपक्षी दल राजद ने विशेष राज्य के मुद्दे को अपने पाले में कर लिया है। राजद के सांसद डा. मनोज कुमार झा ने विशेष राज्य के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष की घोषणा की है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में भी विशेष राज्य की मांग पर विरोधी दल के सदस्यों ने शोर-शराबा किया। बजट में बिहार के लिए जो नए प्रविधान किए गए हैं, उनमें से अधिसंख्य आधारभूत संरचना क्षेत्र के हैं। 26 हजार करोड़ चार सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। 21 हजार चार सौ करोड़ रुपये का प्रविधान बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए किया गया। इसके अलावा नए हवाई अड्डे, मेडिकल कालेज और खेलकूद की अधिसंरचना के निर्माण की भी घोषणा की गई है। साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये की कोसी-मेंची लिंक परियोजना एवं बाढ़ बचाव योजना में सहायता देने का भी आश्वासन दिया गया है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी साढ़े 11 हजार करोड़ की घोषणा की गई है। सीतारमण ने पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन देने की भी घोषणा की है।

बजट बोल

पिछले 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूत नींव रखी है। बजट इन प्रयासों की निरंतरता को दर्शाता है। बजट में एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

– **अश्विनी वैष्णव**, केंद्रीय मंत्री

बजट निराशाजनक है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। बिहारवासियों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जुमला पार्टी पुरानी योजनाओं को नया बताने की अपनी विशेषज्ञता का विशिष्ट प्रदर्शन कर जनता को फिर भ्रमित कर रही है।

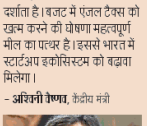

– **तेजस्वी यादव**, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने जैसी हमारी मांगों को बजट में स्थान नहीं दिया गया। हालांकि बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार, कौशल विकास के साथ धार्मिक पर्यटन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को इस क्षेत्र के लिए लाभकारी माना जा रहा है।

–**प्रदीप शेट्टी, प्रेसिडेंट**, फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया

लद्दाख के लिए बजट आवंटन में 32 प्रतिशत की हुई वृद्धि

4,500 करोड़ रुपये पिछले वर्ष किया गया था आवंटन

नई दिल्ली, प्रेट्र: बजट में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन से 32 प्रतिशत अधिक है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपने सचिवालय से संबंधित खर्चों और अन्य विभागों और कार्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र से 2,035.49 करोड़ रुपये मिले हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में लद्दाख को अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय के लिए 3,922.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें कृषि और संबद्ध योजनाएं, जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, बिजली, वानिकी और वन्यजीव, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।

नई दिल्ली में आम बजट 2024-25 पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति भवन पहुंचीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलातीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु • सौ. राष्ट्रपति भवन

विभाजन के 10 साल बाद खत्म हुआ आंध्र प्रदेश का विशेष पैकेज का इंतजार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : विभाजन के 10 साल बाद आखिरकार आंध्र प्रदेश का केंद्रीय पैकेज का इंतजार खत्म हुआ। बदले हुए राजनीतिक समीकरण को देखते हुए केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत इसी साल आंध्र को 15 हजार करोड़ की केंद्रीय सहायता मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने की भी घोषणा की है। ध्यान देने की बात है कि 16 सांसदों के साथ तेदेपा राजग का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है।

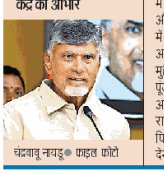

वित्तमंत्री ने हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के बाद आंध्र को नई राजधानी के लिए विशेष वित्तीय सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है। उनके अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में केंद्र सरकार की ओर से की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समन्वित प्रयास किया गया है। 2014 में तेलंगाना के अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू की तत्कालीन सरकार ने अमरावती को नई राजधानी के रूप में विकसित करने का एलान किया था। लेकिन 2019 में जगन मोहन रेड्डी के सत्ता में आने के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। राजग के साथ ही सत्ता में वापसी के बाद चंद्रबाबू ने फिर से अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। सीतारमण ने कहा कि इसके लिए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। वित्तमंत्री ने सालों से लटकी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए फंड उपलब्ध कराकर उसे जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

प्रेट्र के मुताबिक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू ने बजट में आंध्र प्रदेश को फंड आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए नायडू ने कहा कि केंद्र से मिलने वाला समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में बहुत मददगार साबित होगा।

- पोलावरम सिंचाई परियोजना और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए मिलेगा फंड
- आंध्र को फंड आवंटित करने के लिए चंद्रबाबू ने जताया केंद्र का आभार

चंद्रबाबू नायडू • फाइल फोटो

फंड जुटाने में सफल रहे चंद्रबाबू

चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से औद्योगिक विकास की परियोजनाओं के भी फंड जुटाने में सफल रहे। सीतारमण ने विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों की आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए फंड मुहैया कराने का एलान किया। इसके तहत पूंजीगत निवेश के लिए इस साल अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। साथ ही आंध्र के रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय पिछड़े इलाके के विकास को भी अनुदान देने का वादा किया गया।

पूर्वोदय : विकास के उजियारे में राजनीतिक जमीन पर भी नजर

जितेंद्र शर्मा • जागरण

नई दिल्ली : राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भविष्य की चिंता सिर्फ विकास और रोजगार के दृष्टिकोण से ही नहीं दिखी, बल्कि इस पर 'पालिटिकल रोडमैप' की छांव भी दिखाई दी। गठबंधन सहयोगी दलों की खातिर सरकार ने यदि बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष प्रेम दिखाया है तो पूर्वोदय योजना की घोषणा कर यह संदेश भी दे दिया कि विकास की रोशनी फैलाते हुए उसकी नजर अन्य राज्यों में भी राजनीतिक जमीन मजबूत करने या बनाए रखने पर भी होगी। योजना के तहत सरकार ने देश के पूर्वी भाग के राज्यों सहित बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आंध्र के चहुंमुखी विकास का वादा किया है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्पष्ट कहा कि देश के पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इन राज्यों की सांस्कृतिक परंपराएं सुदृढ़ हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी राज्यों के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करेगी। इस योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसर तैयार करना शामिल है ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएं। सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं भी स्थापित करेगी। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र के लिए का पिटारा खोल दिया। इन दो राज्यों के लिए दिए गए बजट का प्रत्यक्ष संदेश यही है कि दोनों जगह भाजपा के सहयोगी दलों के नेतृत्व में राजग सरकार चल रही हैं, जिनमें से बिहार में अगले वर्ष विस चुनाव होने हैं। वहीं, पूर्वोदय में शामिल अन्य राज्यों का भी अपना महत्व है। झारखंड में इसी वर्ष चुनाव होने हैं। ओडिशा में लंबे समय से सत्तासीन बीजू जनता दल को बेदखल कर भाजपा ने सरकार बनाई है तो वह अब वहां अपने पैर विकास के सहारे मजबूती से जमाना चाहती है। इसी तरह बंगाल में भाजपा लंबे समय से संघर्षरत है और अपना आधार बनाने को प्रयास कर रही है। अब पूर्वोदय योजना के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से बड़ी विकास योजनाएं इन राज्यों में शुरू की जाएंगी।

- पूर्वी राज्यों के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नाम से योजना शुरू करेगी सरकार
- बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा व आंध्र प्रदेश को शामिल कर दिया अहम संदेश

आदिवासी वर्ग को लेकर भी बजट में दिखी चिंता

इस बार लोस चुनाव में भाजपा को आदिवासी आरक्षित सीटों पर काफी नुकसान हुआ है। इसका संदेश यह गया कि बीते दो चुनावों में जो आदिवासी वर्ग भाजपा के करीब आया था, वह कुछ विमुख हुआ है। हालांकि, सरकार ने इस वर्ग को लेकर बजट में काफी चिंता दिखाई है। घोषणा की है कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को कवर किया जाएगा। इस अभियान में देशभर के 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2023-24 के बजट में यह 7,605 करोड़ था, जबकि इस बार 13,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

त्वरित टिप्पणी

अनुभव पर आधारित व्यावहारिक बजट

आशुतोष झा •

डेढ़ महीने पहले जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद बजट को लेकर कुछ बातें बहुत स्पष्ट थीं। यह तय माना जा रहा था कि सरकार तेजी से रोजगार बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इसके लिए मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान बढ़ाना जरूरी होगा। यह भी होना था कि मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिले और बिहार और आंध्र प्रदेश के अहम सहयोगियों जदयू और टीडीपी की आर्थिक जरूरतों का ख्याल रखा जाए। यह सब हुआ। यह चुनावी नतीजों के अनुभव का निचोड़ है। लेकिन एक और बात जिसमें सरकार के दस साल का अनुभव दिखा वह है -बड़े सुधारों की घोषणा से बचते हुए राज्यों को साथ लेकर चलने का। दरअसल यही सच्चाई है कि राज्य जबतक केंद्र के साथ कदमताल नहीं करेंगे, देश का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्हें एक मंच पर आना या लाना ही होगा। इसकी ठोस शुरुआत होती दिख रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार की पुरानी छवि से इतर इस बार बड़े और सख्त सुधारों के बजाय बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए राज्यों को प्रेरित करने की कोशिश हो रही है।

लोकसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहा था। विपक्ष की ओर से इसे केंद्रित करते हुए लुभावने वादे भी किए गए थे। अगले कुछ महीनों में तीन-चार राज्यों में चुनाव भी हैं जिसके नतीजे राजनीति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी अहम होंगे। ऐसे में पहले बजट में मोदी सरकार ने रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा तत्परता दिखाई है। यह सच्चाई है कि सरकारी नौकरियां बहुत नहीं बढ़ सकती हैं लिहाजा निजी सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल हुई है। यह जरूरी था क्योंकि कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर युवा परेशान हो।

यह बजट चुनावी नतीजों के अनुभव का निचोड़ है। लेकिन एक और बात जिसमें सरकार के दस साल का अनुभव दिखा वह है -बड़े सुधारों की घोषणा से बचते हुए राज्यों को साथ लेकर चलने का

अब दावा किया जा रहा है कि अगले पांच साल में चार करोड़ रोजगार का सृजन होगा। जरूरत इसकी लगातार मानीटरिंग की होगी क्योंकि इसके लिए लगातार निजी सेक्टर की परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। श्रम सुधार पर तेज कदम बढ़ते तो और रोजगार सृजन में और तेजी आ सकती थी लेकिन सरकार थोड़ी ठिठकी नजर आ रही है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि इसे बहुत दिन तक रोका नही जा सकता है। आज या कल सरकार को इसे बढ़ाना ही होगा। मध्यम वर्ग अर्से से नाराज था कि उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। टैक्स में राहत दे दी गई। हालांकि यह राहत मामूली है लेकिन सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि वह आगे भी कुछ करना चाहती है। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ न कुछ होगा।

आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष घोषणाओं का राजनीतिक पहलू भी है लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन्हें विशेष मदद की जरूरत है। इन घोषणाओं के बाद इन दोनों राज्यों की तरफ से जैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बाद एक अंश भी संशय नहीं कि सरकार पूरी तरह स्थायी है। हालांकि भविष्य में सरकार को विशेष मदद के लिए कमर कस कर तैयार रहना होगा।

अनुभव ने सरकार को बता दिया है कि कृषि सुधार, भूमि सुधार और अधिग्रहण जैसे जरूरी लेकिन विवादित सुधार कार्य शुरू नहीं किए जा सकते हैं। लिहाजा राज्यों की राह ली गई है। पूरे बजट से जो सार निकलता है वह यह है कि राज्यों के रास्ते से ही सुधार अपनाए जाएंगे। आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाकर आगामी सुधारों के नये लक्ष्य तय किए जाएंगे। सुधार करने वाले राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की व्यवस्था हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी कि सरकार उत्पादकता में सुधार और बाजारों व विभिन्न सेक्टरों को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए सुधार करेगी। इनमें भूमि, श्रम, पूंजी क्षेत्र में सुधार भी शामिल हैं। इनमें से कई सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग व आम सहमति आवश्यक है क्योंकि राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव है। केंद्र व राज्य मिल कर जो सुधार करेंगे उनमें प्रमुख है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार।

कुछ बातें चकित करती हैं। निर्मला सीतारमण ने रक्षा, गृह, शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य जैसे मंत्रालयों से संबंधित किसी मुद्दे पर घोषणा तो दूर उनकी उपलब्धियों तक पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। ऐसा क्यों? यह सच है कि कुछ घटनाओं को लेकर कुछ मंत्रालयों के नाम लेने से भी विपक्ष उग्र हो रहा है। लेकिन इतने भर से रक्षात्मक होने की जरूरत तो नहीं दिखती। हो सकता है यह भी अनुभव का हिस्सा हो।

बजट घोषणाओं ने विपक्ष को भी नहीं दिया विघ्न डालने का मौका

संजय मिश्र • जागरण

नई दिल्ली : लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत भले ही आम चुनाव में मोदी सरकार की लगातार तीसरी जीत को उसकी नीतियों के प्रति जनता के विश्वास के दावे से की, मगर उनकी बजट घोषणाओं में इस विजय का बहुत उत्साह दिखाई नहीं दिया। राजग सरकार के दो प्रमुख राजनीतिक पहिए जदयू और तेलुगुदेसम को साधने के लिए बिहार एवं आंध्र प्रदेश के लिए कुछ सौगातों की घोषणाओं के सिवाय सदन में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने का कोई मौका वित्त मंत्री ने विपक्ष को तो क्या सत्ता पक्ष को भी नहीं दिया। सरकारी योजनाओं से जुड़ी कुछ बजटीय घोषणाओं को लेकर वित्त मंत्री ने सत्तापक्ष के सांसदों की ओर से मेजें थपथपाने की औपचारिकता की गूंज कई बार अपने खाते में दर्ज कराई, मगर यह भी उस सीमा तक नहीं पहुंची कि राजग सदस्य उमंग का इजहार करने को मचल जाएं।

निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 11वें बजट के साथ अपना लगातार सातवां बजट पेश किया। टैबलेट पर अंग्रेजी में 85 मिनट के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री को एक मिनट के लिए भी किसी तरह की विघ्न-बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। जबकि आम चुनाव में संख्या बल के साथ मजबूत होकर उभरा विपक्ष अपनी पूरी क्षमता से सदन में मौजूद था। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए वित्त मंत्री ने जब घोषणाएं शुरू कीं तो सदन में विपक्षी बेंचों की ओर से कुछ तंज-तीर चलाते हुए टोका-टाकी की गई, जिसमें कहा गया कि जदयू और तेदेपा के समर्थन की कीमत चुकाई गई है। बंगाल से तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी से लेकर पंजाब के कुछ कांग्रेस सांसदों ने इस पर अपने राज्यों की अनदेखी के सवाल उठाते हुए ताने मारे। वहीं, द्रमुक नेता दयानिधि मारन ने तमिलनाडु के साथ नाइंसाफी का दावा करते हुए आक्रामकता दिखाई। आंध्र को नई राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ देने की घोषणा पर छींटाकशी सबसे ज्यादा हुई और कांग्रेस तथा टीएमसी सदस्यों ने इसे 'सरकार बचाओ, खजाना खाली करो' योजना बताने से गुरेज नहीं किया। वित्त मंत्री ने जब शिक्षा ऋण से जुड़ी योजना की घोषणा की तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अच्छा है आप बंगाल माडल का अनुसरण कर रही हैं। भाजपा सांसदों ने जवाबी शोर से इसका प्रतिकार किया।

बजट के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों इस हल्की-फुल्की गहमागहमी की परिधि से बाहर निकलने के न इच्छुक दिखे और न ही ऐसा कोई मौका आया। भाजपा सांसदों ने बजट पेश होने से ठीक पहले सदन में पहुंचे पीएम मोदी का खड़े होकर स्वागत करने के दौरान भारत माता की जय के नारे कुछ क्षणों तक लगाते हुए राजनीतिक गहमागहमी के लिए तैयार रहने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहली पंक्ति की पहली बेंच से हर बजट घोषणा पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते दिखे। निर्मला सीतारमण पहली पंक्ति में ही दूसरी बेंच से अपना बजट भाषण पढ़ रही थीं और स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी बगल में बैठे थे। विपक्षी बेंच की अगुआई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे थे जो गंभीरता से बजट भाषण सुनते आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और द्रमुक नेता टीआर बालू राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में विपक्षी बेंच का मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं, टीएमसी के सुदीप बंधोपाध्याय व सौगात राय पहली पंक्ति में होने के बावजूद दूसरे दिनों के मुकाबले कुछ शांत नजर आए।

बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों के सांसदों ने अपने राज्यों की अनदेखी के दावे कर उठाए सवाल

85 मिनट के सीतारमण के बजट भाषण में चंद तंज-तीरों, टोका-टाकी की सीमा में ही रहा पक्ष-विपक्ष का संवाद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट 2024-25 प्रस्तुत किया • एएनआइ

****

2.62 लाख करोड़ रुपये आवंटित रेलवे को राशि में से लगभग 50 प्रतिशत संरक्षा कार्य पर खर्च होंगे। इससे उत्तर रेलवे में चल रही और प्रस्तावित योजनाओं के काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आज का मौसम

सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसार है।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
24 जुलाई	34.0	26.0
25 जुलाई	35.0	27.0
नोएडा		
24 जुलाई	36.0	27.0
25 जुलाई	36.0	27.0
गुरुग्राम		
24 जुलाई	33.0	29.0
25 जुलाई	35.0	29.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

अमेरिकी महिला से धोखाधड़ी मामले में आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली: अमेरिका की एक महिला से कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में ईडी ने दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत लक्ष्य विज को सोमवार रात गिरफ्तार किया। विज को विशेष अदालत के समक्ष पेश कर ईडी हिरासत में पूछताछ करने के लिए उसे रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध करेगी। आरोपित के खिलाफ अमेरिकी महिला से कथित तौर पर ठगी करने से जुड़े साइबर धोखाधड़ी के मामले में जांच की जा रही है। (प्रेट्र)

एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने एम्स से मांगा जवाब

नई दिल्ली: एम्स के एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) क्लीनिक में तोड़फोड़ व एचआइवी संक्रमित मरीजों के रिकार्ड फेंके जाने के मामले पर दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने संज्ञान लिया है। सोसाइटी ने एम्स के निदेशक डा. एम श्रीनिवास को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एम्स सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा है। (राब्यू)

एसआइ और एएसआइ रिश्वत लेते गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली में पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने से आजिज आकर आए दिन लोग उनके खिलाफ सीबीआइ में शिकायत कर रहे हैं, जिससे सीबीआइ थानों व यूनिटों में छापा मार पुलिसकर्मियों को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर रही है। ताजा मामला मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी जिले के सरिता विहार थाने का सामने आया है। सुबह छह बजे सीबीआइ ने सरिता विहार थाने में छापा मारकर एसआइ राज कुमार व एएसआइ रघुराज को 35 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। (जासं)

दिल्ली को 1168 करोड़ रुपये का आवंटन

बजट 2024 ▸ केंद्रीय सहायता के रूप में 951 करोड़ और पूंजीगत मद में 200 करोड़ मिले

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

केंद्रीय बजट में दिल्ली सरकार को अलग-अलग मदों में 1,168 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। केंद्रीय करों में भागीदारी के नाम पर 2022-23 तक मिलने वाले 325 करोड़ रुपया इस बार नहीं दिया गया है। केंद्र की माने तो केंद्रीय सहायता के रूप में किए गए आवंटन में ही केंद्रीय करों की सहायता राशि को शामिल किया गया है। दिल्ली को केंद्रीय सहायता के रूप में 951 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद में 200 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।

बजट के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली सरकार को मिले 1,168 करोड़ रुपये में से बीते साल की तरह दो करोड़ रुपये सिख दंगा पीड़ितों के लिए आवंटित किया गया है। आपदा प्रबंधन फंड के तौर पर 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन जो पिछले साल शुरू किया गया था, इस बार भी दिया गया है।

इसके अलावा केंद्र शासित राज्यों को अगला केंद्रीय सहायता के रूप में कुल 951 करोड़ रुपये दिए हैं, जो कि पिछले साल के बराबर है। इसके अलावा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में दिल्ली सरकार को 200 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत योजना के तहत दी गई है।

चार चिकित्सा संस्थानों को भारी राशि का प्रविधान

रणविजय सिंह ● जागरण

▸ दिल्ली के स्वास्थ्य बजट से ज्यादा एम्स, सफदरजंग, आरएमएल व एलएचएमसी को मिली राशि

▸ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य का बजट है 8,685 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है 40 अस्पताल

नई दिल्ली: राजधानी में स्थित केंद्र सरकार के चार प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के लिए केंद्रीय बजट में भारी भरकम राशि का प्रविधान किया गया है। इस वजह से एम्स, सफदरजंग, आरएमएल अस्पताल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (एलएचएमसी) इन चार चिकित्सा संस्थानों का बजट दिल्ली के स्वास्थ्य बजट के पार पहुंच गया है। इन चारों चिकित्सा संस्थानों पर दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था का बड़ा दारोमदार है। इसलिए बजट में भारी भरकम प्रविधान किए जाने से इन चिकित्सा संस्थानों में इलाज की सुविधाओं में सुधार होगा।

वैसे एम्स, आरएमएल और एलएचएमसी व उससे जुड़े कलावती सरन अस्पताल का बजट एक फरवरी के अंतरिम बजट के बराबर ही बरकरार रखा गया है। सिर्फ सफदरजंग अस्पताल के बजट में करीब 40 करोड़ की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। इस वजह से पिछले वित्त वर्ष (वर्ष 2023-24) की तुलना में सफदरजंग अस्पताल का बजट करीब 40 करोड़ बढ़ गया है। इससे उम्मीद है कि अस्पताल में नई सीटी स्कैन मशीन व अन्य अत्याधुनिक उपकरण लगाने में मदद मिलेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में इन चार प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के लिए कुल 8,937 करोड़ बजट का प्रविधान किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब नौ प्रतिशत अधिक है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य का बजट 8,685 करोड़ है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग एलोपैथी व आयुष के अस्पतालों को मिलाकर 40 अस्पतालों का संचालन करता है। इसके अलावा डिस्पेंसरियां व 500 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक भी हैं। परियोजनाओं व विभिन्न कार्यक्रमों पर भी स्वास्थ्य विभाग को खर्च करना होता है। फिर भी इसकी तुलना में केंद्र के उक्त चारों प्रमुख चिकित्सा संस्थानों का बजट 252 करोड़ अधिक पहुंच गया है। एम्स को 4,500 करोड़ से अधिक का बजट मिला है। इससे संस्थान को चिकित्सा सुविधाओं के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आरएमएल अस्पताल के बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 338 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इससे निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक का संचालन जल्द शुरू करने में मदद मिलेगी।

प्रतीकात्मक

केंद्र के प्रमुख अस्पतालों का बजट (करोड़ रुपये में)

अस्पताल	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
एम्स	4,134.67	4,523.00
सफदरजंग	1,853.34	1,874.00
आरएमएल	1,272.18	1,610.00
एलएचएमसी	768.15	750.00
कलावती सरन	168.53	180.00
कुल	8,196.87	8,937

नोट : कलावती सरन अस्पताल एलएचएमसी का ही हिस्सा है।

केजरीवाल सरकार की मांग से अधिक मिला दिल्ली को धन : वीरेंद्र सचदेवा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

वीरेंद्र सचदेवा

भाजपा ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। भाजपा नेताओं ने इसे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बताया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केंद्रीय बजट में दिल्ली को केजरीवाल सरकार की मांग से अधिक धन मिला है। सरकार ने दिल्ली से मिलने वाले प्रत्यक्ष करों का 10 प्रतिशत (करीब 21 हजार करोड़ रुपये) की मांग की थी, लेकिन बजट में विभिन्न मद में इससे अधिक धन दिल्ली के लिए आवंटित किया गया है। दिल्ली के लिए बजट में 1,168 करोड़ रुपये का प्रविधान है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के लिए 11,180 करोड़ रुपये और दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रविधान है। मेट्रो, राष्ट्रीय राजमार्ग, नमो ट्रेन, एनडीएमसी, एम्स सहित दिल्ली में स्थित केंद्र के अन्य अस्पतालों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों व अन्य कार्य के लिए केंद्र से 50 हजार करोड़ से अधिक का बजट मिला है। यह राशि दिल्ली से एकत्रित प्रत्यक्ष करों का लगभग 30 प्रतिशत है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए बेहतर होगा कि वह दिल्लीवासियों को गुमराह करना बंद करे, क्योंकि दिल्लीवासी केंद्र के योगदान के बारे अच्छी तरह से जानते हैं।

केंद्रीय करों में दिल्ली को एक पैसा भी हिस्सा नहीं : आतिशी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दावा किया कि भाजपा नीत केंद्र को 2.32 लाख करोड़ रुपये का कर चुकाने के बावजूद केंद्रीय बजट में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए 10 हजार करोड़ और दिल्ली एमसीडी के लिए भी इतनी ही राशि के बजटीय आवंटन की मांग की थी। इसके बावजूद केंद्र ने न तो टैक्स शेयर में और न ही एमसीडी के लिए दिल्ली को एक पैसा दिया। उन्होंने चुनौती दी कि पिछले 11 बजटों में दिल्ली के लिए एक भी काम दिखाएं।

दिल्ली के पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा के प्रति उदासीनता : देवेंद्र

राज्य ब्यूरो जागरण ● नई दिल्ली: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में दिल्ली की सुरक्षा, स्वच्छता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों की आवासीय जरूरतों के प्रति उदासीनता दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पूरा बजट निराशाजनक और कुर्सी बचाने वाला नजर आता है। यादव ने कहा कि भाजपा ने पीएम आवास योजना का पिछले बजट से 22,487 करोड़ वापस कर दिए, जबकि दिल्ली में झुग्गी वासियों को लगातार उजाड़ा जा रहा है। रेहड़ी-पटरी वालों को मिलने वाले पिछले वर्ष के बजट 468 करोड़ को इस वर्ष घटाकर 326 कर दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान पर केंद्र सरकार का जोर

संजीव गुप्ता ● जागरण

▸ पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब सौ करोड़ रुपये अधिक आवंटित

▸ सीपीसीबी और सीएक्यूएम के बजट आवंटन में भी देखी गई वृद्धि

नई दिल्ली: वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी केंद्र सरकार की गंभीरता-प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। जहां राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान (एनसीएपी) के बजट में इजाफा किया गया, वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के बजट में भी वृद्धि की गई है। बजट में कई योजनाएं भी अपरोक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण की ओर संकेत करती हैं।

बजट में उल्लेख है कि एनसीएपी को वित्त पोषित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों व समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में प्रदूषण नियंत्रण की संकल्पना की गई है। इसी के मद्देनजर इस वर्ष एनसीएपी के लिए करीब 850 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 100 करोड़ रुपये अधिक है। सीपीसीबी को वित्त वर्ष 2023-24 में 72.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस वर्ष इसमें 21 करोड़ से अधिक का इजाफा करते 94.00 करोड़ का प्रविधान किया गया है। इसी तरह सीएक्यूएम को गत वर्ष 2.50 करोड़ आवंटित हुए थे, जबकि इस राशि को बढ़ाकर 5.36 करोड़ कर दिया गया है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भी इस साल 73 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ आवंटित किए गए। सीपीसीबी के सदस्य डा. अनिल गुप्ता ने बजट में पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखे जाने का स्वागत किया है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी कहती हैं कि पर्यावरण क्षेत्र में उन्नत फंडिंग रणनीति के साथ-साथ दीर्घकालिक नीति रोडमैप की आवश्यकता होती है।

एमएसएमई की मजबूती से सुदृढ़ होगी राजधानी की अर्थव्यवस्था

नेमिष हेमंत ● जागरण

जिनेश जैन।

मुकेश

पंकज जैन

▸ औद्योगिक संगठनों ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा पहली बार बजट में हुई उनकी समस्याओं के निराकरण की बात

▸ नए उद्यमी होंगे प्रोत्साहित, पुराने कर सकेंगे विस्तार, दूर होगी कुशल श्रमिकों की कमी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली: विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ने की दिशा में जिस तरह से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एमएसएमई क्षेत्र को विशेष स्थान दिया है। उससे आम तौर पर हर बजट पर निराशा जताने वाला दिल्ली का सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग जगत इस बार खासा खुश है। बल्कि, कमर कस मैदान में उत्साहपूर्वक उतरने की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस बजट में उनके लिए काफी कुछ है।

राष्ट्रीय राजधानी के युवा उद्यमी कहते हैं कि यह दूरगामी बजट है और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मजबूत आधार स्तंभ बनने वाला है। इससे देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। बजट से न सिर्फ आयात पर निर्भरता घटेगी, बल्कि कुशल श्रमिक और बेराजगारी की बड़ी खाई खत्म होगी। दिल्ली में करीब दो लाख औद्योगिक इकाईयां है, जो तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। हालांकि, एक स्थिति यह भी है कि औद्योगिक इकाईयां अभी भी 70 प्रतिशत तक कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रही हैं।

लघु उद्योग भारती के महामंत्री मुकेश अग्रवाल के अनुसार, इस बजट में कई ऐसे प्रविधान है, जो एमएसएमई क्षेत्र के साथ देश के अर्थतंत्र व समाज पर बड़े प्रभाव डालने वाले हैं। इस तरह से जोर रहा तो देश की कई समस्याओं का हल निकल सकता है, जिसमें बेरोजगारी और आयात प्रमुख है। अग्रवाल के अनुसार मुद्रा योजना में ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। इससे वह युवा उद्यमी प्रोत्साहित होंगे जो छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं। इससे हस्तनिर्मित उत्पादों के साथ हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी तरह निर्धारित अवधि में बकाया भुगतान की समस्या के निराकरण के मद्देनजर ट्रेस पोर्टल में पंजीकरण की सीमा 500 करोड़ रुपये सालान कारोबार को घटाकर 250 करोड़ कर दी है। हालांकि, उद्यमी इसे 100 करोड़ रुपये तक करने की मांग कर रहे थे। फिर भी इस निर्णय से औद्योगिक क्षेत्र में भुगतान का माहौल सुधरेगा।

गारंटी ऋण से मिली उद्यमियों को बड़ी राहत

100 करोड़ रुपये तक की मशीनों की खरीद पर बिना गारंटी ऋण का निर्णय बड़ी राहत देने वाला है। इससे उद्योग में आधुनिक मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। कार्य क्षमता बढ़ेगी। बजट में 12 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। औद्योगिक ढांचा तैयार कर किराए पर देने की बात है। इससे उद्योग लगाने की लागत में काफी कमी आएगी। यह उद्यमियों की पुरानी मांग थी, जिसे इस बजट में ध्यान में रखा गया है।

अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुकेश अग्रवाल के अनुसार, युवाओं को नौकरी देने पर सरकार ने तीन माह में 15 हजार रुपये देने की घोषणा की है। इससे अधिक लोगों को काम मिलने के साथ श्रमिकों को पीएफ के अंदर लाया जाएगा। इससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। उद्यमी नए बच्चों को अपने यहां कुशल बनाने को प्रोत्साहित होंगे।

अर्थव्यवस्था की रीढ़ होगी मजबूत

फ्रेंड्स कालोनी औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष पंकज जैन ने कहा कि पहली बार ऐसा है कि जब बजट में एमएसएमई क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया है। पहले इतने विस्तार से कभी भी बात नहीं होती थी। जेपीटी ग्लोबल आटोमोटिव के प्रबंध निदेशक जिनेश जैन कहते हैं कि इससे उद्योग जगत में खुशी की लहर है।

यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की करंट से मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मृतक नीलेश

पटेल नगर की घटना, वर्षा के दौरान लोहे के गेट में करंट उतरने से हुआ हादसा

रणजीत नगर थाना पुलिस को दोपहर 2.43 बजे घटना की सूचना मिली थी। यहां गली के कोने में वर्षा का पानी भरा हुआ था। छात्र को लोहे के गेट से करंट लगा था, छानबीन के बाद इस संबंध में सोमवार को ही मामला दर्ज कर लिया गया। जांच जारी है।
– एम. हर्षवर्धन, मध्य जिला पुलिस उपायुक्त

पटेल नगर में करंट से छात्र की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ग्राहक की क्षतिग्रस्त मोटर वायरिंग से लीक हुए करंट के कारण हुई है। सूचना पर ब्रेकडाउन टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। हम लोगों से मानसून के मौसम में सावधान रहने और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने, गिरी हुई तारों से बचने और किसी भी इलेक्ट्रिकल खतरे को तुरंत रिपोर्ट करने जैसे सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह करते हैं।
–टाटा पावर-डीडीएल के प्रवक्ता

दक्षिणी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में सोमवार को वर्षा के दौरान गली में लगे लोहे के गेट में करंट उतरने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय नीलेश राय के रूप में हुई है। वह पटेल नगर के ब्लाक आठ में पीजी में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। रंजीत नगर थाने में धारा 106 (1), 285 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

नीलेश मूलरूप से गांव देवरिया, जमानिया तहसील, गाजीपुर यूपी का रहने वाला था। परिवार में पिता नरेंद्र कुमार राय, मां नीलम राय और दो बहनें नेहा और निष्ठा राय हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे नीलेश पढ़ाई कर रहा था। वर्षा में ही वह अपने पीजी से चाय पीने के लिए बाहर आया था। वहां से चाय पीकर जब लौटा तो गली के कोने में करीब डेढ़ फीट पानी भरा हुआ था। नीलेश पानी से बचकर एक तरफ से जाने लगा, जैसे ही उसने गली का लोहे का गेट पकड़ा तो करंट की चपेट में आ गया। उसकी चीख सुनकर आसपास खड़े लोग दौड़ पड़े, लेकिन करंट के डर से कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसी बीच एक पड़ोसी ने लकड़ी की सीढ़ी से उसे गेट से हटाने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ सीढ़ी में फंस गया। तभी पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर नीलेश को गेट से हटाया और आरएमएल अस्पताल भेजा, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेकर जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने भी मौका मुआयना कर साक्ष्य एकत्र किए हैं।

प्रशासन की लापरवाही : जिस लोहे के गेट को पकड़ने से छात्र की मौत हुई है वहां बिजली विभाग का खंभा भी है। कई तार टूट कर जमीन पर गिरे हुए हैं। वर्षा के दौरान यहां जलभराव हो जाता है। आशंका है कि जलभराव में बिजली का तार टूटकर गिरने से या इंटरनेट व केबल के तार से करंट फैल गया। लोगों ने नीलेश की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है।

सिर्फ दो बच्चों पर मातृत्व अवकाश नियम की समीक्षा करे सरकार : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी महिला कर्मचारी को दो बच्चों तक मातृत्व अवकाश पाने के अधिकार को सीमित करने वाले सरकारी नियम को लेकर अधिकारियों से केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम के विशेष प्रविधान पर फिर से विचार करने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस नियम के कारण तीसरे और उसके बाद के बच्चे को मातृत्व देखभाल से वंचित होना पड़ता है, जो पहले दो बच्चों को मिला था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा कि तीसरा बच्चा पूरी तरह से असहाय है, इसलिए अदालत का कर्तव्य है कि वह मामले में हस्तक्षेप करे।

कोर्ट ने पूछा कि इसमें तीसरे और उसके बाद के बच्चे का क्या दोष है, जिनका जन्म पर कोई नियंत्रण नहीं था। तीसरे बच्चे को जन्म के तुरंत बाद उसे मातृ स्पर्श से वंचित करना अत्याचार होगा, क्योंकि नियम 43 के अनुसार उस मां को जन्म के अगले दिन ही कर्तव्यों के लिए रिपोर्ट करना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष की बेटी के खिलाफ पोस्ट हटाएं एक्स व गूगल : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ कहा- अंजलि बिरला के खिलाफ प्रथमदृष्टया मानहानिकारक हैं विचाराधीन पोस्ट

भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आइआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स और गूगल को 24 घंटे के अंदर अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।

अंजलि बिरला ने मानहानि मुकदमा दायर कर कहा कि झूठा आरोप लगाकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित किया जा रहा है कि अपने पिता के प्रभाव के कारण पहले प्रयास में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की।

न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने अज्ञात व्यक्तियों को इस मुद्दे के संबंध में अंजलि बिरला के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाने से भी रोक दिया। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह मामला अंजलि के पक्ष में है कि विचाराधीन पोस्ट मानहानिकारक हैं। अंजलि की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि इसी तरह का आरोप पहले वर्ष 2021 में सामने आया था, लेकिन समाचार प्रकाशनों द्वारा फैक्ट-चेक के बाद बिरला के आइआरपीएस अधिकारी होने की जानकारी सार्वजनिक होने पर विवाद खत्म हो गया।

अधिवक्ता संयम खेत्रपाल और आदित्य मनुबरवाला के माध्यम से दायर मानहानि मुकदमे में कहा गया कि कई इंटरनेट मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया कि अंजलि बिरला पेशे से एक माडल हैं और यह ओम बिरला की शक्तिशाली स्थिति के कारण वह अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित तथ्यों के दावों को बेबुनियाद बताते हुए अंजलि ने कहा कि ये इंटरनेट मीडिया हैंडल पूर्व नियोजित साजिश के तहत संचालित किए जा रहे हैं।

ऐसा करने के पीछे मकसद उन्हें व उनके पिता को बदनाम करना है। अंजलि ने 16 एक्स खातों का विवरण प्रदान करके राहत मांगी है। इनमें यूट्यूबर ध्रुव राठी का पैरोडी अकाउंट भी शामिल है। इंटरनेट मीडिया पोस्ट में किए गए दावों के विपरीत, अंजलि आइएएस नहीं बल्कि आइआरपीएस अधिकारी हैं और वर्ष 2019 में यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुईं थी। अप्रैल 2021 में आयोग में शामिल हुईं और उन्होंने पिछले साल अपना अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया।

कुत्ते के काटने से तीन वर्षीय बच्चे में फैला रेबीज, मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : भोजपुर ब्लाक क्षेत्र के गांव बढ़ायला में कुत्ते के काटने से तीन वर्षीय बच्चे की रेबीज के चलते मौत हो गई। कुत्ते ने हमला कर बच्चे को मुंह, गर्दन और छाती पर काटकर जख्मी कर दिया था।

गत 25 जून की शाम को करीब सात बजे गांव बढ़ायला निवासी शिवकुमार का तीन वर्षीय पुत्र नित्यांश घर के बाहर खेल रहा था। उसी समय एक कुत्ते ने नित्यांश पर हमला करते हुए उसके मुंह, गर्दन और छाती पर बुरी तरह से काट लिया। स्वजन व ग्रामीणों ने कुत्ते से बच्चे को छुड़ाते हुए उसे तत्काल मोदीनगर स्थित जीवन हास्पिटल ले गए। जहां पर उसको रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन रेबीज सीरम लगाया गया। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चे को डाग बाइट थर्ड ग्रेड का था। प्राथमिक उपचार करते हुए बच्चे को स्वजन के साथ भेज दिया गया।

मुस्लिम युवक की मौत की जांच सीबीआइ के हवाले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ पुलिसकर्मियों की मारपीट व राष्ट्रगीत गाने को मजबूर करने के बाद हिरासत में लिया था

▸ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- कट्टर मानसिकता से प्रेरित प्रतीत होते हैं संदिग्ध पुलिसकर्मी

दिल्ली दंगों के दौरान राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर करने, मारपीट व चिकित्सा उपचार न देने की वजह से फैजान नाम के युवक की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए जांच सीबीआइ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस पर तल्ख टिप्पणियां की कि जिन पुलिसकर्मियों को कानून के संरक्षक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे कट्टर मानसिकता से प्रेरित थे। कहा कि मामले में जांच न सिर्फ धीमी व अधूरी रही, बल्कि फैजान पर क्रूरतापूर्वक हमला करने में शामिल रहे संदिग्ध पुलिसकर्मियों को आसानी से छोड़ दिया गया है। अदालत ने यहां तक कहा कि पुलिसकर्मियों की गैरकानूनी हरकतें धार्मिक कट्टरता से प्रेरित थीं और पुलिस ने पूरे मामले को दबा दिया था।

फैजान की मां कस्मितुन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में की जांच में कई विसंगतियां पाई गई हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले से जुड़े सभी सुबूत व सामग्री सात दिन के भीतर सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही, सीबीआइ निदेशक को निर्देश दिया कि मामले की जांच को तेजी से करने के लिए एक उचित अधिकारी को लगाया जाए। पुलिस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वर्दीधारी व्यक्तियों द्वारा हेट-क्राइम (घृणा-अपराध) किया जाता है तो घृणा का तत्व बढ़ जाता है। सवाल यह है कि जब फैजान को ज्योति नगर थाने में रखा गया तब क्या उसके साथ कुछ हुआ था। अगर मान भी लिया जाए कि हिरासत में फैजान के साथ कोई हिंसा नहीं हुई, तब भी गंभीर चिकित्सा उपचार की जरूरत के समय उसे थाने में रखा गया था। इसमें अपराध की बू आती है और इससे बदतर कुछ भी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि बताया जा रहा है कि पुलिस थाने में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे उस समय खराब थे, जिसकी वजह से पुलिस के पास कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। इससे पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं जगता है।

यह था मामला : इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित घटना के वीडियो में फैजान को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करते हुए चार अन्य लोगों के साथ पुलिसकर्मी उसे पीट रहे हैं। फैजान की मां ने याचिका में कहा कि पुलिस ने उनके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लिया था और उसे स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर दिया था। ज्योति नगर पुलिस स्टेशन से रिहा होने के 24 घंटे के भीतर शहर के जीटीबी अस्पताल में फैजान की मौत हो गई।

'असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेशों पर रोक लगाएं अदालतें'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाई कोर्ट और सत्र अदालतों को जमानत आदेशों पर रोक लगाने में सोच विचारकर काम करना चाहिए। ऐसा निर्णय बहुत ही दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी आरोपित को दी गई स्वतंत्रता में लापरवाही से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत का फैसला मनी लान्ड्रिंग मामले में आरोपित परविंदर खुराना की याचिका पर आया है, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पिछले साल 17 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट ने खुराना को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत देने पर अदालत केवल असाधारण मामलों में रोक लगा सकती है, जब प्रथम दृष्टया जमानत रद करने का आधार बनता है।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

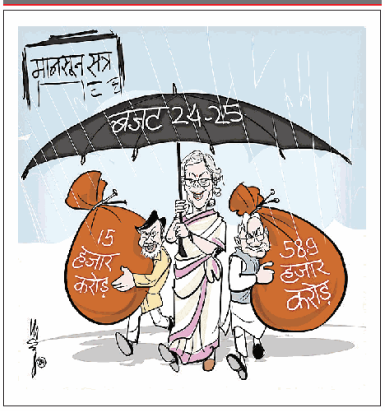

****

दैनिक जागरण

ईश्वर के प्रति भक्ति ही आसक्ति से मुक्ति दिला सकती है

विकसित भारत का लक्ष्य

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही प्रकट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य उनकी निगाह में है। इसी कारण आम बजट अंतरिम बजट की कड़ी दिख रहा है। इस बजट से यह साफ है कि कृषि उत्थान के साथ-साथ रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक था, क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने के वादे सरकार के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये के प्रविधान किए गए हैं। बजट का जोर कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर करने पर है, लेकिन कृषि और किसानों की दशा सुधारने के लिए जो उपाय किए जाने हैं, उन्हें वांछित सफलता तब मिलेगी, जब राज्य सरकारें कृषि संबंधी केंद्रीय योजनाओं को सहयोग देने के साथ किसानों की दशा सुधारने के लिए अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगी। राज्य सरकारों का यह रवैया समस्याजनक है कि कृषि क्षेत्र का उत्थान तो केवल केंद्र की जिम्मेदारी है।

बजट में रोजगार के सवाल का समाधान करने के लिए जो कई उपाय किए गए हैं, वे युवाओं को उत्साहित करने वाले तो हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इस सिलसिले में सरकार ने जिन तीन नई योजनाओं की घोषणा की है, वे रोजगार के कितने मौके उपलब्ध करा सकेंगी? युवाओं के लिए यह घोषणा खासी आकर्षक है कि सरकार पांच सौ बड़ी कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी और उन्हें पांच हजार रुपये महीना देगी। अच्छा हो कि इस दायरे में अन्य कंपनियां भी लाई जाएं, ताकि अधिकाधिक युवाओं का कौशल विकास हो सके। यह महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनावों में अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद भी सरकार ने खुद को लोकलुभावन योजनाओं से दूर रखा और देश को विकसित बनाने में सहायक बनने वाली योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और ऐसा करते समय वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी। यह सरकार के आत्मविश्वास का परिचायक तो है, लेकिन इसके बाद भी इस बजट में देश की सूरत बदलने वाले क्रांतिकारी उपायों का अभाव दिखता है। ले-देकर आयकर कानून की समीक्षा का वादा किया गया है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि शहरीकरण की तेज रफ्तार के चलते अगले पांच-छह वर्षों में 40 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही होगी। इसे देखते हुए शहरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि शहर आर्थिक विकास के इंजन होते हैं। समस्या यह है कि शहरों के विकास के मामले में राज्य सरकारों का रवैया भी ढीलाढाला है। यह समझना होगा कि विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र और राज्यों के सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है।

चारधाम यात्रा की चुनौतियां

उत्तराखंड में जोरदार मानसून के बावजूद चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। प्रतिदिन आठ से दस हजार तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं। यद्यपि ग्रीष्मकाल की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या में गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिखती। अब जबकि, मानसूनकाल चरम की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में यात्रा सामान्य दिनों की तुलना में अधिक जोखिमभरी हो गई है। जोखिम इस मायने में कि जगह-जगह भूस्खलन होने के कारण यात्रा मार्गों पर यातायात घंटों अवरुद्ध हो रहे हैं। पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने से जानमाल का खतरा भी बढ़ गया है। यही नहीं, गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 16 किलोमीटर और जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक के छह किलोमीटर पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की चुनौतियां बढ़ गई हैं। केदारनाथ मार्ग पर एक दिन पहले पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आकर तीन श्रद्धालु जिंदा दफन हो गए थे, पांच अन्य को चोटें आई थी। सूरतेहाल यात्रा मार्गों पर चुनौती और चिंता दोनों बढ़ गई है। अब चूंकि, सावन का महीना भी शुरू हो गया है, इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे तो आस्था के आगे तमाम चुनौतियां बौनी नजर आती रही हैं, श्रद्धालु हंसी-खुशी यात्रा राह पर आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन, यह जरूरी है कि यात्रा सावधानी के साथ की जाए। विशेषकर, रात के समय सफर न तो हाईवे पर सुरक्षित है और न ही पैदल मार्गों पर। भारी वर्षा के दौरान भी यात्रा को सुरक्षित पड़ाव पर विराम देने में ही समझदारी है। प्रशासन को समय-समय पर इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करते रहना चाहिए। पड़ावों पर यात्रियों को इस बात की जानकारी जरूर दी जानी चाहिए कि आगे के सफर में मौसम का पूर्वानुमान क्या है और इसमें स्थितियां अनुकूल हैं या नहीं। तभी सुरक्षित और निर्बाध यात्रा की योजना पर आगे बढ़ पाएंगे।

वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार

धर्मकीर्ति जोशी

माना जा रहा था कि चुनावी झटके के बाद बजट कुछ लोकलुभावन हो सकता है, लेकिन सरकार ने उचित ही उससे किनारा किया

अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भी मोदी सरकार ने वित्तीय अनुशासन की राह पर चलने की अपनी परिपाटी को कायम रखा। अस्थिर एवं उथल-पुथल भरे वैश्विक एवं घरेलू माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से संतुलन साधने का प्रयास किया। किसी बड़ी रेवड़ी के एलान से परहेज करते हुए उन्होंने आवश्यक क्षेत्रों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोलने से संकोच भी नहीं किया। स्वस्थ राजस्व संग्रह के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को जो अतिरिक्त लाभांश प्राप्त हुआ, उसका उपयोग भी बहुत विवेकसम्मत ढंग से किया गया। सरकार ने जहां इसका कुछ हिस्सा राजकोषीय घाटे को घटाने में किया तो वहीं शेष राशि को वहां खर्च किया, जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता महसूस हो रही थी। जैसे सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, एमएसएमई सहित समग्र मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन, शहरी आवास की समस्या के समाधान और महंगाई को काबू करने से जुड़े उपाय तलाशने में अपने संसाधन लगाए। देखने में ये भले ही बड़े खर्चे लगें, लेकिन इनकी प्रकृति बहुत उत्पादक किस्म की होती है। जैसे कौशल विकास से लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मियों की आपूर्ति होती है। इसी प्रकार, शहरी आवास के निर्माण की योजना को देखें तो जहां उनके निर्माण से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाएं बनेंगी, वहीं ऐसी परिसंपत्तियों का भी सृजन होगा जो दीर्घकाल में उद्योगों से लेकर कामगारों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होंगी। इस प्रकार की गतिविधियों से आर्थिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, जिससे अंततः आर्थिकी को ही गति मिलती है।

विभिन्न मदों में अपना खर्च बढ़ाने के बावजूद यदि सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9 प्रतिशत तक लाने में सफल रही तो यह बहुत सराहनीय कहा जाएगा। यह अंतरिम बजट में घाटे के 5.1 प्रतिशत के अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन है। वित्त मंत्री ने आगामी वित्त वर्ष में न केवल घाटे के दायरे को और घटाकर 4.5 प्रतिशत पर लाने का एलान किया, बल्कि यह भी कहा कि सरकार चरणबद्ध रूप से अपनी उधारी का दायरा घटाएगी। असल में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ने का अर्थ बाहरी उधारी पर उसकी निर्भरता बढ़ना है। इससे जहां ब्याज अदायगी पर सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, वहीं आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय तंत्र में संसाधनों की किल्लत भी पड़ जाती है। राजकोषीय घाटे का बेलगाम होना कई मोर्चों पर चिंता का सबब बन जाता है। यही कारण है कि इसे काबू करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होता है और मोदी सरकार इस मोर्चे पर खरी उतरती आ रही है।

अवधेश राजपूत

उत्पादक खर्चों में कोई कंजूसी न करते हुए सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाए रखने का सिलसिला कायम रखा है। देश में पिछले कुछ समय से बुनियादी ढांचे के विकास ने तेज रफ्तार पकड़ी है। केंद्र सरकार इस मोर्चे पर राज्य सरकारों से लेकर निजी क्षेत्र को भी साधकर समन्वित प्रयासों पर जोर दे रही है। चूंकि बुनियादी ढांचे का प्रभाव कई स्तरों पर देखने को मिलता है, इसलिए इस पर जोर दिया जाना आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य हो जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास से निजी क्षेत्र के लिए भी अनुकूल कारोबारी परिवेश तैयार होता है। बजट में निजी क्षेत्र को और सहारा देने के लिए सरकार ने कई वस्तुओं पर ड्यूटी घटाई है। इससे देश में मोबाइल फोन से लेकर चार्जर का निर्माण किफायती होगा। मूल्यवान धातुओं सहित कई अन्य वस्तुओं पर ड्यूटी घटने से उनके दाम भी संभलेंगे, जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत आवश्यक हो गया था। मैन्यूफैक्चरिंग के मोर्चे पर लेबर इंटेंसिव एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और मुद्रा लोन का दायरा बढ़ाना भी सराहनीय कदम हैं। कौशल विकास और इंटर्नशिप से जुड़ी पहल न केवल रोजगार सृजन का विस्तार करेगी, बल्कि उद्यमों को भी बड़ा सहारा देगी। अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती पर सरकार का 3,000 रुपये का प्रोत्साहन भी नई नौकरियों को बढ़ावा देने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

आर्थिक मोर्चे को संतुलन प्रदान करने की दृष्टि से महंगाई पर अंकुश लगाने को सरकार ने अपनी प्राथमिकता सूची में रखा। अक्सर देखने में आता है कि महंगाई की स्थिति मौद्रिक मोर्चे के बजाय आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी होती है तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। इस दिशा में जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अप्रभावित विभिन्न फसलों की नई किस्मों की पेशकश जैसी पहल की गई है। इससे प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं से फसल को होने वाले नुकसान पर अंकुश लगने के साथ ही आपूर्ति के समीकरण भी नहीं बिगड़ेंगे और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। सरकार कृषि उपज के भंडारण के लिए भी कमर कसे हुए है।

निजी आयकर की दरों में बहुत मामूली फेरबदल किए हैं। इसे लेकर वेतनभोगी वर्ग में असंतुष्टि का भाव दिख सकता है, क्योंकि ये शाश्वत अपेक्षाएं हैं। पूंजी बाजार से जुड़े विभिन्न करों के स्तर पर भी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। हालांकि पूंजीगत लाभ जैसे कर को लेकर अभी बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन इसे बाजार में विभिन्न प्रकार के करों को एक स्तर पर सुसंगत करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत माना जा सकता है। वैसे भी, फ्यूचर एंड आप्शन यानी एफएंडओ को लेकर बीते दिनों तमाम तरह की आशंकाएं जताई गईं तो उसे देखते हुए यह अपेक्षित लग रहा था कि कुछ कदम जरूर उठाए जाएंगे। एंजल टैक्स की विदाई निःसंदेह स्वागतयोग्य है।

माना जा रहा था कि चुनावी झटके के बाद बजट कुछ लोकलुभावन हो सकता है, लेकिन सरकार ने उचित ही उससे किनारा किया। यह सही है कि इस समय सरकार, बैंकों और उद्योगों के बहीखातों से लेकर समग्र अर्थव्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां जिस प्रकार बेहद अस्थिर एवं अनिश्चित हैं, उसे देखते हुए अपने कवच को जरा सा कमजोर करना बहुत भारी पड़ सकता है।

(लेखक क्रिसिल में मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

समावेशी विकास के हरसंभव उपाय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। उनकी पहली प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि को समर्पित रही। बजट में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मद्देनजर विशेष किस्मों के विकास के लिए व्यापक अनुसंधान के जरिये खेती-किसानी के कायाकल्प की योजना बनाई है। इस दिशा में करीब 109 उच्च उत्पादकता वाली किस्में न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए कवच की भूमिका निभाएंगी, बल्कि इनसे किसानों की आय भी सुधरेगी। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा और बायो-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना से भी कृषि को बड़ा संबल मिलेगा। दलहन एवं तिलहन को प्रोत्साहन से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उपभोग केंद्रों के निकट बड़े वेजिटेबल क्लस्टर और कृषि में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की पहल से आपूर्ति सुधरने के साथ ही बाजारों तक किसानों की पहुंच सुगम होगी।

दूसरी प्राथमिकता कौशल विकास एवं रोजगार से जुड़ी है। इसके अंतर्गत विशेष पैकेज में दो लाख करोड़ रुपये का प्रविधान है, जिससे 4.1 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। पहली बार नौकरी में आए कर्मियों को 15,000 रुपये तक का एक महीने का पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। विनिर्माण में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन से 30 लाख नए कर्मियों को फायदा पहुंचेगा। वहीं, अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती पर नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से 50 लाख नई भर्तियों की योजना है। महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल से लेकर अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कौशल विकास के लिए 1,000 आइटीआइ को उन्नत करना, 20 लाख युवाओं का केंद्रीय योजनाओं के जरिये कौशल विकास और आदर्श कौशल ऋण योजना को नए सिरे से तैयार किया गया है। शिक्षा ऋण में छूट के साथ ही उसे और सुगम बनाया जाएगा। शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दिलाई जाएगी। इससे रोजगार संकट के समाधान के साथ ही हुए उद्योगों की अपेक्षाएं भी पूरी होंगी।

समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

विवेक देबराय

आदित्य सिन्हा

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सतत आर्थिक वृद्धि का खाका नजर आता है

स्पष्ट प्राथमिकताओं वाला बजट। प्रेट्र

इसके लिए पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जरिये दस्तकारों, स्वयं सहायता समूहों और स्ट्रीट वेंडर्स की मदद दी जाएगी। पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आंध्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन विकास के जरिये वृद्धि को नए पंख लगाए जाएंगे। एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम मशीनरी एवं उपकरण खरीदारी में मददगार होगी। एमएसएमई क्लस्टर्स के निकट सिडबी की शाखाओं के विस्तार से वित्त तक उनकी पहुंच भी बेहतर होगी। ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब भी स्थापित होंगे। दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप और विशेष औद्योगिक पार्कों की स्थापना से निवेश को लुभाने एवं रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

शहरी विकास को प्राथमिकता में रखते हुए सरकार ने 30 लाख से अधिक की आबादी वाले कुछ बड़े शहरों को चिह्नित किया है। लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में करीब 10 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना का एलान किया गया है। घर खरीदने पर ब्याज में छूट की सुविधा भी जारी रहेगी। पीपीपी माडल के जरिये भी शहरी कामगारों के लिए आवास तैयार करने की योजना है। जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्ट्रीट मार्केट से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से शहरों में रहने के लिए अनुकूल परिवेश एवं रोजगार सृजन के प्रयास हुए हैं। सतत वृद्धि के लिए ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता के तहत मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से लोगों को छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की गई है। स्माल माड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों का विविधीकरण किया जाएगा। एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स और ऐसी कुछ अन्य पहल के जरिये ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया है। पारंपरिक छोटे उद्यमों में इन्वेस्टमेंट-ग्रेड एनर्जी आडिट से भी स्वच्छ ऊर्जा के उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर भी सरकार की वरीयता सूची में है। सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान करने के साथ ही राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र को अतिरिक्त सहायता के संकेत दिए हैं। इस मोर्चे पर सड़क निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन आदि से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। तकनीक के महत्व को समझते हुए शोध एवं विकास की दिशा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के विस्तार की योजना है। अंतरिक्ष से जुड़ी आर्थिक संभावनाओं को भुनाने के लिए 1,000 करोड़ का विशेष कोष स्थापित किया जाना है। भूमि से लेकर श्रम सुधारों के मुद्दे पर भी आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं, जो बेहद आश्वस्तकारी कदम है, क्योंकि लंबे समय से ऐसे सुधारों की प्रतीक्षा हो रही है। इसी कड़ी में ईज आफ डूइंग बिजनेस, डाटा गवर्नेंस और टेक्नोलाजी अडाप्शन से भी आर्थिक सक्षमता बढ़ने के भरे-पूरे आसार हैं। कुल मिलाकर, कौशल विकास एवं रोजगार में लक्षित निवेश के माध्यम से बजट में सतत एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि का खाका खींचा गया है।

(देबराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख एवं सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन को उत्सव बनाएं

जीवन जीना एक कला है। इसमें निपुण होना एक सिद्धि प्राप्त करने के बराबर है। मानवीय संवेदनाओं के आवेग में हर पल घटित होने वाली सुख-दुख की लहरों को पूरी तरह समाहित कर लेना ही एक सच्चे मनुष्य की निशानी है। काम, क्रोध, मोह और लोभ इन क्षणभंगुर तत्वों को परे रखकर जीवन का आस्वादन करना समयानुकूल उत्सवों में शामिल होने के समान है। जो इस स्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है वह अंतरात्मा को जीवन का सही दर्शन करा देता है और स्वयं को पूरी तरह उत्सव के रंग में रंगकर अपने रोम-रोम को पुलकित होने के लिए बाध्य कर देता है।

एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि 'उत्सव मनाने के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ है?' तो गुरु द्वारा कहा गया कि 'मौत का दिन।' शिष्य ने कहा, 'यह कैसे पता चलेगा कि मौत का दिन कौन सा है?' तब गुरुजी ने कहा-हर दिन के हर पल को उत्सव की तरह मनाएं तो जीवन का सोलहवां संस्कार मौत भी उत्सव बन जाएगा।' जीवन में आने वाले सुख-दुख, उतार-चढ़ाव और परेशानियों को सहज रूप से स्वीकार कर लेना और उन्हें आभूषण समझ धारण कर लेना ही समझदारी है। तभी आप वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और वर्तमान का खुले मन से स्वागत कर पाएंगे। व्यर्थ में अतीत और भविष्य के बारे में सोचना, वर्तमान को कुएं में धकेलने के समान है। ऐसा करके हम बाधाओं को निमंत्रण देते हैं।

यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वह जीवनपर्यंत आपका ही बना रहेगा। यदि यह भाव हम तिरोहित कर दें तो जीवन में उत्सव के रंग सदा ही बने रहेंगे। जीवन में यूं ही उत्सव की स्थिति बनी रहे उसके लिए जरूरी है कि अपने अंतस में झांकते रहें। जो काम कल करना है, उसे आज ही करके स्वयं को किसी भी बंधन से मुक्त कर लें और अपनी खुशी को दोगुना कर लें।

पारुल हर्ष बंसल

देश को दिशा देता बजट

योगेश कुमार गोयल

हर साल पेश किए जाने वाले बजट का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश किया। वह लगातार सात बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकार्ड था, जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री के रूप में छह बजट लगातार पेश किया था। इसी साल एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। दरअसल चुनाव से पहले पेश किया गया अंतरिम बजट केवल नई सरकार बनने तक के लिए ही था। अंतरिम बजट में सरकार को अनुमति होती है कि वह नई सरकार बनने तक जरूरी खर्चों के लिए सरकारी खजाने से फंड का इस्तेमाल करे, जबकि आम बजट नई सरकार का पूरे वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए वित्तीय प्लान होता है, जिसमें राजस्व, खर्चे और सरकार की नीतियों का विवरण होता है, जिस पर संसद के दोनों सदनों में बहस भी की जाती है। पूर्ण बजट को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। केंद्रीय बजट देश के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से देश का सुधार करना और लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना होता है। इसके जरिए सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करती है। दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करती है। इसके जरिए सरकार यह तय करती है कि अपने राजस्व की तुलना में खर्च को किस हद तक बढ़ा सकती है। यह कवायद इसीलिए होती है, क्योंकि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे का एक लक्ष्य हासिल करना होता है।

बजट आमतौर पर तीन प्रकार के होते हैं-संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट में आय और खर्च की मात्रा का समान होना जरूरी है, जबकि अधिशेष बजट में सरकार की आय खर्चों से अधिक होती है और घाटे के बजट में सरकार के खर्च उसकी आय के स्रोतों से अधिक होते हैं। 2016 तक फरवरी माह के अंतिम दिन आम बजट पेश किया जाता था, किंतु 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर एक फरवरी कर दिया। 1999 तक बजट भाषण फरवरी के अंतिम कार्यदिवस पर शाम पांच बजे पेश किया जाता था, लेकिन 1999 में यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। 2017 से पहले रेल बजट भी अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में उसे आम बजट में ही समाहित कर दिया गया।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

शिक्षा बजट का उचित उपयोग जरूरी

गिरीश्वर मिश्र का 'पूरी हो शिक्षा पर समुचित खर्च की मांग' शीर्षक से प्रकाशित आलेख पढ़ा। जमीनी स्तर पर शिक्षा में सुधार एवं शिक्षा को गुणवत्तापरक कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसमें धन से ज्यादा मन का अभाव है। आज अपने देश में शिक्षा एक बड़ा कारोबार है। देश में प्राइवेट स्कूलों, कालेजों एवं तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाओं की भरमार है। यहां तक कि मेडिकल कालेज भी प्राइवेट क्षेत्र में अधिक हैं। सरकारी स्कूलों एवं कालेजों में शिक्षक एवं छात्र अनुपात अभी तक जरूरत से कम है। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में दोष है। भ्रष्टाचार है। सबसे पहले शिक्षक पढ़ाना जानता भी है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरे, सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। एक ही क्लास में ठूंस-ठूंस कर विद्यार्थी अगर बैठाए जाएंगे तो वे पढ़ेंगे क्या? अतः भवनों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल वाले मुहैया करते हैं। अपने देश में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को सच पूछिए तो बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। सुविधाओं का नितांत अभाव है। धन का उपयोग इसे दूर करने पर किया जाना चाहिए, वरना शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव ही रहेगा। वर्तमान व्यवस्था में ही शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और ज्यादा जवाबदेह बनाना होगा। शिक्षा व्यापार बनकर न रह जाए, यह ध्यान देने की जरूरत है। समर्पित एवं ईमानदार लोग ही इस विधा में आएं, नौकरी समझ कर केवल नौकरी न करें, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में शिक्षकों की बड़ी अहम भूमिका है। शिक्षक ही देश को भावी नागरिक देते हैं। इसी से किसी देश का भविष्य संवरता है।

अशोक कुमार दुबे, पटना

चिंता का विषय

पिछले कुछ दिनों से जम्मू संभाग में सेना पर आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमले की खबरें कुछ अधिक आ रही हैं। सबसे दुखद है समाज, प्रशासन यहां तक की राजनीतिक दलों में आतंकियों के मददगार मौजूद होना। यह कटु सत्य है कि जनता में शामिल समर्थकों के बिना आतंकवाद सफल नहीं हो सकता। जनता में समर्थकों की मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है इस बार की लोकसभा में पंजाब से एक खालिस्तान समर्थक और कश्मीर से एक अलगाववादी जेल से चुनाव जीत कर आए हैं। जनरल बिपिन रावत ने ठीक कहा था कि देश को ढाई दुश्मनों से खतरा है। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी ने तो इससे भी आगे कटु सत्य कह दिया है कि मुख्यधारा के नेता आतंकियों के घर जाकर उनसे सहानुभूति प्रकट करते हैं। सरकार देश के अंदर के आतंकी समर्थकों पर सख्त कार्रवाई करे। जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आतंकियों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। इसके अतिरिक्त लद्दाख एवं उत्तर पूर्वी भारत विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में चीन से सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। म्यांमार के राजनीतिक हालात भी मणिपुर की स्थिति बिगाड़ सकते हैं।

सीपी बंसल, दिल्ली

आरएसएस का विरोध गलत

विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर देश के कई नेता लंबे समय से गलत टिप्पणी करते आ रहे हैं। संघ की सही जानकारी न होने कारण ही शायद ये सभी लोग ऐसा करते हैं। अभी केंद्र सरकार ने पिछले 58 वर्षों से संघ की शाखा में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक को हटाया है। रोक हटते ही विपक्षी नेताओं ने इस पर अपनी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। संघ एक देशभक्त एवं सामाजिक संगठन है। सामाजिकता एवं देशभक्ति से जुड़ने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को है। चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या सामान्य नागरिक। संघ पर गलत टिप्पणी करने वाले ये सभी लोग केवल राजनीति के कारण विशेषकर मुस्लिम वोट पाने के कारण ही संघ के खिलाफ बोलते हैं। वास्तव में संघ के कार्यों को देखेंगे तो 1925 से लेकर आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जिससे देश एवं समाज को कोई हानि हो।

ललित शंकर, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

2.4 करोड़ यात्रियों को रोजाना अपनी सेवाएं प्रदान करती है भारतीय रेल, जिसका नेटवर्क देशभर में 68,584 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेल देश की जीवन रेखा बनी हुई है।

आजकल

हर्ष वर्धन त्रिपाठी
आर्थिक मामलों के जानकार

राजनीतिक संतुलन के साथ विकास पर जोर

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार दिखता है। साथ ही, इसमें विकसित भारत की आकांक्षा के साथ राजनीतिक संतुलन साधने का भी स्पष्ट प्रयास दिखता है। तीसरी बार की मोदी सरकार के समक्ष रोजगार पर अलग से बड़ी घोषणा करने का दबाव भी नजर आ रहा है। लिहाजा इसमें इस मसले पर भी व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं, जिनके माध्यम से यह उम्मीद की जा सकती है कि इसका लाभ अधिकतम जनसंख्या तक पहुंचेगा

औद्योगिक विकास के साथ ही रोजगार परिदृश्य में बदलाव के साथ ही समग्र विकास को मिलेगी तीव्र गति। फाइल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तीसरा कार्यकाल पहले दोनों कार्यकाल से कितना अलग है, इसका अनुमान तीसरी बार की मोदी सरकार बनने के बाद आए इस बजट से पता लग गया है। लोकसभा में किसी एक पार्टी के 272 से अधिक सदस्य होने पर ही एक पार्टी की सरकार बन पाती है। ऐसा न होने पर उसे दूसरी पार्टी से समर्थन लेना पड़ता है। हालांकि तीसरी बार की मोदी सरकार के साथ अच्छा यह है कि चुनाव पूर्व गठबंधन वाली राजग की सरकार बिना किसी किंतु परंतु के बन गई है। मोटे तौर पर देखने पर यह बजट पूरी तरह से नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार बजट ही दिखता है, लेकिन इसमें विकसित भारत की आकांक्षा के साथ राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास भी स्पष्ट तौर पर दिखता है।

मोदी सरकार पर रोजगार पर अलग से बड़ी घोषणा करने का दबाव भी नजर आ रहा है। सरकार बनते ही घोषित प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अतिरिक्त तीन करोड़ घरों के लिए बजट प्रविधान कर दिया गया है। एमएसएमई के लिए कई राहत भरे एलान के साथ उनको कर्ज देने का प्रविधान भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और बुनियादी ढांचागत विकास के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान प्रधानमंत्री की नीतिगत निरंतरता और प्रतिबद्धता को स्थापित कर रहा है, लेकिन सरकार यह नहीं चाहेगी कि इस बार भी निरंतरता के बजट के तौर पर इसे प्रस्तुत किया जाए। यही वजह है कि इस बार वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होते ही रोजगार पर चला गया था। साथ ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन पर चल रही मोदी सरकार ने बड़े सलीके से विकास की पैकेजिंग में राजनीतिक संतुलन का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है।

प्रधानमंत्री ने अपने दोनों प्रमुख सहयोगियों को केंद्रीय बजट में देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन दोनों ही राज्यों की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी के नियमों के लिहाज से दोनों ही राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और ऐसा होने पर दूसरे राज्य भी ऐसी ही मांग कर सकते थे, लेकिन नीतीश और नायडू की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसका भी ध्यान रखना था। वित्त मंत्री ने उसे ध्यान में रखते हुए बिहार को विशेष पैकेज राजमार्ग, हवाई अड्डे, बड़े पुल और पर्यटन सर्किट की शक्ल में दे दिया। चंद्रबाबू नायडू को नई राजधानी के साथ पूरा राज्य अपने हिसाब से बनाना है, इसीलिए वह बजट से पहले अपनी मांग रख चुके थे। नई राजधानी और औद्योगिक गलियारे के लिए केंद्रीय बजट में 15 हजार करोड़ रुपये देकर मोदी ने नायडू के उस विश्वास को बढ़ाने की कोशिश की है जो संसद के केंद्रीय कक्ष में सरकार बनने से पहले दिखा था। तीसरी बार की मोदी सरकार ने अन्य राजनीतिक दबावों में पड़कर किसान सम्मान निधि बढ़ाने या एमएसपी की गारंटी देने जैसा देश को पीछे ले जाने वाला निर्णय नहीं लिया, यह अच्छी बात रही।

रोजगार को नई दिशा : रोजगार को लेकर देशभर में एक वातावरण बना हुआ था और इस पर कुछ ऐसा एलान करना आवश्यक था, जिससे सीधे तौर पर भाजपा समर्थकों को एक मजबूत तर्क मिल सके। एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का बजट में एलान सरकार के लिए बड़ा हथियार है। युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के समय प्रति माह पांच हजार रुपये मिलेंगे और बाद में छह हजार रुपये भी दिए जाएंगे। पढ़ाई पूरी करके निकले नौजवान को इंटर्नशिप के साथ 66 हजार रुपये पक्के हो जाने से नौजवानों में रोजगार के मसले पर सरकार का पक्ष बहुत हद तक बेहतर होता दिख रहा है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके लिए सरकार को अलग से खजाने पर बोझ नहीं बढ़ाना पड़ रहा है।

कुशल श्रमिक न मिल पाना उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या रही है। अपने पहले कार्यकाल से ही मोदी सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता में रख रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो सका है।

एमएसएमई पर विशेष ध्यान : एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उस रीढ़ को मजबूत करने के लिए इस बजट में भी विशेष प्रविधान किया गया है। एमएसएमई मुद्रा लोन सीमा 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दी गई है। नई योजना के तहत एमएसएमई को 100 करोड़ रुपये तक कर्ज मिल सकेगा। पीपीपी माडल के तहत ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब बनाए जाने की बात बजट में कही गई है, इसका लाभ भी एमएसएमई को मिलेगा। अपना कारोबार करने वालों को अब 20 लाख तक का कर्ज बिना गारंटी के मिलेगा, पहले यह सीमा 10 लाख थी। कोविड और दूसरी वजहों से ढेरों कंपनियां दिवालियां हुई हैं। अच्छी बात है कि सरकार का ध्यान इस ओर भी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण गावों में निवेश लेकर आ सकता है। कर छूट के मामले में पिछले बजटों की तरह इस बजट में भी सरकार बहुत उदार नहीं रही है। कुल मिलाकर नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में थोड़ी छूट का लाभ करदाताओं को अवश्य मिल जाएगा। कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर बाजार में नाराजगी देखने को मिली, लेकिन बाजार बंद होते होते सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत मामूली गिरावट बची रह गई। शेयर बाजार भी मोदी सरकार के साथ मध्य वर्ग की ही तरह व्यवहार कर रहा था। अपने अनुकूल निर्णय न होने पर थोड़ी देर की नाराजगी और फिर समग्रता में निर्णय देखकर राष्ट्र के लिए आहुति मानकर उसे स्वीकार कर लेना। इस बजट में रोजगार पर जो संदेश प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं, उसे जमीन पर उतार सके, तो विपक्ष के लिए युवाओं की भावनाएं भड़का पाना आसान नहीं होगा।

खरी-खरी

विशेष विवाह की कथा

विनोद कुमार विक्की

भविष्य में जब कभी 21वीं सदी के महान क्रांतिकारी परिवर्तन की चर्चा होगी, तो उसमें अंबानी पुत्र के एकल से युगल बनने की घटना को प्रमुखता से याद किया जाएगा। विभिन्न समयावधि में में प्री-वेडिंग, मेंहदी आदि रस्मों से लेकर वरमाला, मंगलसूत्र तक चलने वाली प्रक्रिया के तहत वैवाहिक कार्यक्रम कई मायनों में अहम रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतांत्रिक आर्यावर्त में राजसी परिणय की इस परिघटना से संपूर्ण चराचर आह्लादित हो गया।

शिव के वैवाहिक उत्सव में भूत-पिशाच, यक्ष गंधर्व आदि बाराती झूमकर नाचे थे, कुछ उसी तरह का नजारा इस अनंत विवाह में देखने को मिला, जिसमें साधु, संन्यासी, खिलाड़ी, उद्योगपति, नेता अभिनेताओं का हुजूम झूमते हुए दिखाई दिया। सदी के इस महान वैवाहिक महोत्सव में आश्चर्यजनक घटनाएं भी देखने को मिलीं। वर के पिता की अमीरी का मुक्त कंठ से विरोध करने वाले महामानव भी मुस्कुराते और कमर हिलाते हुए दिख गए। न्यूज, मीम्स, रील्स के अलावा दूल्हे का पशु प्रेम, संस्कारी वर आदि शीर्षकों के साथ सुर्खियों में रहने वाले अनंत विवाह की खबरों से देश की अन्य समस्याओं को समाचार बनने का मौका ही नहीं मिला।

आम तौर पर देखा जाता है कि मध्यवर्गीय परिवार में होने वाली शादी में ऐसे रिश्तेदार नाराज होते हैं, जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया हो और जो निमंत्रित तो होते हैं, परंतु यदि उन्हें तवज्जो नहीं मिलती तो विवाह प्रक्रिया में मीन मेख निकालने की नैतिक जिम्मेदारी उठा लेते हैं। सब कुछ सामान्य रहे तो भी शादियों में मुंह फुलाए रखने का कापीराइट जीजा और फूफा के पास होता है। अब शीर्ष धनाढ्य मानव का विवाह भला इस परंपरा से कैसे अछूता रह सकता है। अनंत विवाह में जीजा और फूफा की भूमिका निभाई उनके उपभोक्ताओं ने जो उन्हें कोसते हुए कह रहे हैं कि मोबाइल फोन रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ा कर शादी का खर्च निकाला गया है।

अरे भाई, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत बाएं-दाएं तो चलता ही है। बहरहाल, महीनों तक चलने वाली इस शादी और वर्षों तक होने वाली चर्चा के लिए कुछ तो लोग कहेंगे... लोगों का काम है कहना।

भारतीय रेल : संसाधनों के बाद भी कायम चुनौतियां

अरविंद कुमार सिंह
पूर्व सलाहकार, भारतीय रेल

वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार के कुल व्यय 48.3 लाख करोड़ रुपये में से परिवहन क्षेत्र के हिस्से में 5.44 लाख करोड़ आया है। इस लिहाज से देखें तो रेलवे को ठीक-ठाक धन मिला है। रेलवे का सकल राजस्व व्यय 2023-24 में 2.58 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में 2.78 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में पूंजीगत व्यय 2.65 लाख करोड़ रुपये है। इसमें सामान्य राजस्व से 2.52 लाख करोड़ राशि मिलेगी, पर आंतरिक संसाधनों से रेलवे महज तीन हजार करोड़ रुपये ही जुटा सकेगा, क्योंकि भारी कमाई के साथ भारी व्यय भी कायम है और आंतरिक संसाधनों की दशा चिंताजनक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल यात्रियों से लगभग 80 हजार करोड़ रुपये और माल ढुलाई से 1.74 लाख करोड़ रुपये की कमाई करेगी, ऐसा अनुमान है। विभिन्न मदों में रेलवे की कुल आमदनी 2.78 लाख करोड़ रुपये तक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 से इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय रेल की कमाई काफी अधिक बढ़ी है। धन आवंटन और अन्य तथ्यों को देखें तो बेशक ये आंकड़े सुखद दिखते हैं, परंतु आम नागरिकों को यह बजट भारतीय रेल के लिहाज से थोड़ा निराश कर गया। उम्मीद थी कि इस बजट में वित्त मंत्री रेलवे के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगी, जिससे यात्री सुविधा में वृद्धि होने के साथ रेलवे को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी वृद्धि होती। परंतु फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया। संभवतः रेलवे में किए जा रहे सुधारों को यात्रियों तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार 68,584 रूट किलोमीटर में फैला विशाल भारतीय रेल 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ देश की जीवन रेखा बनी हुई है। भारतीय रेल रोजाना आस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर यात्रियों को ढोते हुए देश का सबसे बड़ा नियोजक और परिवहन का मुख्य आधार स्तंभ बनी हुई है। लेकिन सुरक्षा और संरक्षा पर चिंता कायम है। एक लाख करोड़ रुपये के संरक्षा कोष के बाद भी चुनौतियां कायम हैं। भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रेल योजना में 2024 तक भीड़-भाड़ वाले मार्गों का संकुचन हटाना, दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर 160 किमी प्रतिघंटा और अन्य स्वर्णिम चतुर्भुज एवं स्वर्णिम विकर्ण मार्गों पर 130 किमी प्रतिघंटा की गति के साथ सभी स्तर के क्रासिंगों की समाप्ति की दिशा में अभी बहुत कार्य शेष हैं। दिसंबर 2021 तक डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर पूरा होना था, वह भी लेटलतीफी का शिकार रहा। चालू परियोजनाओं के लिए भारी रकम की दरकार बनी हुई है।

हमारी परिवहन प्रणाली रेलवे, राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन तथा वायुमार्ग जैसे साधनों से मिल कर बनी है। इनमें सबसे दक्ष और किफायती भारतीय रेल ही है जो रोज 12 हजार से अधिक सवारी और नौ हजार से अधिक मालगाड़ियों का संचालन करती है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के बाद से भारतीय रेल का एक नया युग आरंभ हुआ। वंदे भारत ने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं, परंतु गति के दावे से लेकर बहुत से मामलों में इसे अपना जौहर अभी दिखाना शेष है। एक अच्छी बात यह भी है कि देरी से ही सही, हमारी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब साकार होती दिख रही है। रेलवे के पास यात्रियों की कमी नहीं हैं। पर गरमी की छुट्टियां, होली, दीवाली और अन्य त्योहारों व मेलों के दौरान विशेष गाड़ियां चला कर भी भीड़ संभाल पाने में अक्षम साबित हो रही है। भारतीय रेल थोड़ा ध्यान दे तो सुरक्षित, समय की पाबंद और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन के तौर पर वह अपना विशिष्ट स्थान लंबी दूरी के साथ ही उपनगरीय यातायात में भी बना सकती है, बशर्ते क्षमता का विस्तार किया जाए।

पोस्ट

कांग्रेस का दावा है कि बजट उसके घोषणापत्र से उठाया गया है और साथ ही वह यह भी कह रही है कि बजट एकदम बेकार है। अनुपम मिश्रा@scribe9104

भले ही बिहार व आंध्र को औपचारिक रूप से विशेष राज्य का दर्जा न मिला हो, पर बजट में दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो हुए न ये दोनों विशेष राज्य। अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

चाहे आपके घर का हो या फिर देश का, बजट असल में आशाओं और सीमाओं का समझौता होता है। आलोचना बहुत हो सकती है, पर संतोष इसका कि घाटा कम किया और रोजगार को प्राथमिकता दी, जो उद्यम एवं कौशल विकास के बिना नहीं बढ़ सकता। नेताओं को सीखना होगा कि सरकारी नौकरी बांटना रोजगार सृजन नहीं है। शिव कांत@shivkant

समग्रता में देखा जाए तो बजट नीतिगत निरंतरता, राजकोषीय अनुशासन और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। एंजल टैक्स और सोने पर भारी ड्यूटी को हटाने जैसे अच्छे कदम उठाए गए। पूंजी बाजार के मोर्चे पर कुछ करों में मामूली बढ़ोतरी हुई। कोई बड़ी रेवड़ी नहीं दी गई। राजनीतिक मजबूरियों को आर्थिक एवं राष्ट्रहित के दायरे में समायोजन किया गया। हर्ष मधुसूदन@harshmadhusudan

जागरण जनमत

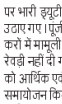

कल का परिणाम

क्या जो बाइडन की जगह कमला हैरिस प्रभावी राष्ट्रपति प्रत्याशी साबित होंगी?

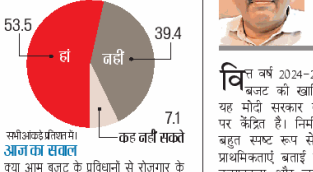

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आम बजट के प्रविधानों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

खुश दिखते हैं नायडू खुश दिखते नीतीश,
चुका दिया इस बजट में गठबंधन की फीस।
गठबंधन की फीस रहें खुश संगी-साथी,
तो घूमें नाराज भले सारे बाराती!
बढ़िया पैकेज पाय सभी साथी हैं टिकते,
किंतु विपक्षी लोग कभी भी ना खुश दिखते।
- ओमप्रकाश तिवारी

पंजाब डायरी

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

बजट से निराशा, वित्त आयोग से उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पहली नजर में देखकर लगता है कि यह बिहार और आंध्र प्रदेश केंद्रित है। बजट में इन दोनों राज्यों को जितना कुछ देने की घोषणा की गई है, उतनी घोषणा किसी और राज्य के लिए नहीं की गई है। इस पर पंजाब के कुछ नेताओं का कहना है कि यह बजट केंद्र सरकार का नहीं लगता, बल्कि दो राज्यों के लिए बनाया गया प्रतीत होता है। बजट में पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया।

इसमें दो राय नहीं कि पंजाब इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बात की पूरी आस थी कि इस बार आम बजट में इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी। पंजाब के किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद थी कि इस संबंध में भी बजट में कोई न कोई घोषणा अवश्य की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब को अब सारी उम्मीदें 16वें वित्त आयोग से है। अब देखना होगा कि वित्त आयोग पंजाब की आर्थिक रूप से मदद कर पाता है या नहीं। इससे पहले 15वें वित्त आयोग ने पांच वर्षों के लिए पंजाब को राजस्व घाटा अनुदान दिया था, जो लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के लगभग बनता है। ऐसा तब होता है, जब वास्तविक आय बजट आय और व्यय से मेल नहीं खाता। यह अलग बात है कि इस अनुदान को पूंजीगत व्यय में खर्च करने के बजाय सरकार ने इसे बिजली सब्सिडी पर ही बर्बाद कर दिया। तीन सौ यूनिट निःशुल्क बिजली का वादा पूरा करने के लिए यह पैसा खर्च किया गया।

अब इसी प्रकार का राजस्व घाटा अनुदान 16वें वित्त आयोग से मांगा जा रहा है। वित्त आयोग के चेयरमैन डा. अरविंद पानगड़िया ने स्वयं माना है कि राज्य की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बिजली सब्सिडी पर खर्च किया जा रहा है। सवाल है कि क्या इस बिजली सब्सिडी को वापस लेने का कोई विकल्प है? वोटों की खातिर दी गई यह सुविधा कब लोगों का अधिकार बन गया, यह राजनीतिक पार्टियां समझ ही नहीं पाईं। खैर, इसके लिए पंजाब सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्रणाली का विस्तार कर इस सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्त आयोग को एक रोडमैप दिया है। वित्त आयोग से इसके लिए राज्य को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद कायम है।

बिजली सब्सिडी के रूप में खर्च हो रहा है पंजाब में राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा। फाइल

सबसे बड़ा सवाल केंद्रीय करों के बंटवारे को लेकर है। अभी केंद्रीय कर दो तरीकों से बांटा जाता है। पहले केंद्र और राज्य के बीच तय नियम के अनुसार बांटा जाता है। फिर इसे राज्यों के बीच बांटा जाता है। इसके लिए एक फार्मूला तय किया गया है। पिछले वित्त आयोग ने इसके तहत आबादी के लिए 15 प्रतिशत, भूभाग के लिए 15 प्रतिशत, वन एवं पर्यावरण के लिए दस प्रतिशत, आय के अंतर के लिए 45 प्रतिशत, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए 12.5 प्रतिशत, टैक्स एफर्ट के लिए 2.5 प्रतिशत को आधार बनाया था। कर बंटवारे की यह व्यवस्था पंजाब के लिए उपयुक्त नहीं है। पंजाब भूभाग और आबादी के लिहाज से अपेक्षाकृत छोटा प्रदेश है। यहां वन क्षेत्र बहुत कम है। ऐसे में उसके हिस्से कर बहुत कम पैसा आता है। पंजाब का भूभाग मात्र दो प्रतिशत है, लेकिन अनाज भंडारण में उसका योगदान 31 प्रतिशत है। इससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा बनी हुई है। इसे बनाए रखने के लिए पंजाब ने अपना सारा भूजल गंवा दिया है, अपनी जमीन को रसायनों के प्रयोग से जहरीला कर लिया है, लेकिन इसे कर बंटवारे की व्यवस्था में नहीं रखा गया है। सवाल यह है कि अगर पंजाब अपनी बिजली सब्सिडी के पैसे का उपयोग राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने पर खर्च करे तो उसे वित्त आयोग से भी अधिक फंड मिलेगा, लेकिन ऐसा होने के बाद अगर देश में अनाज का संकट पैदा हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? वित्त आयोग ने भी इसे विचारणीय माना है।

अर्थशास्त्री डा. रंजीत सिंह घुम्मण ने भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद होने के 18 महीने बाद इसका पंजाब पर हुए असर का अध्ययन किया है। उनके अनुसार इस दौरान जहां 2104 करोड़ रुपये का राज्य को नुकसान हुआ, वहीं 12 हजार के लगभग लोगों का रोजगार छिन गया। उनका कहना है कि इस प्रकार के निर्णयों का संबंधित राज्यों पर असर होता है, उस नुकसान की भरपाई करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगती सीमा जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और गुजरात से भिन्न है। इसीलिए भारत में होने वाला बड़ा निवेश पंजाब में नहीं आता। डा. घुम्मण का मानना है कि इस नुकसान को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को पंजाब को विशेष पैकेज देना चाहिए।

आम बजट

डा. अश्विनी महाजन
प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

समावेशी नीतियों पर जोर

बजट आम तौर पर लोकलुभावनवाद से प्रेरित रहे हैं, पर मोदी सरकार इससे बचती रही है। इसके बजाय विकास व समावेशी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती रही है। यह बजट भी उसी राह पर है

खेती-किसानी के विकास के लिए बजट में किए गए हैं विशेष प्रविधान। फाइल

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट की खासियत यह है कि यह मोदी सरकार की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। निर्मला सीतारमण ने बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की नौ प्राथमिकताएं बताई हैं, जैसे कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन, विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। कुल मिलाकर, यह एक संतुलित बजट है, जिसमें मध्य वर्ग, गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को साधा गया है।

रोजगार पर ध्यान : हम समझते हैं कि रोजगार दो स्रोतों से आता है-नौकरी और स्वरोजगार। स्वरोजगार का लाभ यह है कि ऐसा करने वाले लोग नौकरी के सृजनकर्ता भी होते हैं। इस संदर्भ में बजट में दो बड़ी घोषणाएं हैं। बिना गारंटी वाले मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के साथ ही स्टार्टअप को भी एंजल टैक्स के माध्यम से कुछ राहत दी गई है। दूसरी योजना रोजगार के संबंध में है और वह भी संगठित क्षेत्र में, इसके लिए तीन योजनाएं शुरू की गई हैं। एक प्रमुख योजना अप्रेंटिसशिप है, जिसके तहत एक अप्रेंटिस को पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के वित्त पोषण के लिए कारपोरेट सीएसआर फंड का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक तरफ बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा तो दूसरी ओर व्यवसायों के लिए कुशल कर्मचारियों की कमी भी दूर होगी। यदि यह योजना सफल होती है, तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। छोटे उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। फिलहाल सरकार ने केवल बड़े उद्योगों को ही इस योजना में शामिल किया है और इसका कारण यह है कि सीएसआर के माध्यम से जो पैसा आता है, वह इसमें इस्तेमाल हो पाएगा। इसके अलावा, कंपनियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से पहली नौकरी का पहला वेतन सरकार द्वारा देने का वादा भी इस बजट में किया गया है। साथ ही नियोक्ता को ईपीएफओ में प्रोविडेंट फंड जमा करने हेतु भी सहयोग भी दिया जाएगा। ऐसा होने से देश में रोजगार बाजार को एक नई दिशा मिलेगी।

सभी क्षेत्रों के साथ संतुलन : बजट के बारे में सामान्य तौर पर माना जाता है कि यह सरकार की नीतियों का आईना होता है। बीते 10 वर्षों में सरकार जिन नीतियों पर चली है, उस कारण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। चाहे वह संवृद्धि की बात हो या महंगाई पर रोक लगाने की, सरकार सफल रही है। क्योंकि पिछली सरकार के 10 वर्षों की औसत महंगाई की दर 8.6 थी, जो इस सरकार के समय लगभग छह प्रतिशत है। इन बातों से उत्साहित होकर सरकार ने इस बार के बजट में कई ऐसे प्रविधान किए हैं जो विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं। सरकार की ओर से भी बार-बार कहा गया है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है। विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उन्हें केवल चार ही जातियां दिखाई देती हैं-युवा, महिला, गरीब और किसान।

खेती-किसानी पर खास ध्यान : किसानों की बात करें, तो किसान क्रेडिट कार्ड, सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए एफपीओ का गठन और डेयरी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन समेत तमाम उपाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट में दिखाई देते हैं। जहां तक गरीबों की बात है तो आवास उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में वह तीन करोड़ और शहरी क्षेत्र में एक करोड़ आवास उपलब्ध कराएगी, यह अच्छा कदम है। आप कल्पना कीजिए कि जो कच्चे घर में रह रहा है, यदि उसे पक्का घर मिल जाए, तो निश्चित तौर उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। जीवन स्तर में बदलाव से उस व्यक्ति की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। संभवतः इन्हीं सब कारणों से बीते वर्षों में भारत की बहुआयामी गरीबी में काफी कमी आई है। यूएनडीपी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया, विशेषकर गरीब देशों की तुलना में बहुआयामी गरीबी को कम करने में हमने अच्छी सफलता प्राप्त की है।

केंद्र और राज्य के तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार अन्य राज्यों की तरह अब तक अपेक्षाकृत विकसित नहीं हो पाया है। लिहाजा, केंद्र ने कुछ ऐसे प्रयास इस बार बजट में दिखाए हैं, जिनके फलीभूत होने से बिहार तेजी से तरक्की के पथ पर अग्रसर हो सकता है। यह राज्य प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत नीचे है। लंबे समय से बाढ़ की त्रासदी से भी गुजर रहा है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी इंट्रा स्टेट लिंक समेत अन्य परियोजनाओं को लेकर बजट में विशेष प्रविधान किया जाना अभिनंदनीय कदम माना जाना चाहिए, इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको बिहार की इस त्रासदी को लेकर संवेदनशील होना चाहिए।

****

24 जुलाई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ओडिशा के चांदीपुर में अत्याधुनिक लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करेगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 24 जुलाई, 2024

न्यूज गैलरी

ममता ने दुर्गा पूजा कमेटियों को अनुदान बढ़ाया

कोलकाता: लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में दुर्गा पूजा कमेटियों को मिलने वाला वार्षिक अनुदान इस बार 15 हजार रुपये बढ़ाकर 70 हजार से 85 हजार रुपये कर दिया है। मंगलवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्यभर के दुर्गा पूजा आयोजकों और पुलिस- प्रशासन के साथ आयोजित समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। पिछले साल राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा कमेटियों के अनुदान में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर 60 से 70 हजार रुपये कर दिया था। (राब्यू)

माता वैष्णो देवी के बैटरी कार मार्ग का कुछ हिस्सा धंसा

कटड़ा: लगातार बारिश के कारण जमीन धंसने से माता वैष्णो देवी के बैटरी कार मार्ग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मंगलवार तड़के तीन बजे से इस मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। बैटरी कार सेवा भी स्थगित कर दी गई। हालांकि, पुराने पारंपरिक मार्ग से यात्रा जारी है। वहीं, बादल छाए रहने से कटड़ा से सांझी छत और जम्मू से भवन मार्ग पर स्थित पंछी हेलीपैड तक चलने वाली हेलीकाप्टर सेवाएं मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बाधित रहीं। बैटरी कार मार्ग को दुरुस्त करने को लेकर श्राइन बोर्ड प्रशासन ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। (संस)

सिंघवी की याचिका पर अब छह अगस्त को होगी सुनवाई

शिमला: भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिका पर अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी। सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में मत की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को चुनौती दी है। हर्ष महाजन ने इस याचिका में जरूरी पक्षकारों को प्रतिवादी न बनाए जाने को गंभीर त्रुटि बताते हुए खारिज करने की मांग की है। (विधि संवाददाता)

परमाणु संयंत्र के पास से छह रूसी नागरिक गिरफ्तार

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार को छह रूसी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। वे सभी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के आसपास घूमते पाए गए थे। स्थानीय मछुआरों ने रूसी नागरिकों को उसके आसपास घूमते देखकर पुलिस को सूचना दी थी। विदेशियों के साथ ही वल्लियूर के दो व्यक्ति और तिरुअनंतपुरम का रहने वाला कार चालक भी हिरासत में लिया गया है। (प्रेट्र)

बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंकी संगठनों से संपर्क

कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने महानगर से गिरफ्तार तीन बांग्लादेशी घुसपैठियों के जमात-उल-मुजाहिदीन या किसी अन्य आतंकी संगठनों के साथ संपर्क होने का संदेह व्यक्त किया है। घुसपैठियों ने कोलकाता के निकट नरेंद्रपुर में डेरा डाला था। वह अलग-अलग जगहों पर कार से आते जाते थे। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि तीन में से एक बांग्लादेशी पिछले सात वर्षों से गलत पहचान के तहत राज्य के नदिया जिले में रह रहा था। (राब्यू)

बिहार में अगवा कर ले जा रहे अपराधियों से भिड़े ग्रामीण

झाझा (जमुई): बिहार के जमुई जिले में ग्रामीण सोमवार की देर रात दो ठेकेदार को अगवा कर ले जा रहे बदमाशों से भिड़ गए। पांच करोड़ की फिरौती के लिए इन दोनों का अपहरण किया गया था। दो बदमाशों को पकड़कर उनकी पिटाई की फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों हथियारबंद अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, इनके अन्य साथी अपराधी भाग निकले। गिरफ्तार बदमाशों में कुख्यात धर्मा पासवान और कर्मा पंचायत का पूर्व मुखिया अर्जुन सिंह है। (जासं)

राज्यपाल की अनुमति के बिना तृकां के चार नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई गई शपथ

राज्यपाल पर जमकर बरसीं ममता, कहा- राजभवन नामिनेटेड है और विधानसभा इलेक्टेड

- सीएम ने विस अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया

बंगाल विस में सदस्यता की शपथ के बाद बाएं से, मधुपर्णा ठाकुर, कृष्णा कल्याणी, मुकुट मणि व सुप्ति पाण्डेय। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल में राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने हाल में हुए बंगाल विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के चार विधायकों को मंगलवार को विधानसभा में शपथ दिलाई। इस कदम के बाद राजभवन के साथ टकराव और बढ़ने के आसार हैं। शपथ के दौरान सदन में मौजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराते हुए राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस पर जमकर बरसीं।

राज्यपाल की आलोचना करते हुए उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ में जानबूझकर अड़ंगा डालने और विधानसभा के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। ममता ने राज्यपाल को संविधान की याद दिलाते हुए कहा कि लाइन मानकर चलिए लाइन से बाहर नहीं। याद रखिए राजभवन (राज्यपाल) नामिनेटेड है जबकि विधानसभा इलेक्टेड है। राज्यपाल को कानून के अनुसार काम करना चाहिए।

क्या राज्यपाल को टिफिन के पैसे चाहिए : इससे पहले लोकसभा के साथ हुए विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित तृणमूल के दो विधायकों की शपथ को लेकर राजभवन के साथ खासा विवाद हुआ था। पिछले मामले में राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष की बजाय उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उनके इन्कार के बाद अध्यक्ष ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दोनों को शपथ दिला दी थी। जिसे राज्यपाल असंवैधानिक बता चुके हैं। राज्यपाल ने सोमवार को ही दोनों विधायकों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अवैध तरीके से शपथ लेने के लिए उनपर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ममता ने सदन में इसपर भी टिप्पणी करते हुए राज्यपाल से पूछा कि क्या आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं? क्या आपको टिफिन के पैसे चाहिए। आप कहें तो मैं इसका इंतजाम कर दूंगी।

राज्यपाल ने बांग्लादेश के हिंसक आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने बांग्लादेश में चल रहे हिंसक आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर संविधान की धारा 167 के अंतर्गत रिपोर्ट मांगी है। मालूम हो कि ममता ने गत 21 जुलाई को कोलकाता में हुई तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में कहा था कि बांग्लादेश के असहाय लोग अगर मदद के लिए बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो उन्हें शरण दी जाएगी।

राजभवन सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान असंवैधानिक है। उन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस तरह की बातें कही हैं। संविधान के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री ऐसा आश्वासन नहीं दे सकतीं। ममता ने बयान के समर्थन में कहा था कि अशांत क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करना संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है। ममता ने बंगाल के उन निवासियों को भी सहयोग का आश्वासन दिया था, जिनके सगे-संबंधी हिंसा के कारण बांग्लादेश में फंस गए। उन्होंने उन बांग्लादेशियों की भी सहायता करने की बात कही थी, जो बंगाल से देश लौटने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

ममता बनर्जी और डा. सीवी आनंद बोस। फाइल

आइएनएस ब्रह्मपुत्र दुर्घटना की जांच करेंगे नौसेना के रियर एडमिरल

- युद्धपोत दुर्घटना की जांच रिपोर्ट आने के बाद तय होगी जवाबदेही
- आइएनएस ब्रह्मपुत्र को सीधा करने की कोशिशें लगातार जारी है

नई दिल्ली, एएनआइ: आइएनएस ब्रह्मपुत्र युद्धपोत से जुड़ी दुर्घटना पर कड़ी रुख अपनाते हुए नौसेना मुख्यालय ने सटीक कारणों का पता लगाने और जांच रिपोर्ट के आधार पर जवाबदेही तय करने के लिए रियर एडमिरल के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया है। इसकी दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए कहा गया है।

रविवार रात को आग लगने की घटना के बाद युद्धपोत नौसेना डाकयार्ड में एक तरफ झुक गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने मंगलवार को मुंबई नौसैनिक डाकयार्ड में आग के कारण युद्धपोत आइएनएस ब्रह्मपुत्र को हुए नुकसान की समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने डाकयार्ड का दौरा कर स्थिति का आकलन किया और युद्धपोत की मरम्मत के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस दौरान संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों को संभालने में बहुत सावधानी बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। नौसेना प्रमुख को पश्चिमी कमान के अधिकारियों ने दुर्घटना और बल द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।

वहीं, पणजी में नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि युद्धपोत को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। आग की घटना के बाद लापता हुए नाविक को रविवार के दिन जहाज से बाहर जाते हुए देखा गया था और उसका पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आग लगने की घटना के बाद आइएनएस ब्रह्मपुत्र एक तरफ झुक गया था और उसे सीधा करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। गौरतलब है कि युद्धपोत आइएनएस ब्रह्मपुत्र पर रविवार को आग लग गई थी, जिससे युद्धपोत को काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान एक नाविक लापता हो गया है।

मर्चेंट नेवी के जहाज में लगी भीषण आग बुझाई गई

गोवा के पास करवार तट पर मर्चेंट कंटेनर जहाज में लगी आग बुझा दी गई है। गंभीर खतरे को देखते हुए प्रभावित जहाज को गहरे समुद्र में ही रहने देने के प्रयास जारी हैं। जहाज इस समय न्यू मैंगलोर से 13 समुद्री मील पश्चिम में है और खुले समुद्र की ओर जा रहा है। एमवी मर्सक फ्रैंकफर्ट, जिसमें 1,154 कंटेनर थे, जिनमें बेंजीन और सोडियम साइनेट जैसे खतरनाक माल भी थे, गोवा के तट से करीब 102 समुद्री मील दूर गुजरात के मुंद्रा से श्रीलंका के कोलंबो जाते समय आग लग गई थी।

बच्चों-अभिभावकों को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष मांगे माफी : प्रधान

- नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा मंत्री ने साधा निशाना
- कहा, उन्होंने की अराजकता और समाज में अशांति फैलाने की कोशिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नीट-यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी व विपक्षी नेताओं को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों व अभिभावकों को गुमराह करने और देश की परीक्षा प्रणाली को जिस तरह से निंदित किया है, उसके लिए उन्हें बच्चों-अभिभावकों के साथ शिक्षण समाज से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उन्होंने ऐतिहासिक बताया।

शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को नीट-यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि चुनाव के समय से ही राहुल गांधी अराजकता व समाज में अशांति फैलाने के षडयंत्र में लगे है। यह उनकी राजनीति का एक हिस्सा भी रहा है।

चुनावों में हार के बाद भी वह ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और वाद-विवाद अलग हो सकती है, लेकिन देश के विद्यार्थी सभी के होते हैं। वे किसी पार्टी के नहीं होते हैं। प्रधान ने कहा कि मैंने सोमवार को लोकसभा में भी राहुल गांधी के बेतुके सवालों का जवाब दिया था। बताया था कि मेरी सरकार ने परीक्षाओं में शुचिता लाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसकी जानकारी तो मैंने दी है। अब वह बताएं कि उन्होंने इस दिशा में क्या किया। किन कारणों से उनकी सरकार ने परीक्षा में सुधार से जुड़े तीन बिल को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि एनटीए को 21 वीं सदी की विश्वसनीय परीक्षा एजेंसी बनाने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। यह दो महीने में रिपोर्ट देगी।

नीट-यूजी 2024 प्रकरण पर मंगलवार को नई दिल्ली में प्रेसवार्ता के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रेट्र

एक-दो दिनों में जारी हो जाएगी नई मेरिट लिस्ट, जल्द शुरू होगी काउंसलिंग

प्रधान ने नीट-यूजी काउंसलिंग के जल्द शुरू होने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगले एक दो दिनों में एनटीए की ओर से नीट-यूजी की नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जो परीक्षा में एक सवाल के सही जवाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसले पर आधारित होगी। नई मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ ही नीट-यूजी का पूरा रिजल्ट एनएमसी को दे दिया जाएगा।

जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला

- जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल ने सुनाए दो अलग-अलग फैसले
- पीठ ने सर्वसम्मति से कहा, इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों (जीएम सरसों) की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं पर विभाजित फैसला सुनाया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मंगलवार को दो अलग-अलग फैसले सुनाए है। जस्टिस नागरत्ना ने भारत में जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति देने के खिलाफ फैसला सुनाया है। जस्टिस करोल ने असहमति जताई और जीएम सरसों की वाणिज्यिक बिक्री को मंजूरी देने के जीईएसी के फैसले को बरकरार रखा है।

हालांकि पीठ ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया कि केंद्र को देश में अनुसंधान, खेती, व्यापार और वाणिज्य के लिए जीएम फसलों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। पीठ ने जीएम सरसों के उत्पादन की शुरुआत की सिफारिश करने के जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के 18 अक्टूबर, 2022 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सिफारिशें करने के लिए केवल वैश्विक स्तर पर उपलब्ध विदेशी शोध अध्ययनों का उपयोग किया गया है। स्वदेशी रूप से किए गए शोध अध्ययनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं किया गया। इसे देखते हुए, मैं कहता हूं कि 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2022 की मंजूरी गलत है। जस्टिस करोल ने कहा कि जीईएसी की संरचना नियमों के अनुसार है और इसलिए संवैधानिक चुनौती विफल हो जाएगी। जीईएसी द्वारा दी गई मंजूरी एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा दी गई है और इसलिए, इस तरह की मंजूरी को चुनौती नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज में खनन पट्टों पर अंतिम मंजूरी रोकी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अरावली पर्वतमाला वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मंजूरी के बिना खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए अंतिम अनुमति देने पर रोक रहेगी। अरावली दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में फैली हुई है। खनन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दो नए आवेदनों पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने सहित पट्टों के नवीनीकरण के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अदालत की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना अरावली रेंज में खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए कोई अंतिम अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नौ मई के आदेश को दोहराया, जहां उसने कहा कि अरावली रेंज के राज्य खनन पट्टों के अनुदान व नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन अंतिम अनुमति नहीं दी जाएगी।

बिहार में मेयर व डिप्टी मेयर के विरुद्ध नहीं लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: राज्य की किसी भी नगरपालिका में मेयर व डिप्टी मेयर के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। ये अपना पांच वर्षों का कार्यकाल पूरा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के किसी नियम, निर्देश के खिलाफ भी नगरपालिकाओं की बैठक में प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। मंगलवार को विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि मेयर और डिप्टी मेयर का चयन चुनाव से होता है। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जाता है। इस नियम को खत्म किया गया है। नगरपालिकाओं एवं उसकी समिति की बैठक से संबंधित स्पष्टता न होने की वजह से आयोजित होने वाली बैठकों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। संशोधन विधेयक 2024 में प्रविधान किए गए हैं कि किसी भी बैठक में सरकार के नियम, निर्देश के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।

जामताड़ा के जिन साइबर ठगों पर बनी वेबसीरीज, उन्हें पांच-पांच वर्ष की सजा

- पीएमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, साइबर अपराध में पहली बार ईडी ने दर्ज किया था मनी लांड्रिंग का मामला

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

जामताड़ा के जिन साइबर ठगों के गिरोह पर वेब सीरीज बनी, वह अब पांच वर्ष तक जेल में बंद रहेंगे। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग मामले में इन पांचों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इन पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को छह महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सजा पाने वालों में गणेश मंडल, उसका बेटा प्रदीप कुमार मंडल, संतोष मंडल उसका बेटा पिंटू मंडल के अलावा अंकुश कुमार मंडल शामिल है। अभियुक्त बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे।

सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार ने कहा कि साइबर क्राइम समाज के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे लोगों पर दया नहीं, बल्कि इन्हें अधिकतम सजा दी जाए।

बता दें कि अभियुक्तों पर फर्जी पते पर सिम कार्ड लेने और बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन कर अपराध करने का आरोप है। ये लोग केवाइसी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी पूछकर खातों से पैसे निकाल लेते थे। ईडी ने साइबर अपराध के किसी मामले में पहली बार छह अगस्त 2018 को मामला दर्ज किया था। साइबर अपराध की कमाई से इनकी 85 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है।

कुपवाड़ा में मुठभेड़, चार-पांच पाक आतंकी घिरे

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में त्रिमुखा की पहाड़ियों में छिपे आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मंगलवार शाम से मुठभेड़ शुरू हुई, जो देर रात तक जारी थी। घेराबंदी में चार से पांच पाकिस्तानी आतंकियों के होने की सूचना है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों को पता चला था कि आतंकियों का दल कुपवाड़ा की लोलाब घाटी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसी आधार पर लोलाब घाटी के विभिन्न हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। शाम को त्रिमुखा की पहाड़ियों में तलाशी ले रहे जवानों ने स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के दल को पेड़ों के बीच गुजरते देखा। जवानों ने ललकारते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा तो आतंकियों ने भागने के साथ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। सूचना मिलते ही निकटवर्ती शिविरों से सुरक्षाबलों की अतिरिक्त टुकड़ियां मुठभेड़ स्थल की तरफ रवाना हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इस अभियान में सेना की 22 और 28 आरआर शामिल हैं।

मजहबी कट्टरपंथ बड़ी चुनौती, कई देश इसे फैला रहे : दत्तात्रेय होसबाले

- बीएमएस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा, भारत इसे रोकने का काम कर सकता है
- संस्कृति का नाश कर कोई समाज खड़ा नहीं हो सकता, मजदूरों में कोई ऊंचा-नीचा नहीं होता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के सामने आज बड़ी चुनौती मजहबी कट्टरपंथ है। कई देश इसे फैला रहे हैं। संवाद, सामंजस्य और वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा से भारत इसे रोकने का काम कर सकता है। मजदूर के लिए आर्थिक हित बाद में, पहले समाज और राष्ट्रहित है।

पंथ-संप्रदाय अलग-अलग हो सकते हैं, पर सबसे ऊपर मजदूर की संस्कृति है। संस्कृति का नाश कर कोई समाज खड़ा नहीं हो सकता। मजदूरों में कोई ऊंचा-नीचा नहीं होता। वह मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में बीएमएस के 70वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी उपस्थित थे।

होसबाले ने कहा कि पर्यावरण का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उल्लेख करते उन्होंने कहा कि हमें तंत्र का गुलाम नहीं बनना है। उपकरण आवश्यक हैं, पर मनुष्य से ऊपर नहीं है।

इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या ने कहा कि 95 प्रतिशत कामगार वाले असंगठित क्षेत्र में भी हम हर जगह पहुंचेंगे। इसके लिए हम सभी को काम करना होगा और संपर्क बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य वी भागैया ने कहा कि नाम कमाना भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य नहीं है। 'मैं नहीं तू' की धारणा के चलते मजदूर संघ आगे बढ़ा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सम्मान और न्याय मिलना चाहिए।

विकलांग सास-ससुर पर मारपीट के आरोप लगाने वाली बहू पर एक लाख का जुर्माना

- हाई कोर्ट ने बहू की ओर दर्ज कराई एफआइआर को किया रद
- टिप्पणी- एफआइआर कानून की उचित प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महिला पर अपने शत-प्रतिशत विकलांग सास-ससुर के खिलाफ शारीरिक क्रूरता की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया था कि सास-ससुर उसके पीछे दौड़े और डंडे से मारा जबकि वे पूरी तरह से विकलांग पाए गए।

झज्जर निवासी वृद्ध दंपती के खिलाफ क्रूरता की एफआइआर को रद करते हुए जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा कि कानून की पवित्रता, कानूनी प्रक्रिया और पीड़ा को कम करने के लिए बनाए गए इसके प्रविधान का व्यक्तिगत रूप से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। चार महीने की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ताओं को बराबर हिस्सों में यानी 50-50 हजार रुपये में वितरित किया जाएगा। पेश मामले में एफआइआर कानून की उचित प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इसलिए शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की सास और ससुर 100 प्रतिशत विकलांग हैं, यहां तक कि चलने में भी असमर्थ हैं। उनके लिए अपने दैनिक कार्य पूरा करना भी अत्यधिक कठिनाई भरा होगा। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता ने ही सास-ससुर पर अत्याचार और दुर्व्यवहार किया है। एफआइआर में लगाए गए आरोपों का सरासर झूठ इससे साबित होता है कि ससुर बैसाखी पर है और सास व्हीलचेयर से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में इस कोर्ट का अंतरात्मा शिकायतकर्ता के घोर आरोप से स्तब्ध है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगाना अमानवीय और अक्षम्य है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

जयपुर में मीट की दुकानों पर लिखना होगा हलाल या झटका

जागरण संवाददाता, जयपुर : उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखे जाने के आदेश का मामला अभी सरगर्म ही है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम (ग्रेटर) ने मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य किया है।

निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। निगम खुले में मीट बेचना भी प्रतिबंधित किया है। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि जहां लोग रहते हैं, उसके आसपास मीट की मंडी नहीं होनी चाहिए। निगम ने तय किया है कि अब उन्हीं मीट दुकानों को लाइसेंस दिया जाएगा, जिनके पास व्यावसायिक पट्टा होगा। कांवड़ यात्रा मार्गों की पवित्रता का भी ध्यान रखा जाएगा। इस मार्ग पर और शिव मंदिरों के निकट खुले में मीट की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।

बिहार में जाति सर्वे पर सितंबर में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

- कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से लिखित में दलील दाखिल करने को कहा है
- पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र: बिहार में जाति सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सितंबर में अंतिम सुनवाई होगी। याचिका में जाति सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने पक्षों से पूछा कि क्या राज्य को जाति सर्वे कराने का अधिकार है और किन शर्तों पर व परिस्थितियों में कानून के तहत ऐसा करना वर्जित है। कोर्ट ने याचिकार्कताओं से इस सबंध में लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है।

पीठ ने बिहार सरकार के जाति सर्वे को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह से कहा कि उनकी दलीलें इस बात से संबंधित होनी चाहिए कि क्या राज्य द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। इस पर वकील अराजिता सिंह ने कहा कि उनकी चुनौती का मुख्य बिंदु यह है कि राज्य द्वारा किए गए सर्वे ने व्यक्तियों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है क्योंकि लोगों को अपनी जाति का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इससे लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंद्रा साहनी फैसले के तहत व्यक्तिगत जाति सर्वे पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के सर्वे में हर किसी पर जाति की पहचान का खुलासा करना अनिवार्य है।

मुरादाबाद में पंचायत में किशोरी की आबरू की कीमत दो बीघा जमीन

जासं, मुरादाबाद : 55 वर्षीय मौलाना एक मजदूर की 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करता रहा। किशोरी के गर्भवती होने पर मामला रफा-दफा करने के लिए पंचायत में बोली लगाई गई। करीब 10 लाख रुपये कीमत की दो बीघा जमीन में मामला निपट गया। गांव में कई दौर की पंचायत होने के बाद भी पुलिस को भनक नहीं लगी।

एक मौलाना मुस्लिम किशोरी के साथ लंबे अरसे से दुष्कर्म कर रहा था। जान से मारने की धमकी देकर उसे स्वजन को बताने से रोकता रहा। किशोरी के गर्भवती होने पर करीब एक माह पहले स्वजन को जानकारी हुई। पूछने पर किशोरी ने सब कुछ बता दिया। स्वजन मौलाना के पास गए तो उसने गांव में लोगों से दबाव बनाकर पंचायत करने को मजबूर कर दिया।

****

11 साल की बच्ची से लेकर 61 साल की बुजुर्ग तक पेरिस में दिखाएंगी दम

नई दिल्ली, जेएनएन : पेरिस 26 जुलाई से ओलिंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनियाभर के करीब 10,000 एथलीट हिस्सा लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में 11 साल की बच्ची लेकर 61 साल की घुड़सवार तक अपनी चमक बिखेरती नजर आएंगी। भारत की ओर से 117 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा, जिनमें तैराक धिनिधि देसिंघु सबसे युवा तो रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज होंगे।

चीन की झेंग सबसे युवा

11 साल और 11 महीने की स्केटबोर्डर झेंग हाओहाओ पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वह सबसे कम उम्र के ओलिंपियन ग्रीस के जिम्नास्ट दिमित्रोस लाउंडरास से एक साल बड़ी हैं। दिमित्रोस ने 1896 में दस वर्ष 218 दिन की उम्र में पहला ओलंपिक खेला था। 11 अगस्त को 12 वर्ष की हो रही झेंग ने बुडापेस्ट और शंघाई में क्वालीफिकेशन सीरीज के बाद पेरिस का टिकट कटाया। मजे के लिए स्केटबोर्डिंग खेलना शुरू करने वाली झेंग ने कहा, किसी ने मुझे बोला कि स्केटबोर्डिंग में बहुत मजा आता है और वाकई यह सच था। टोक्यो ओलिंपिक क्वालीफायर में पहली बार एक लड़की को स्केटबोर्डिंग करते देखा तो मुझे वह बहुत कूल लगी।

कनाडा की घुड़सवार सबसे बुजुर्ग

कनाडा की घुड़सवारी टीम की सदस्य जिल इरविंग 61 वर्ष की उम्र में पेरिस ओलिंपिक में पदार्पण करेंगी। आस्ट्रेलिया की मेरी हान्ना 1996 अटलांटा ओलिंपिक से छह ओलंपिक खेल चुकी हैं और 69 वर्ष की उम्र में घुड़सवारी टीम (ड्रेसेज) में रिजर्व खिलाड़ी हैं और शायद प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका नहीं मिले। आस्ट्रेलियाई टीम में किसी के चोटिल या बीमार होने पर ही उन्हें बुलाया जाएगा। ओलिंपिक के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्वीडन के निशानेबाज आस्कर स्वान थे, जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेला था।

बोपन्ना सबसे उम्रदराज भारतीय

44 वर्ष और चार महीने के बोपन्ना पेरिस ओलिंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं। वह तीसरा ओलिंपिक खेल रहे हैं और पुरुष डबल्स में श्रीराम बालाजी के साथ उतरेंगे। उन्होंने लंदन ओलिंपिक 2012 में महेश भूपति के साथ पदार्पण किया था। भारतीय दल में 42 साल के अचंता शरत कमल और 40 साल के तीरंदाज तरुणदीप राय भी हैं। वहीं अगर भारत की ओर से ओलिंपिक में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात करें तो वह स्कीट निशानेबाज भीम सिंह बहादुर हैं जिन्होंने 1976 मांट्रियल ओलंपिक में 66 वर्ष की उम्र में हिस्सा लिया था।

सबसे युवा भारतीय धिनिधि

200 मीटर फ्रीस्टाइल में उतरने वाली 14 वर्ष दो महीने की धिनिधि देसिंघु भारतीय दल की सबसे युवा सदस्य हैं। बेंगलुरु में नौवी की छात्रा देसिंघु ने यूनिवर्सल कोटा के जरिये क्वालीफाई किया है। इसमें अगर किसी देश के तैराक सीधे क्वालीफाई नहीं करते तो वहां के दो शीर्ष तैराकों को मौका मिलता है। देसिंघु ओलिंपिक में भाग लेने वाली अब तक की भारत की दूसरी युवा एथलीट हैं। 11 वर्ष की तैराक आरती साहा ने 1952 हेलिंस्की ओलिंपिक में भाग लिया था।

ओलिंपिक के बाद संन्यास लेंगे एंडी मरे

पेरिस, एपी : पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी एंडी मरे पेरिस ओलिंपिक के बाद संन्यास लेंगे। मरे ने मंगलवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी।

2008 में बीजिंग में अपना पहला ओलिंपिक खेलने वाले 35 वर्षीय मरे पेरिस में सिंगल्स और डबल्स स्पर्धा में हिस्सा लेंगे, जो उनका पांचवां ओलिंपिक होगा। एंडी मरे ने एक्स पर लिखा, अपने आखिरी टेनिस टूर्नामेंट के लिए पेरिस पहुंचा हूं। टीम ब्रिटेन के लिए प्रतिस्पर्धा करना मेरे करियर का अब तक का सबसे यादगार सप्ताह रहा है और मुझे इसे अंतिम बार खेलने का मौका पाकर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। ब्रिटिश खिलाड़ी ने 2012 लंदन ओलिंपिक के सिंगल्स में रोजर फेडरर को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। रियो 2016 खेलों में वह अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोत्रो को हराकर दो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने थे। पेरिस में टेनिस स्पर्धा 27 जुलाई से शुरू होगी और चार अगस्त को समाप्त होगी, जिसमें पदक मुकाबले दो अगस्त से खेले जाएंगे।

सात्विक-चिराग **स्वर्ण के प्रबल दावेदार** ओलिंपिक में रजत और कांसा जीत चुकी सिंधू की नजरें पदक का रंग बदलने पर

स्वर्णिम उड़ान भरने को तैयार भारतीय 'चिड़िया'

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पेरिस ओलिंपिक 26 जुलाई को सीन नदी पर एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पेरिस में बैडमिंटन की स्पर्धाएं 27 जुलाई से खेली जाएंगी और भारत के सात खिलाड़ी इसमें चुनौती पेश करेंगे। इनमें पीवी सिंधू एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो दो ओलिंपिक पदक जीत चुकी हैं। सिंधू ने रियो में रजत और टोक्यो में कांस्य पदक जीता था और अब उनकी नजरें पदक का रंग बदलने पर होंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी भी स्वर्ण की प्रबल दावेदार है। 2016 ओलिंपिक के बाद दूसरी बार बैडमिंटन में सात भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे।

बैडमिंटन में अब तक भारतीय महिलाओं ने ही तीन पदक जीते हैं। सर्वप्रथम साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलिंपिक में कांस्य जीता। इसके बाद सिंधू ने भारत के लिए दो पदक 2016 रियो में रजत और 2020 टोक्यो में कांस्य जीता। इस बार पीवी सिंधू महिला सिंगल्स में खेलने वाली एकमात्र महिला एथलीट हैं, जबकि तनीषा और अश्विनी की जोड़ी डबल्स में प्रतिस्पर्धा करेंगी। एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन सिंगल्स में जबकि सात्विकसाईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी डबल्स में भाग लेगी।

अश्विनी पोनप्पा 35 वर्ष, केरल
उपलब्धि | महिला डबल्स
- राष्ट्रमंडल खेल 2022 : रजत (मिक्स्ड टीम)
- एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 : स्वर्ण (टीम)
- अबु धाबी मास्टर्स 2023 : स्वर्ण (डबल्स)

तनीषा क्रास्टो 21 वर्ष, गोआ
उपलब्धि | महिला डबल्स
- एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 : स्वर्ण
- अबु धाबी मास्टर्स 2023 : स्वर्ण (डबल्स)
- सैयद मोदी 2023 : रजत (डबल्स)

पीवी सिंधू 28 वर्ष, हैदराबाद (तेलंगाना)
उपलब्धि | महिला सिंगल्स
- ओलिंपिक : रजत (रियो), कांस्य (टोक्यो)
- सिंगापुर ओपन 2022 : स्वर्ण
- विश्व चैंपियनशिप 2019 : स्वर्ण

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी 23 वर्ष, आंध्र प्रदेश
पुरुष डबल्स
उपलब्धि
- एशियाई खेल 2022 : स्वर्ण (डबल्स)
- थामस कप 2022 : स्वर्ण (टीम)
- फ्रेंच ओपन 2022, 2024 : स्वर्ण (डबल्स)

चिराग शेट्टी 27 वर्ष, मुंबई (महाराष्ट्र)
उपलब्धि | पुरुष डबल्स
- एशियाई खेल 2022 : स्वर्ण
- थामस कप 2022 : स्वर्ण
- फ्रेंच ओपन 2022, 2024 : स्वर्ण (डबल्स)

शटलरों के पीछे माता-पिता की अथक मेहनत

ओलिंपियन बनाने का कोई नुस्खा नहीं होता लेकिन इसके पीछे बलिदानों और जज्बातों से भरी कहानियां जरूर होती हैं। दुबई में जन्मी तनीषा पेरिस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। छह साल पहले जब उनके पिता क्लिफोर्ड क्रास्टो ने जब उनके 15वें जन्मदिन पर हैदराबाद की पुलेला गोपीचंद अकादमी में भेजा था तो इसी उम्मीद पर कि दुबई में अपने घर से दूर रहकर भी वह बैडमिंटन में नाम कमाने के अपने सपने पूरे कर सकेगी। क्लिफोर्ड ने बताया, यह काफी साहसिक और जज्बाती फैसला था कि उसे एक अलग देश में अकेले छोड़ना है। हम दोनों के लिए यह कठिन था लेकिन हमें पता था कि उसने सही रास्ता चुना है और हमने उसका साथ दिया। वहीं, सात्विक के पिता काशी विश्वनाथम ने बताया कि अंडर-15 टूर्नामेंट में पुलेला गोपीचंद ने सात्विक को देखा और कहा कि उन्हें भारत की टीम चैंपियनशिप के लिए पुरुष डबल्स खिलाड़ी चाहिए। पहले कुछ साल आर्थिक रूप से मेरे लिए कठिन था, लेकिन मेरे परिवार और दोस्तों ने मदद की। फिर 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छे प्रदर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा।

लक्ष्य सेन 22 वर्ष, उत्तराखंड
उपलब्धि | पुरुष सिंगल्स
- एशियाई खेल 2022 : रजत (टीम)
- राष्ट्रमंडल खेल 2022 : स्वर्ण (सिंगल्स)
- थामस कप 2022 : स्वर्ण (टीम)

एचएस प्रणय 32 वर्ष, तिरुअनंतपुरम
उपलब्धि | पुरुष सिंगल्स
- एशियाई खेल 2022 : कांस्य, रजत (टीम)
- थामस कप 2022 : स्वर्ण (टीम)
- एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2023 : कांस्य

पेरिस में आधे होटल खाली, स्थानीय यातायात महंगा

ओलिंपिक डायरी

पेरिस, प्रेट्र : पेरिस में ओलिंपिक के दौरान होटलों की भारी मांग दिखाई गई, जिससे पेरिस के कई लोगों ने कमाई के लिए अपने घरों को किराये पर लगा दिया लेकिन होटलों की उतनी मांग है नहीं। एक होटल के मैनेजर समीर ने कहा कि इस समय हमारे होटल में एक रात का किराया 120 यूरो (लगभग 11 हजार रुपये) रहता है लेकिन हम आधे दाम पर लगा रहे हैं। ओलिंपिक की मेजबानी हमारे लिए अच्छी नहीं रही। काफी पाबंदियां हैं और कई जगहों पर जाने के लिए क्यूआर कोड चाहिए।

वहीं, स्थानीय निवासी भी ओलिंपिक के आयोजन से खुश नहीं है क्योंकि इसका उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है। स्थानीय यातायात 2.15 यूरो (195 रुपये) से बढ़कर चार यूरो (363 रुपये) तक पहुंच गया है और आठ सितंबर को पैरालिंपिक तक यही किराया रहेगा। आयोजन स्थलों के आसपास आवागमन पर भी पाबंदियां हैं।

क्या वाकई साफ है सीन नदी: ओलिंपिक के लिए स्थानीय प्रशासन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीन नदी की सफाई था। ओलिंपिक के इतिहास में पहली बार पानी पर उद्घाटन समारोह हो रहा है। सीन नदी में तैराकी पर सौ साल पहले प्रतिबंध लग गया था लेकिन इसकी सफाई पर डेढ़ अरब यूरो (1363 करोड़ रुपये) खर्च किए गए। पेरिस के मेयर एने हिडाल्गो ने पिछले सप्ताह डुबकी लगाकर इसे तैराकी के लिए सुरक्षित करार दिया।

आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कोविड-19 पाजिटिव

पेरिस, आइएएनएस : आस्ट्रेलिया के वाटर पोलो खिलाड़ी को कोविड-19 टेस्ट में पाजिटिव पाए जाने के बाद पेरिस खेलों में अलग कर दिया गया है। इसकी पुष्टि देश की ओलिंपिक टीम प्रमुख एना मेयर्स ने मंगलवार को की। एथलीट का नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन वायरस के प्रसार को रोकने के लिए करीबी संपर्कों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और परीक्षण किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो 2020 ओलिंपिक में एक साल की देरी हुई और सीमित दर्शकों के साथ आयोजित किया गया।

खेलो इंडिया को ₹ 900 करोड़

नई दिल्ली, प्रेट्र : जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया को एक बार फिर खेल मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में सबसे अधिक राशि आवंटित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3,442.32 करोड़ रुपये में से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 880 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन से 20 करोड़ रुपये अधिक है। इस साल अगस्त में पेरिस ओलंपिक चक्र समाप्त होने वाला है और राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों अभी भी दो साल का समय है। ऐसे में पिछले चक्र की तुलना में केवल 45.36 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

खेल मंत्रालय के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में बजट 3,396.96 करोड़ रुपये था। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया में भारी निवेश किया है क्योंकि यह कार्यक्रम देश से प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपये था। अगले साल (2023-24) के बजट में लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया था। इसे हालांकि संशोधित कर 880 करोड़ रुपये किया गया था।

केंद्रीय बजट 2024 में खेल संरचना में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा के वित्त मंत्री का आभार। यह पूरे खेल समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। नई खेल सुविधाओं का विकास न केवल गर्व की बात है, यह प्रतिभाओं को विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

-राकेश तिवारी, अध्यक्ष, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन

भारत के पाक में नहीं खेलने की स्थिति में आइसीसी ने की तैयारी

कराची, प्रेट्र: पीसीबी ने अगले वर्ष होने वाली चैंपियंस ट्राफी के लिए बीसीसीआइ को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए मनाने का काम आइसीसी पर छोड़ा है। कोलंबो में हुई आइसीसी की बैठक में चैंपियंस ट्राफी के बजट को मंजूरी दी गई है। आइसीसी ने अपने टूर्नामेंट बजट में पूरक खर्चे को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रखा है और इसमें भारतीय टीम के पाकिस्तान से बाहर खेलने की संभावना भी शामिल है।

बीसीसीआइ ने हमेशा ही कहा है कि पाकिस्तान में खेलना पूरी तरह से भारत सरकार का निर्णय है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले एशिया कप में भी टीम भेजने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद ये टूर्नामेंट हाइब्रिड माडल के आधार पर श्रीलंका में आयोजित किया गया था। पीसीबी ने चैंपियंस ट्राफी में भारत के सभी मैच लाहौर में करने का सुझाव दिया है।

भारतीय बेटियां सेमीफाइनल में

अंतिम ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रनों से हराया, शेफाली का अर्धशतक, दीप्ति के तीन विकेट

नई दिल्ली, जेएनएन : भारत ने महिला टी-20 एशिया कप के अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में नेपाल को 82 रन से हराकर शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ग्रुप ए में तीनों मुकाबले जीतकर शीर्ष पर रही और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ अंतिम चार में पहुंचीं। पाकिस्तान ने इससे पहले मुकाबले में यूएई को 10 विकेट से हराया था।

भारत ने आक्रामक बल्लेबाज शेफाली वर्मा (81) की तूफानी अर्धशतकीय पारी के दम पर तीन विकेट पर 178 रन का स्कोर खड़ा किया था। दीप्ति ने केवल 48 गेंदों में 12 चौके और एक छक्का जड़ते हुए 81 रनों की पारी खेली। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत की जगह स्मृति मंधाना कप्तानी करने उतरी थीं, लेकिन उन्होंने ओपनिंग पर आने के बजाए हेमलता को बल्लेबाजी करने भेजा। शेफाली और हेमलता ने नेपाली गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और पहले विकेट के लिए 14 ओवर में 122 रन जोड़ डाले थे। हेमलता केवल तीन रन से अर्धशतक से चूक गईं। उन्होंने 42 गेंदों में 47 रन बनाए। इसके बाद आलराउंडर दीप्ति शर्मा और अरुंधति की शानदार गेंदबाजी ने नेपाल को नौ विकेट पर 95 रन ही बनाने दिए। अंत में बिंदु ने 17 रन बनाकर यह सुनिश्चित किया कि भारतीय गेंदबाज उनकी टीम को आलआउट न कर पाएं।

शेफाली वर्मा ● आइएएनएस

नए कप्तान सूर्य के संबोधन से हार्दिक की दूरी

नई दिल्ली, जेएनएन : नए मुख्य कोच गौतम गंभीर की देखरेख में भारतीय टीम श्रीलंका के विरुद्ध तीन मैचों की सीरीज से पहले मंगलवार को पल्लेकेले में शुरुआती अभ्यास सत्र में उतरी। इस दौरान खिलाड़ियों ने हलका अभ्यास किया जिसमें क्षेत्ररक्षण अभ्यास, दौड़ने और गेंद को पकड़ने का अभ्यास शामिल था। हालांकि इस दौरान हार्दिक पांड्या नए कप्तान सूर्यकुमार यादव से कटे-कटे दिखाई दिए।

सूत्रों के अनुसार, जब नए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली बार हर्डल में टीम को संबोधित करने के लिए बुलाया तो उसमें हार्दिक पांड्या शामिल नहीं थे। अब वह किस कारण उस समय वहां नहीं थे ये मालूम नहीं।

हालांकि वह बाद में अभ्यास सत्र में शामिल हुए। मालूम हो कि रोहित शर्मा के टी 20 कप्तानी छोड़ने के बाद उपकप्तान हार्दिक ही दावेदार थे लेकिन नए कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने सूर्य को टीम की कमान सौंप दी। हालांकि वह इस दौरान गंभीर से लंबी चर्चा करते नजर आए। उन्होंने उनसे बैटिंग स्टांस पर भी बात की। हालांकि बाद में एक मिनट के लिए सूर्य और हार्दिक में बात हुई। दोनों मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते हैं। हार्दिक इस साल मुंबई के कप्तान बने हैं। टीम ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया था। तब से उन दोनों के संबंध भी अच्छे नहीं हैं।

श्रीलंकाई टीम में चांदीमल की वापसी, असलंका होंगे कप्तान

पल्लेकेले, प्रेट्र : चरिथ असलंका भारत के विरुद्ध 27 जुलाई से शुरू हो रही तीन मैचों की टी-20 सीरीज में श्रीलंका के कप्तान होंगे। श्रीलंकाई टीम में 24 वर्षीय दिनेश चांदीमल और कुशल परेरा की वापसी हुई है। स्पिन आलराउंडर वानिंदु हसरंगा के बाद असलंका को कप्तानी सौंपी गई है। हसरंगा ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में पिछले महीने हुए टी-20 विश्व कप में श्रीलंका की कप्तानी की थी। असलंका ने इस वर्ष की शुरुआत में बांग्लादेश दौरे पर भी दो टी-20 मैचों में कप्तानी की थी, जब हसरंगा निलंबन झेल रहे थे। टी-20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद चयनसमिति ने टीम में कई बदलाव किए हैं। आलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डिसिल्वा, सदीरा समाराविक्रमा और दिलशान माधुशंका को टीम से बाहर किया गया है। **श्रीलंका टीम :** असलंका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुशल परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महेश तीक्षणा, चामिंदु विक्रमासिंघे, पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो।

चरिथ असलंका

राष्ट्रीय फलक

दावानल रोकने को अगले सीजन से पहले सब कुछ ठीक करना होगा

- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के अफसरों को दिए निर्देश
- पीठ ने पाया अधिकांश आग मानव निर्मित कारणों से लगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों को उत्तराखंड में जंगल की आग को रोकने के लिए अगले सीजन से पहले सब कुछ ठीक करना होगा। अधिकांश घटनाएं मानव निर्मित कारणों से हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ उत्तराखंड में जंगल की आग से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने 17 मई को कहा था कि कीमती जंगलों को जंगल की आग के खतरों से बचाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि फिलहाल तत्काल कुछ नहीं है, लेकिन अगले सीजन से पहले आपको सब कुछ दुरुस्त करना होगा। अदालत ने कहा कि हमारे सामने पिछली सुनवाई के दौरान एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश की गई और हफ्ते भर के भीतर हमने अखबारों में पढ़ा कि जंगल की आग में चार वन रक्षकों की मौत हो गई।

मामले में पेश एक वकील ने शीर्ष अदालत के 17 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर गौर किया गया था कि वह खुद, राज्य के मुख्य सचिव, न्याय मित्र, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिनिधि और जंगल की आग के मुद्दे पर आवेदन दायर करने वाले वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता साथ बैठकर समाधान निकालेंगे। वकील ने कहा कि बैठकें पहले हो चुकी हैं और अगस्त में कुछ और होनी हैं। पीठ ने पाया कि इनमें से अधिकांश जंगल की आग मानव निर्मित कारणों के कारण हैं, मामले को सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

खुद को जिंदा साबित करने के लिए छात्रों को बंधक बनाया, शिक्षकों पर किया हमला

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में बालोतरा जिले के चुली बेरा धारणा गांव में स्वयं को जिंदा साबित करने के लिए 40 वर्षीय एक ग्रामीण ने सरकारी स्कूल में घुसकर न केवल छात्रों को बंधक बना लिया, बल्कि प्रधानाध्यापक व एक शिक्षक पर चाकू से हमला भी किया। घायल शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से ग्रामीण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि स्वजनों ने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है और अब उसकी जमीन खुद के नाम कराना चाहते हैं। ऐसे में उसने ऐसा कदम उठाया कि पुलिस गिरफ्तार कर ले और साबित हो जाए कि वह जिंदा है।

घटना 19 जुलाई की है। आरोपित ने बताया कि उसके बच्चे छोटे हैं। पत्नी बीमार रहती है। वह आर्थिक व शारीरिक रूप से कमजोर है। ऐसे में उसे जानकारी मिली कि स्वजनों ने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है और वे उसके हिस्से की जमीन हड़पना चाहते हैं। सरकारी कार्यालयों में उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उसे कोई यह नहीं बता रहा था कि उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र कैसे बना, जबकि वह जिंदा है।

ओडिशा के कानून मंत्री बोले- कुछ दिनों में होगा रत्न भंडार की लेजर स्कैनिंग पर निर्णय

- एएसआइ रिपोर्ट बाद तय होंगी लेजर स्कैनिंग व मरम्मत की बातें
- रत्न भंडार 46 वर्ष बाद गत 14 जुलाई को खोला गया

मीडिया से बात करते राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जागरण

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) विभाग की टीम दो-चार दिनों में पुरी श्रीमंदिर के रत्न भंडार के अंदर निरीक्षण का कार्य शुरू कर देगी। एएसआइ की रिपोर्ट के बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि रत्न भंडार की लेजर स्कैनिंग होगी या नहीं।

हरिचंदन पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एएसआइ के निरीक्षण कार्य से रत्न भंडार की मौजूदा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद उसकी मरम्मत की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। कानून मंत्री ने बताया कि रत्न भंडार के निरीक्षण, मरम्मत आदि कार्यों को केंद्र में रखकर रत्न भंडार में विद्यमान आभूषण और अन्य कीमती सामान पहले ही अस्थायी स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

बताते चलें कि रत्न भंडार 46 वर्ष बाद गत 14 जुलाई को खोला गया। फिर सभी कीमती सामान 18 जुलाई को श्रीमंदिर परिसर के अंदर अस्थायी स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित किए गए। निगरानी ओडिशा सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा की गई। एएसआइ के निरीक्षण व लेजर स्कैनिंग के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि रत्न भंडार के अंदर वास्तव में कोई सुरंग अथवा अन्य खजाना भी है, जिसकी चर्चा समय-समय पर होती रही है।

****

श्रद्धा का महासावन

शिव कृपा से ही संभव है जीवन के विष का भंजन

शिव सर्वदा और सर्वथा कल्याणकारी हैं। शिव रुद्र हैं। प्रकृति विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष में अभिव्यक्त विश्वव्यापक रुद्र स्वानुकूल जिन-जिन विशेष शक्तियों द्वारा जिन-जिन कार्यों का संचालन करते हैं, उन्हीं शक्तियों की उपासना वेदों में बताई गई है। समुद्र मंथन के समय विष जैसे महाविनाशक, हेय त्याज्य पदार्थ को ग्रहण कर उसके दुष्प्रभावों से समष्टि की रक्षा महादेव के सिवा भला कौन कर सकता था। प्रतीकात्मक रूप से समुद्र मंथन का अर्थ 'मनो मंथन' है। मन में विष और अमृत दोनों समाहित हैं। मन के नकारात्मक विचार, आलस्य, अकर्मण्यता, भ्रम, भय, अवसाद आदि ही जीवन के विष हैं, जिनका भंजन शिव कृपा से ही होता है। इसलिए शिव को विवेक और विचार का देवता कहा गया है। संहारक रूप में शिव तांडव करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से पुरुष और प्रकृति के मिलन का नाम ही तांडव है। उस समय अणु-अणु में क्रियाशीलता जागृत होती है और सृष्टि का निर्माण होता है। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के सृजन की ही परिणति है, किंतु सृजन के पूर्व की भूमिका महाकाल रुद्र के रूप में स्वयं शिव ही तैयार करते हैं। इसलिए वो सृजन के पूर्व से भी पूर्व हैं। वो सृष्टि, स्थिति और लय के आदि कारण हैं। शिव सबके हैं, जिनका कोई अवलंबन नहीं, उनके भी। शिव परम आश्रय हैं।

स्वामी अवधेशानंद गिरि, आचार्य महामंडलेश्वर, जूना पीठाधीश्वर

पहली बार आयनमंडल से परे प्रसारित हुई मानव ध्वनि

1954 में आज ही अमेरिका में नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में इंजीनियर जेम्स ट्रेक्सलर ने स्टंप नेक रेडियो एंटीना सुविधा में एक माइक्रोफोन में बात की थी। ढाई सेकेंड बाद उनकी आवाज आयनमंडल से परे प्रसारित होकर पांच लाख मील की यात्रा करते हुए चंद्रमा से परावर्तित होने के बाद पृथ्वी पर लौटी।

देश की पहली महिला ग्रैंडमास्टर बनीं एस विजयलक्ष्मी

2000 में आज ही के दिन एस विजयलक्ष्मी शतरंज में ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। उन्होंने विप्रो इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर चेस चैंपियनशिप के नौवें राउंड में पी हरिकृष्ण से मैच ड्रा कर यह खिताब हासिल किया था। इंटरनेशनल मास्टर का खिताब भी उनके पास है।

फिल्मों से देशभक्ति का भाव जगाने वाले हैं मनोज कुमार

अभिनेता मनोज कुमार का जन्म 1937 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के एबटाबाद (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। 1957 में फैशन फिल्म से अभिनय की शुरुआत की। 1961 में कांच की गुड़िया फिल्म ने पहचान दिलाई। 1967 में उपकार फिल्म से निर्देशन में कदम रखा। इसी फिल्म के बाद से उन्हें भारत कुमार का नाम मिल गया। बेइमान, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, पूरब और पश्चिम जैसी कई सफल फिल्में की। 1992 में पद्मश्री एवं 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए।

मस्तिष्क में विसंगतियां करती हैं खतरे की भविष्यवाणी

शोधकर्ताओं की एक टीम ने 20 वर्षों तक 5–34 वर्ष की आयु के 300 रोगियों का अनुसरण किया

जिनेवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने किया अध्ययन

- इसमें तीन मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच बातचीत में लगातार विसंगति पाई गई

प्रतीकात्मक

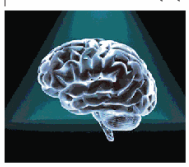

नई दिल्ली, प्रेट्र : हर 2000 व्यक्ति में से एक में मस्तिष्क की विसंगतियां पाई जाती हैं। मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच इसको प्रभावित करने वाले एक सामान्य जीन को हटाने से जुड़े विसंगतियां मनोविकृति के विकसित होने के खतरे का आकलन करने में मदद करती हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने 20 वर्षों तक 5-34 वर्ष की आयु के 300 रोगियों का अनुसरण किया, जो एक विशिष्ट जीन के हटाने से 22q11.2 डीएस माइक्रोडिलीशन से प्रभावित थे। इसमें यह जानकारी सामने आई।

एक सामान्य आनुवंशिक हटाने के परिणामस्वरूप गुणसूत्र 22 पर एक छोटा डीएनए अनुक्रम अनुपस्थित होता है। जीन के मिटाने के वाहकों में हृदय के दोष और इम्यून की खराबी का कारण बनता है। ऐसे व्यक्तियों में से लगभग एक तिहाई किशोरावस्था या वयस्क होने पर मनोविकृति संबंधी विकार भी विकसित होते हैं। इस तरह के विकार में वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है क्योंकि व्यक्ति के मन को प्रभावित करने वाले लक्षण विकसित होते हैं। ऐसे में उनके विचार और धारणाएं बाधित होती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन समूह के लगभग 40 प्रतिशत लोगों में सिज़ोफ्रेनिया विकसित हुआ।

हाल में जर्नल बायोलजिकल साइकियाट्रीः काग्निटिव न्यूरोसाइंस एंड न्यूरोइमेजिंग में अध्ययन प्रकाशित किया गया। इसमें शोधकर्ताओं ने देखा कि बचपन से वयस्कता तक मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच बातचीत या "युग्मन" कैसे विकसित हुआ। उन्होंने बताया कि ये बातचीत हमारी संज्ञानात्मक (सोच) प्रक्रियाओं का आधार बनती है।

लेखक यह पता लगाना चाहते थे कि क्या जीन के हटाने वाले लोगों में कम कुशल युग्मन का मतलब मनोविकृति विकसित होने का खतरा बढ़ गया है। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग का उपयोग करते हुए टीम ने अध्ययन समूह में व्यक्तियों में 12 वर्षों तक मस्तिष्क के विकास का अवलोकन किया।

शोधकर्ताओं ने कहा कि मस्तिष्क के विकास के दौरान विकसित जीन को हटाने और विसंगतियों के बीच पाया गया मजबूत संबंध 'बीमारी (मनोविकृति) के लिए पूर्वानुमानित मार्करों की पहचान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिनेवा विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में प्रोफेसर और प्रमुख लेखक स्टीफन एलीज़ ने समझाया कि अगला कदम यह निर्धारित करना होगा कि ये युग्मन मस्तिष्क के एक व्यक्तिगत 'फिंगरप्रिंट' का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट रूप से जानना संभव हो सकेगा कि क्या उस व्यक्ति को मनोविकृति विकसित होने का खतरा दूसरे की तुलना में अधिक है या इसके विपरीत, इससे सुरक्षित है।

मस्तिष्क के तीन क्षेत्रों में लगातार पाई गई विसंगति

उन्होंने तीन मस्तिष्क क्षेत्रों में ललाट प्रांतस्था (फ्रंटल कोरटेक्स) समन्वित रूप चलने और भाषा के लिए जिम्मेदार है। सिंगुलेट प्रांतस्था (सिंगुलेट कोरटेक्स) दर्द और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। इसके अलावा टेम्पोरल प्रांतस्था (टेम्पोरल कोरटेक्स) स्मृति के साथ-साथ श्रवण और दृश्य जानकारी को व्यक्त करता है। इनके बीच बातचीत में "लगातार" विसंगति पाई। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह विसंगति विशेष रूप से किशोरावस्था में चिह्नित की गई है। जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रथम लेखक सिलास फोरर ने कहा कि जीन हटाने वाले रोगियों में बचपन से ही विकास संबंधी विसंगति थी, जिसमें मस्तिष्क में हाइपर और हाइपो युग्मन के क्षेत्र थे। हाइपर युग्मन के विकास के दौरान मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच अधिक से अधिक सुसंगत अंतःक्रियाओं को संदर्भित करता है। हाइपो युग्मन कम-से-कम सुसंगतता को संदर्भित करता है।

लैवेंडर के फूलों की बहार

चीन के आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में स्थित टोंगलियाओ के विशाल खेतों में इन दिनों लैवेंडर के फूलों की बहार आई हुई है। लैवेंडर के फूलों की सुगंध के साथ इनकी सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एएफपी

कर्ण से कीट होगा बोल्ड, शिवांगी बनेगी जल प्रहरी

कपिल पूनिया • जागरण

- गेहूं की डीबीडब्ल्यू 377 (कर्ण शिवांगी) और डीबीडब्ल्यू 359 (कर्ण बोल्ड) प्रजाति जारी
- तीन सिंचाई की पड़ेगी जरूरत, मध्य और दक्षिण भारत के लिए अनुकूल

भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल

करनाल : भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की दो नई प्रजाति जारी की हैं। इन्हें डीबीडब्ल्यू 359 (कर्ण शिवांगी) और डीबीडब्ल्यू 377 (कर्ण बोल्ड) नाम दिया गया है। दोनों प्रजातियों के पकने तक सामान्य की तुलना में कम पानी ही लगेगा। इन प्रजातियों को मुख्य रूप ये मध्य भारत और प्रायद्वीप के क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है।

डीबीडब्ल्यू 359 प्रजाति 115 दिन में तैयार होगी। इसका उत्पादन 41.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देगी। डीबीडब्ल्यू 377 प्रजाति 124 दिन में पकेगी। इसका उत्पादन 63.90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होगा। दोनों प्रजाति के बीज इसी वर्ष से किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। दोनों प्रजाति का गेहूं जिंक, आयरन और प्रोटीन से भरपूर है। दोनों प्रजाति से बने बिस्किट और रोटी की गुणवत्ता बेहतर होगी। विज्ञानी देश के किसानों को गेहूं एवं जौ के उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए निरंतर शोध कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले सीजन में गेहूं का उत्पादन 112.92 मिलियन टन पहुंचा, जो अब तक सर्वाधिक है। संस्थान की ओर से 114 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। गेहूं का रकबा घटने के कारण लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका।

मध्य और दक्षिण भारत के लिए अनुकूल, रोगों ने लड़ने में सक्षम : आइआइडब्ल्यूबीआर के विज्ञानी डा. अनुज कुमार ने बताया कि दोनों नई प्रजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश के झांसी, राजस्थान के कोटा और उयपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोआ और तमिलनाडु के लिए अनुकूल हैं। इस प्रजाति को केवल तीन ही सिंचाई पर्याप्त हैं, जबकि सामान्य तौर पर पांच सिंचाई की जरूरत होती है। उर्वरकों की अनुमोदित कम मात्रा में ही दोनों प्रजाति ने पैदावार में प्रथम स्थान पाया है। बांग्लादेश में किये गए मूल्यांकन में यह किस्म ब्लास्ट की बीमारी के प्रति अत्याधिक प्रतिरोधक है। इसके अलावा काला और भूरा रतुआ से भी यह किस्म खुद को बचाने में सक्षम है।

दुर्लभ जीन का म्यूटेशन बनता है मिर्गी का कारण

- आस्ट्रेलिया के फ्लोरी इंस्टीट्यूट आफ न्यूरोसाइंस एंड मेंटल हेल्थ में किया गया अध्ययन
- निर्बाध सोडियम आयन प्रवाह मस्तिष्क की न्यूरोनल संकेतों को बंद करने की क्षमता को बाधित करता है

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : मस्तिष्क कोशिकाओं में एक दुर्लभ आनुवंशिक म्यूटेशन सोडियम के 'निरंतर' प्रवाह का कारण बनता है, जिससे शिशुओं में मिर्गी होती है। एक अध्ययन के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज मिर्गी के रोगियों के इलाज में सोडियम चैनलों के कामकाज को संशोधित करने में सक्षम दवाओं के संश्लेषण द्वारा मदद कर सकती है।

मिर्गी एक मस्तिष्क विकार है, जिसमें व्यक्ति बार-बार अकारण दौरे या दौरे का अनुभव करने के लिए असुरक्षित होता है। मिर्गी के दौरे कई तरह के हो सकते है, हालांकि कई मामलों मिर्गी पीड़ित रोगी का शरीर ऐंठने लगता है, परन्तु हर मामलो में ऐसा नहीं होता। यह स्थिति गंभीर विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि मस्तिष्क कोशिकाओं (न्यूरान्स) के अंदर प्रोटीन, जिन्हें 'सोडियम चैनल' कहा जाता है, में एक तंत्र होता है, जो "खुद बंद होने वाले द्वार" की तरह काम करता है।

आस्ट्रेलिया के फ्लोरी इंस्टीट्यूट आफ न्यूरोसाइंस एंड मेंटल हेल्थ में बायोफिजिसिस्ट और अध्ययन के लेखक गेज़ा बेरेकी ने कहा कि स्वस्थ व्यक्तियों में यह सेलुलर द्वार कुछ समय के लिए खुलता है। फिर सोडियम आयनों (आवेशित सोडियम कणों) को न्यूरान्स में लगातार प्रवाहित होने से रोकने के लिए स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।

जर्नल ब्रेन में प्रकाशित टीम का शोध यह दिखाने वाला पहला शोध है कि सोडियम चैनलों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करके एससीएनटूए जीन में म्यूटेशन न्यूरान्स में निर्बाध सोडियम आयन प्रवाह का कारण बन सकता है, जिससे दौरे पड़ सकते हैं।

बेरेकी ने कहा कि यह मस्तिष्क की न्यूरोनल संकेतों को बंद करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे मस्तिष्क की उत्तेजना में समग्र वृद्धि होती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि एससीएनटूए एक बड़ा जीन है, जिसमें आनुवंशिक भिन्नता की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि जीन अनुक्रमण अधिक व्यापक होने के कारण अलग-अलग एससीएनटूए म्यूटेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। अध्ययन के लिए, लेखकों ने आस्ट्रेलिया और विदेश में मिर्गी के रोगियों के डाटा के साथ काम किया। उन्होंने म्यूटेशन से प्रभावित प्रोटीन के सेल नमूनों और कंप्यूटर माडल में न्यूरान्स के काम का विश्लेषण किया। बेरेकी ने कहा कि मिर्गी के इलाज के लिए निष्कर्षों का निहितार्थ हैं। बेरेकी ने कहा कि सोडियम चैनलों के कामकाज को संशोधित करने में सक्षम दवाएं प्रभावित व्यक्तियों के लिए अधिक प्रभावी व्यक्तिगत उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका में कमला इतिहास रचने को तैयार

राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति हैरिस का प्रत्याशी बनना लगभग तय

डेमोक्रेटिक पार्टी में उत्साह जगा, आठ करोड़ डालर का चंदा आया

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सोमवार को विलमिंगटन स्थित अपने प्रचार मुख्यालय में पहुंचीं। एपी

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आवश्यक समर्थन जुटा लिया है। उनकी उम्मीदवारी पर पार्टी के चार हजार आधिकारिक प्रतिनिधियों में से 2,538 ने समर्थन जताया है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एपी के सर्वे में सामने आई है। यह आंकड़ा उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक 1,976 प्रतिनिधियों के समर्थन से अधिक है। इतना ही नहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के चंदादाताओं ने भी कमला का नाम सामने आने के बाद उत्साह दिखाया है। उन्होंने महज 24 घंटों में 8.10 करोड़ डालर का चंदा पार्टी फंड में दिया है।

चेन्नई में पैदा हुईं श्यामला गोपालन की बेटी कमला हैरिस अब अमेरिका में गौरवान्वित करने वाली दास्तां लिखने की तैयारी में हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनने की औपचारिकता पूरी होने पर वह अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। यह औपचारिकता अगस्त में होने वाले पार्टी अधिवेशन में पूरी होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कमेटी के चेयरमैन जैमी हेरीसन ने बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा सात अगस्त को होगी। वैसे अभी तक शीर्ष पद की उम्मीदवारी के लिए पार्टी में किसी अन्य नेता का नाम नहीं उभरा है लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा चुप हैं। उन्हें छोड़कर डेमोक्रेटिक पार्टी के बाकी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है। नवंबर में होने वाले चुनाव में अगर वह रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को हराने में सफल होती हैं तो अमेरिका के 236 वर्षों के लोकतंत्र के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाली वह पहली महिला होंगी।

कमला की उम्मीदवारी मजबूत होती देख ट्रंप खेमे ने उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। उन्हें बाइडन की बर्बाद करने वाली नीतियों को आगे ले जाने वाला बताया है। देर न करते हुए कमला ने उनका करारा जवाब दिया है। कहा, वह विरोधियों की सभी तरह की साजिशों का पर्दाफाश करेंगी। निजी लाभ के लिए नियम तोड़ने वाले नेता का असली चेहरा वोटरों के सामने लाएंगी। वह डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को अच्छी तरह से पहचानती हैं। कमला ने कहा, उन्हें अपनी बेदाग छवि और शानदार रिकार्ड पर गर्व है। राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा उम्मीदवारी के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने के 28 घंटे बाद कमला का पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष यह पहला चुनावी भाषण था।

अमेरिका में सीक्रेट सर्विस की प्रमुख का इस्तीफा

- पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के मामले में हो रही थी आलोचना

किंबरली चीटल। रायटर

सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेते हुए छोड़ा पद

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका में राष्ट्रपति और पूर्ववर्तियों को सुरक्षा देने वाली एजेंसी सीक्रेट सर्विस की प्रमुख किंबरली चीटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के मामले में सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। इससे पहले सोमवार को ट्रंप की सुरक्षा पर संसदीय समिति ने किंबरली को कैपिटल हिल में तलब कर सवाल-जवाब किए थे और कड़ी फटकार लगाई थी।

पेनसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी सभा के दौरान 13 जुलाई को एक युवक ने असाल्ट राइफल से आठ फायर किए थे। इस फायरिंग में एक गोली ट्रंप के कान को घायल करते हुए निकल गई थी, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। घटना में सीक्रेट सर्विस के निशानेबाज ने कुछ ही मिनटों के भीतर हमलावर युवक को मार गिराया था। इस घटना को 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर हुई फायरिंग की घटना के बाद वीवीआइपी सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक माना गया। घटना के बाद सुरक्षा में चूक के लिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने किंबरली के इस्तीफे की मांग की थी। किंबरली 2022 से सीक्रेट सर्विस के निदेशक के पद पर कार्य कर रही थीं।

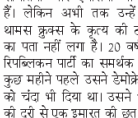

ट्रंप पर हमले के बाद घटना के सिलसिले में अमेरिकी संसद की कई समितियां और एजेंसियां जांच में जुटी हैं। लेकिन अभी तक उन्हें हमलावर थामस क्रुक्स के कृत्य की ठोस वजह का पता नहीं लगा है। 20 वर्षीय थामस रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक था लेकिन कुछ महीने पहले उसने डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा भी दिया था। उसने 140 मीटर की दूरी से एक इमारत की छत से ट्रंप पर गोलियां चलाई थीं।

कनाडा में हिंदू मंदिर को फिर बनाया गया निशाना

- एडमंटन में स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे
- भारतीय दूतावास ने की आरोपितों पर कार्रवाई कर जांच की मांग

प्रतीकात्मक

ओटावा, प्रेट्र: कनाडा में हिंदू मंदिर को फिर निशाना बनाया गया है। देश में एडमंटन शहर में सोमवार सुबह बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे पाए गए। वैंकूवर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने घटना की निंदा की है। उसने कनाडा की जिम्मेदार एजेंसियों से आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए घटना की जांच की मांग की है।

कनाडाई हिंदू चैंबर्स आफ कामर्स ने कहा है कि यह किसी ढांचे पर हमला नहीं है बल्कि हिंदुओं की भावनाओं पर हमला है। वहीं, भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने कनाडाई हिंदुओं के विरुद्ध चलाए जा रहे घृणित अभियान की निंदा की है। आर्य ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, पिछले कुछ वर्षों से ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र, ब्रिटिश कोलंबिया समेत कनाडा के विभिन्न स्थानों पर हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा के लिबरल सांसद आर्य ने कहा कि देश में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों को कनाडाई हिंदू समुदाय के विरुद्ध घृणा और हिंसा फैलाने की खुली छूट मिली हुई है। कहा, सिख फार जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पिछले वर्ष खुलेआम हिंदुओं को भारत जाने की बात की थी। सांसद रैंडी बाइसोनाल्ट ने कहा कि मंदिर की दीवारों पर घृणित नारे लिखे पाए गए हैं। कनाडा के किसी भी भाग में मंदिर या किसी पूजास्थल को नुकसान पहुंचाने और घृणा फैलाने को कोई स्थान नहीं है।

एस जयशंकर क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए जाएंगे टोक्यो

- विदेश मंत्री हिंद-प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम पर करेंगे विमर्श

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस जयशंकर चार देशों भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया व जापान के समूह क्वाड की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 28 जुलाई से तीन दिनी यात्रा पर टोक्यो जाएंगे। उनके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा और उनके आस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग 29 जुलाई को क्वाड बैठक में शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा के आमंत्रण पर जयशंकर 28 से 30 जुलाई तक जापान की यात्रा करेंगे। वह 29 जुलाई को टोक्यो में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। चारों विदेश मंत्री क्वाड पहल व कार्य समूहों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वह क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

बीजिंग में हमास, फतह समेत 14 फलस्तीनी समूहों में समझौता

अंतरिम राष्ट्रीय एकता सरकार के घोषणापत्र पर किए हस्ताक्षर

बीजिंग में फतह उपाध्यक्ष महमूद अल-अलौल (बाएं) तथा हमास के सदस्य मूसा अबु मरजुक (दाएं) के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी। एपी

बीजिंग, रायटर: गाजा में युद्धविराम की कोशिशों के बीच हमास, फतह समेत 14 फलस्तीनी प्रतिद्वंद्वी समूह एक साथ काम करने को सहमत हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, गाजा पट्टी में अंतरिम राष्ट्रीय एकता सरकार के लिए इन समूहों ने मतभेद समाप्त कर समझौता किया है। वहीं, इजरायल ने कहा है कि हम चरमपंथियों को गाजा से खदेड़ने में सफल होंगे।

चीन की राजधानी में 21-23 जुलाई के बीच चली वार्ता में 14 फलस्तीनी संगठन के पदाधिकारियों ने बीजिंग घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। ज्ञात हो, मिस्र व अन्य अरब देश गत 17 वर्षों से सत्ता के लिए लड़ रहे हमास व फतह समेत विभिन्न धड़ों के बीच समझौता कराने में विफल रहे थे। यह समझौता इस मायने में अहम है कि गाजा में युद्ध समाप्ति के बाद हमास द्वारा संचालित शासन कैसे काम करेगा। हमास के वरिष्ठ पदाधिकारी हुसैन बद्रान ने कहा, सबसे अहम तथ्य है कि फलस्तीनियों के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार पर सहमत होना। हमास गाजा पट्टी में शासन करता है और फलस्तीनी प्राधिकरण पर फतह का कब्जा है।

बंधकों के परिवार से बोले नेतन्याहू, समझौते के करीब: इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के स्वजन से कहा है कि उनकी रिहाई का समझौता होने वाला है। वहीं, गाजा में हमास लड़ाकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है।

जान-माल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई सेना : शेख हसीना

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश में हिंसक झड़पों को देखते हुए कर्फ्यू लगाने और सेना की तैनाती के अपने फैसले का प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए।

हसीना की टिप्पणी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अधिकांश कोटा खत्म करने के एक दिन बाद आई है। बांग्लादेश में विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग को लेकर छात्रों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया था, जो बाद में हिंसक हो गई। इसमें सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए हैं। शेख हसीना ने हिंसा के लिए मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी और उनकी छात्र शाखाओं को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सेना की तैनाती का समय रहते निर्णय लेने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। राजधानी समेत 57 जिलों में 27,000 सैन्यकर्मियों को तैनात किया गया है।

****

रूस ने यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर किए फिर हमले

- 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के घर की बत्ती गुल
- यूक्रेन ने भी रूस के बंदरगाह पर किए हमले, एक की मौत

कीव, रायटर: रूस ने उत्तरी यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं पर फिर हमले किए हैं। इससे पचास हजार से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि उसकी रक्षा प्रणाली ने रूस के आठ ड्रोन में से सात को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर, यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी क्रासनोदर क्षेत्र के कावकाज बंदरगाह के एक गोदाम में आग लग गई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई।

यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने टेलीग्राम प्लेटफार्म पर दिए बयान में कहा है कि करीब 25 हजार उपभोक्ताओं की बिजली बहाल हो गई है। सैन्य प्रशासन ने कहा कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। उधर, यूक्रेन के ड्रोन हमले में कावकाज बंदरगाह के एक अनाज गोदाम में आग लग गई।

दूसरी ओर, क्रेमलिन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ रूस की जब्त संपत्तियों से अर्जित ब्याज को चोरी से यूक्रेन को सैन्य मदद देने में प्रयोग कर रहा है। कहा कि जो भी इस निर्णय में शामिल पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रूस ने ब्रिटेन के 15 लोगों पर लगाया प्रतिबंध

यूक्रेन को लेकर रूस के विरुद्ध सार्वजनिक बयानबाजी करने को लेकर 15 ब्रिटिश मूल के लोगों पर देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने 15 लोगों की सूची जारी करते हुए कहा कि ये लोग ब्रिटिश सैन्य उद्योग कांप्लेक्स के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ या प्रकाशक जो मीडिया में रूस विरोधी बातें फैलाते हैं।

पाकिस्तान में ईसाइयों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने मंगलवार को ईसाई पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष कर दी। उम्र में यह वृद्धि 1872 में लागू कानून में संशोधन के बाद की गई है।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत ईसाई विवाह (संशोधन) अधिनियम 2024 को स्वीकृति दी है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह अधिनियम ईसाई विवाह अधिनियम 1872 की धारा 60 में संशोधन के बाद लागू किया गया है।

नए कानून के अंतर्गत ईसाई समुदाय में पुरुष और महिला दोनों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इससे पहले ईसाई पुरुष और महिला की उम्र क्रमशः 16 और 13 वर्ष निर्धारित थी। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने इस महीने के शुरू में ध्वनिमत से विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 करने की स्वीकृति दी थी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न ईसाई संगठनों ने ईसाइयों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का स्वागत किया है।